www.indiatodayhindi.in

राजस्थानः गुलदारों से गुलजार गलियारा

बिहारः दो डिप्टी सीएम बनाने के राज

प्रतिरक्षाः कब परवान चढ़ेगा मेक इन इंडिया

इंडिया टुडे

29 सितंबर, 2021
50 रुपए

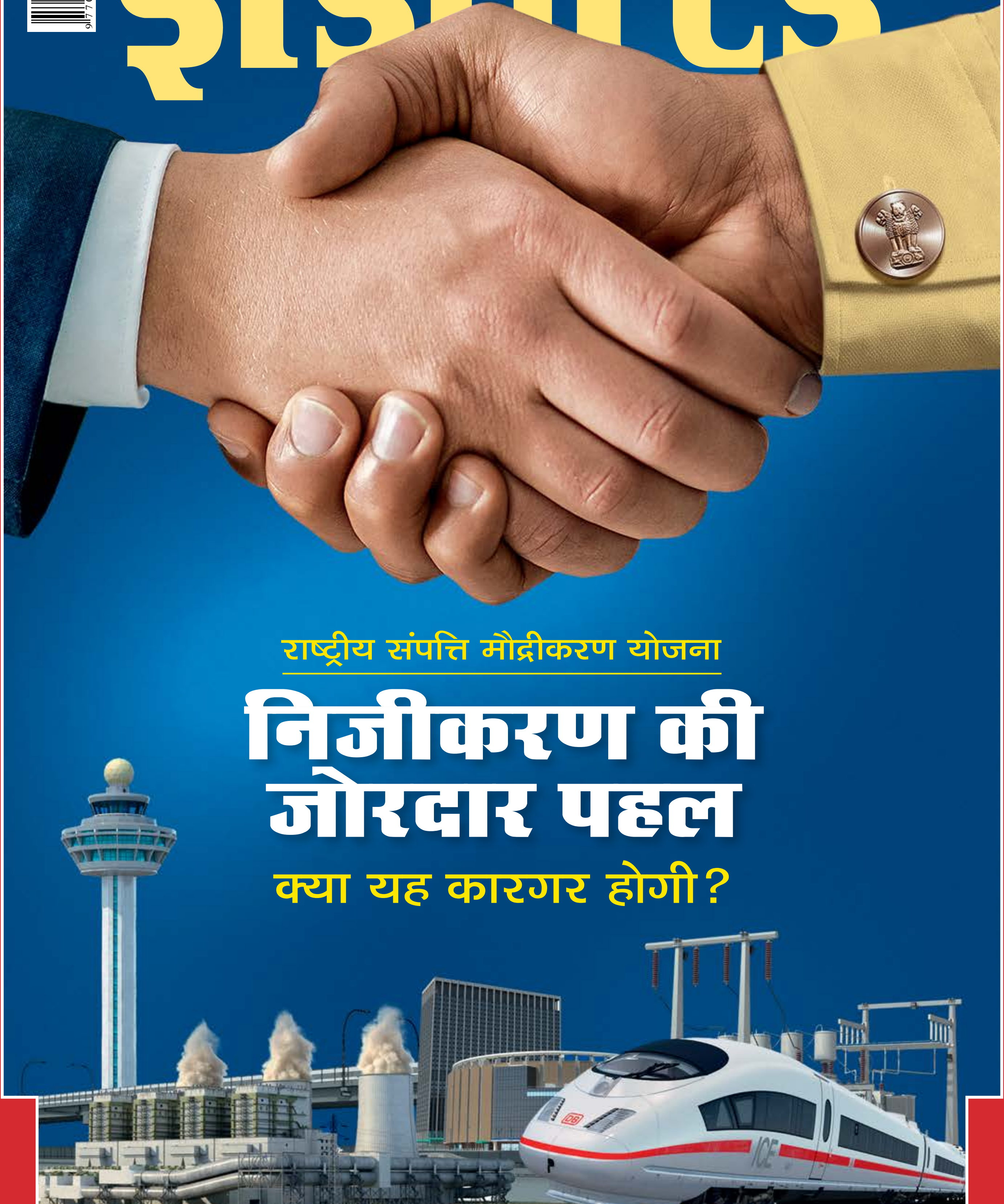

राष्ट्रीय संपत्ति मौद्रीकरण योजना

निजीकरण की जोरदार पहल

क्या यह कारगर होगी?

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

OC

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 66 (आवरण सहित)

VISIT…

LANZAROTE
Caliente.com

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

9:41

INDIA TODAY

LIVE

TOP NEWS VIDEOS PROGRAMMES

TOP STORIES

LOK SABHA 2019

Narendra Modi Live: By Congress-mukt India we will fulfil Gandhi's dream

PM Narendra Modi was speaking in Lok Sabha

only books magazine

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

प्रधान संपादक की कलम से

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की शुरुआत में दो सूत्रवाक्यों ने काफी आशाएं जगाई थीं. वे थे 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम राजकाज' और 'कारोबार में होना सरकार का कारोबार नहीं'. यह सुनकर मेरे कानों में शहद घुल जाता था. भारतीय राज्यसत्ता लंबे समय से अर्थव्यवस्था की 'कमांडिंग हाइट्स' या नियंत्रणकारी हिस्सों पर काबिज थी. कुछ तो नियंत्रणकारी भी नहीं थे, मसलन, होटल और एयरलाइंस. ज्यादातर नाकारा और सरकारी खजाने को खोखला करने वाले थे. दुर्भाग्यवश विपक्ष के 'सूट-बूट की सरकार' ताने ने पहले कार्यकाल के उन सूत्रवाक्यों पर विराम लगा दिया. हालांकि सरकार माल और सेवा कर (जीएसटी) और ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवाला संहिता (आइबीसी) सरीखे बहुत जरूरी सुधार लाई. इस साल 24 फरवरी को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को यह ऐलान करते सुनना उत्साहवर्धक था कि ''सरकार जब एक संपत्ति विशेष का मुद्रीकरण करती है, तो उसकी जगह देश का निजी क्षेत्र ले लेता है. निजी क्षेत्र निवेश के साथ बेहतरीन वैश्विक प्रथाएं भी लेकर आता है. यह सबसे अव्वल गुणवत्ता का मानवबल लाता है और प्रबंधन का कायापलट कर देता है. वह उस क्षेत्र का तेजी से विस्तार करता है और नौकरियों के नए अवसर रचता है.'' प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ध्यान दिया और इस साल के केंद्रीय बजट में विनिवेश की बात कही गई. सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान आज 'मुद्रीकरण' और 'विनिवेश' शब्दों को खुलकर प्रयोग करता है, जो पहले अभिशाप होता. विचारधारा बरतरफ, इस दिशा में सरकार की बड़ी कोशिश की अच्छी वजह भी है.

भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे साल आइसीयू में है. पिछले वित्त वर्ष में यह 7.3 फीसद संकुचित हुई, जो 1979-80 में जीडीपी के 5.2 फीसद सिकुड़ने के बाद पहला पूरे साल का संकुचन था. रही-सही उम्मीदों को इस अप्रैल में कोविड-19 महामारी की दूसरी जानलेवा लहर ने तहस-नहस कर दिया, जब चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था 1.6 फीसद की दर से बढ़ी. वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था अपनी सबसे तेज दर 20.15 फीसद से बढ़ी, लेकिन यह पिछले साल के निम्न आधार के कारण था.

इंडिया टुडे
बजट 2021
सुधारों की खुराक

17 फरवरी, 2021 का आवरण

इसी वित्तीय संकट के चलते सरकार ने अब संपत्ति मुद्रीकरण जैसे गैरमामूली उपायों का सहारा लिया है, जिसमें वह संसाधन उगाहने के लिए अपनी परिसंपत्तियां निजी क्षेत्र को लीज पर देगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का ऐलान किया, जिसके लिए सरकार ने 12 मंत्रालयों और महकमों से जुड़े 13 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें 20 परिसंपत्ति वर्ग हैं. निजी क्षेत्र सड़कों पर टोल वसूल सकता है, सरकार की बनाई पटरियों पर ट्रेन दौड़ा सकता है, रेलवे स्टेशन चला सकता है, बिजली उत्पादन और पारेषण लाइनों से राजस्व जमा कर सकता है, गोदाम और टेलीकॉम टावर संभाल सकता है और हवाई अड्डों का संचालन कर सकता है. सरकार का मनसूबा इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को लीज पर देकर अगले चार सालों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है. उसे उम्मीद है कि सड़कों (1.6 लाख करोड़ रु.), रेलवे (1.52 लाख करोड़ रु.), बिजली पारेषण (45,200 करोड़ रु.) और बिजली उत्पादन (39,832 करोड़ रु.) से बड़ी कमाई होगी.

इसमें से कुछ कमाई का इस्तेमाल सरकार अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की खातिर 111 लाख करोड़ रु. की राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सरीखी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए करेगी. उसे 2024 तक हर गांव में नल का जल पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रु. की जल जीवन मिशन सरीखी मौलिक सामाजिक योजनाओं के लिए भी धन चाहिए.

संपत्ति मुद्रीकरण सराहनीय विचार है, लेकिन हम पहले भी देख चुके हैं कि कमी नारों और विचारों की नहीं है; नाकामी उन पर अमल में है. अपने नारों को जमीन पर उतारने के मामले में सरकार का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. 2020-21 में सरकार 2.1 लाख करोड़ रु. के नियोजित विनिवेश लक्ष्य का बस दसवां हिस्सा ही जुटा सकी. वह भी तब जब शेयर बाजारों में तेजी थी. मार्च 2020 की 31 तारीख तक कुल जमा 70,820 करोड़ रु. के घाटे से दबे एयर इंडिया सरीखे भीतर से सड़ते पीएसयू बिके नहीं हैं. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी सरीखे दूसरे पीएसयू की अधर में लटकी बिक्री इरादे और अमल के बीच विशाल खाई का प्रमाण है.

सरकार को इस अभियान के पीछे अपने इरादों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए. यह महज इसलिए किया जा रहा है कि पैसों की किल्लत है, या वे दिल से मानते हैं कि देश के हित में यही सबसे अच्छा है? जवाब तय करेगा कि वे उस निकम्मी अफसरशाही पर पूरा जोर डालने के लिए कितनी सख्ती से तैयार हैं, जिसकी बुनियादी फितरत यथास्थिति की हिफाजत करना है, क्योंकि वे अपनी जागीर के बड़े हिस्से पर हुकूमत गंवा बैठेंगे. असल खेल बारीकियों में है. मुद्रीकरण की शर्तों को वे इतना सख्त बना सकते हैं कि यह बोली लगाने की खातिर किसी के लिए भी आकर्षक न रह जाए. राजस्व उगाहने के अलावा सरकार में यह विश्वास होना ही चाहिए कि निजी हाथों में सौंपे जा रहे संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा दक्षता से और देश के फायदे में होगा. विवाद तो खैर होंगे कि संपत्तियों का मूल्य निर्धारण कैसे किया गया है. विपक्ष सरकार को घर की बेशकीमती चीजें बेचने और कुछेक कुलीनों के आधिपत्य पैदा करने का आरोप भी लगाएगा. सरकार को विरोधों का डटकर मुकाबला करना और यह अफसाना भरोसेमंद ढंग से लोगों के गले उतारना होगा कि यह उपभोक्ता और देश के फायदे के लिए ही है.

हमारी आवरण कथा 'निजीकरण की जोरदार पहल' सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण नीति की पड़ताल करती है. इसे एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.जी. अरुण और डिप्टी एडिटर श्वेता पुंज ने लिखा है.

हालिया इतिहास में ऐसे काफी उदाहरण हैं जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पर सरकार-नियंत्रित कंपनियों का दबदबा आम तौर पर दरअसल मौत का शिकंजा होता है. चीन सरीखे कट्टरपंथी कम्युनिस्ट देश को अपनी अर्थव्यवस्था निजी उद्यमों के लिए खोलनी पड़ी, ताकि वह वृद्धि के रास्ते पर बढ़ सके. 1978 में यह कदम उठाने के बाद उनका जीडीपी सालाना 10 फीसद की औसत दर से बढ़ा. इसकी बदौलत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला गया. 1978 में चीन की प्रति व्यक्ति आय 156.4 डॉलर और भारत की 205.6 डॉलर थी. 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,900 डॉलर और चीन की 10,500 डॉलर थी. चीनी सुधारों के महान वास्तुशिल्पी देंग श्याओ पिंग का मशहूर कथन है: ''बिल्ली जब तक चूहे पकड़ती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह काली है या सफेद.''

प्रधानमंत्री को भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके आलोचक उनकी बिल्ली को किस रंग का कहेंगे. उन्हें बहुप्रतीक्षित सुधार की राह पर पक्के इरादे से आगे बढ़ना चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारे विनाशकारी सोशलिज्म दौर की आखिरी निशानियों से आजाद कर देना चाहिए.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादकः अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सनः कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टरः राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः मनोज शर्मा
एडिटरः अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटरः मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटरः शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटरः मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरोः, अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटरः नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टरः चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टरः असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटरः बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंटः यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चरः प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चरः सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफः अभिनव पुगला

एसोसिएट पब्लिशरः विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेडः सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजरः जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजरः मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजरः इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसरः विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजरः दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजरः विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजरः राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजरः पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

वर्षः 35; अंकः 44; 23-29 सितंबर 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोनः 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजेंः** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवाः** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोनः दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्सः (0120) 4078080. ई-मेलः wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालयः** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोनः 022-66063355 फैक्सः 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालयः** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोनः 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोनः 2212448, 226233, टेलेक्सः 0845-2217 INTO IN. फैक्सः 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालयः एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**

संपादकः राज चेंगप्पा

भीतर

सुर्खियां
आटोमोबाइल सेक्टरः शटर गिराकर चल दिए!
पेज 5

फुरसत
सिनेमाः तो क्या महामारी बदल देगी पूरा किस्सा
पेज 62

अर्थात्ः तेल की चौसर
पेज 31

सवाल-जवाब/काशीनाथ सिंहः बनारस में नहीं रहा बनारस
पेज 64

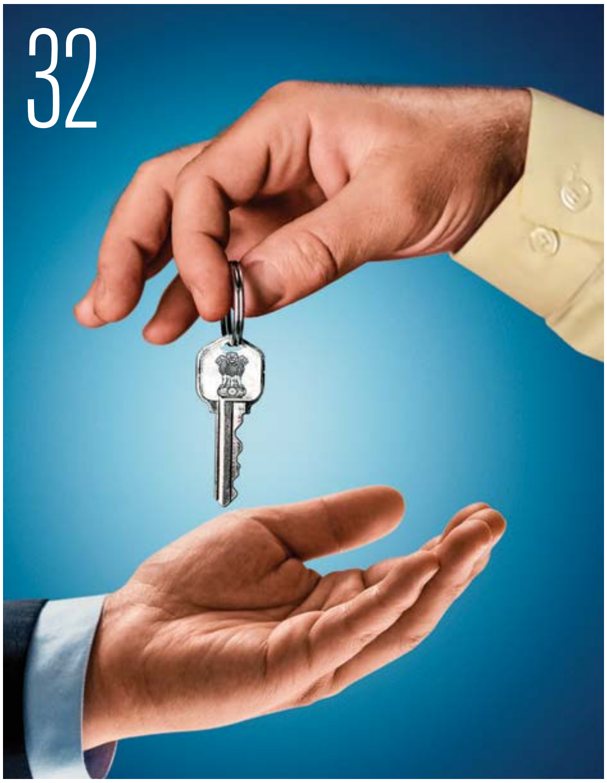
फोटो इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास; डिजिटल इमेजिंगः अमरजीत सिंह नागी

32

आवरण कथा

निजीकरण की जोरदार पहल

सरकारी संपत्तियों के मौद्रीकरण के जरिए अगले चार साल में 6 लाख करोड़ रुपए उगाहने की मोदी सरकार की योजना क्या कारगर हो पाएगी?

खास रपट

46 **क्या है भाजपा का गुजरात गेमप्लान**

भूपेंद्र पटेल क्या पाटीदार समुदाय को संतुष्ट कर भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष दूर कर पाएंगे?

सेहत

54 **दाने-दाने में है दम पर...**

फोर्टिफाइड चावल को राष्ट्रीय मानक बनाना सही है पर इसमें कई जोखिम भी छिपे हैं

आवरणः **नीलांजन दास**; डिजिटल इमेजिंगः **अमरजीत सिंह नागी**

भूल सुधार

'एलआईसीः द इंस्टीट्यूशन' शीर्षक से **इंडिया टुडे** के हिंदी संस्करण के 15 सितंबर 2021, के अंक में प्रकाशित भारतीय जीवन बीमा निगम के **एडवरटोरियल** में एलआईसी के एयूएम का आकार 38,04,610.01 करोड़ रु. पढ़ा जाना चाहिए, न कि 38,04,610.01 रु.

इंडिया टुडे
इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करेंः Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

पाठकों के लिए सूचनाः कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

सुर्खियां

पंजाब विधानसभा चुनावः वापसी के लिए बिछती सुखबीर की शतरंज
पेज 20

उत्तराखंडः अपने ही करा रहे फजीहत
पेज 22

पश्चिम बंगालः दीदी मतलब अब कारोबार
पेज 24

आफ्सपाः युद्ध या शांति?
पेज 26

only books magazine

Ford
SANAND VEHICLE ASSEMBLY AND ENGINE PLANT
ENTRANCE
GATE-3

< बंद होते दरवाजे
गुजरात के साणंद में स्थित फोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट

गेट्टी इमेजेज

ऑटोमोबाइल सेक्टर

शटर गिराकर चल दिए!

एम.जी. अरुण

अपने कामकाज के केवल 25 वर्षों में—किसी ऑटो निर्माता के लिए यह बहुत लंबा समय नहीं होता—अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है. ऐसा भी नहीं कि मॉडल टी, थंडरबर्ड और मस्टैंग जैसी कारों के इस प्रतिष्ठित निर्माता के लिए ये 25 साल आसान थे. फोर्ड को भारत में जहां आइकॉन, एंडेवर और ईकोस्पोर्ट जैसे मॉडलों में बड़ी सफलता मिली, वहीं मोंडेओ और फ्यूजन सरीखे मॉडलों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. कंपनी ने अपने कार्य-व्यापार में दो अरब डॉलर (करीब 14,700 करोड़ रुपए) से ज्यादा का घाटा दर्ज किया था और इसके वाहनों की मांग कमजोर थी. फोर्ड इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा के मुताबिक, कंपनी दीर्घकालिक लाभ का स्थायी रास्ता नहीं खोज पाई.

महामारी का हवाला देते हुए 2019 में महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के साथ साझा उद्यम को बंद करने से फोर्ड के लिए स्थिति और खराब हो गई. साझा उद्यम का लक्ष्य भारत में फोर्ड वाहनों के विकास, विपणन और वितरण के साथ-साथ कुछ फोर्ड और महिंद्रा उत्पादों को ऊंची विकास दर वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वितरित करना था. साझा उद्यम खत्म होने के साथ ही भारतीय बाजार में फोर्ड के जीवित रहने की संभावना धूमिल हो गई.

फोर्ड का कहना है कि वह 2021 की चौथी तिमाही तक अपने साणंद (गुजरात) संयंत्र को बंद कर देगी और 2022 तक चेन्नै संयंत्र में वाहन और इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगी. इस फैसले से देश भर में उसके 4,000 कर्मचारियों पर असर पड़ेगा. साणंद संयंत्र की सालाना क्षमता 2,40,000 वाहन उत्पादन की है और चेन्नै संयंत्र में 2,00,000 वाहन सालाना तैयार हो सकते हैं. खैर, फोर्ड भारत में आयात के जरिए कारें बेचती रहेगी. इस बारे में आए समाचारों के मुताबिक, इनमें मस्टैंग माक-ई,

मस्टैंग और रेंजर जैसे हाइ-एंड मॉडल होंगे. कंपनी मौजूदा ग्राहकों को सेवा देती रहेगी.

पिछले कुछेक वर्षों में तीन प्रमुख बहुराष्ट्रीय ऑटो कंपनियों की विदाई भारत के लिए शुभ संकेत नहीं. भारत, रूस और पश्चिमी यूरोप सहित कुछ क्षेत्रों में गैर-लाभकारी संचालन से बाहर निकलने का निर्णय लेने के बाद जनरल मोटर्स ने 2017 में देश छोड़ दिया था. टॉप-एंड मोटरसाइकिल निर्माता हार्ले डेविडसन ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों जैसे चुनिंदा बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी 'रीवायर' रणनीति के तहत 2020 में भारत छोड़ा. हार्ले को अप्रैल-जून 2020 में 9.6 करोड़ डॉलर (करीब 710 करोड़ रुपए) का घाटा हुआ था. यह बड़ा नुक्सान भले न हो पर स्पष्ट रूप से कंपनी को निकट भविष्य में अच्छी मांग की उम्मीद न थी. महामारी ने ऑटो कंपनियों के लिए चुनौती और बढ़ा दी है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें रीटेल दुकानें बंद रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

जापानी और कोरियाई कार निर्माताओं के प्रभुत्व के कारण इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय बाजार विशेष रूप से कठिन रहा है. मारुति सुजुकी की बाजार में करीब 48 फीसद और हुंडई इंडिया की करीब 17 फीसद हिस्सेदारी है. उदारीकरण के बाद के दौर में बढ़ते मध्यम वर्ग और भारतीय परिवारों में ऑटोमोबाइल की कम मौजूदगी के कारण व्यापार संभावनाओं से प्रेरित होकर कई बहुराष्ट्रीय ऑटो कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया था. उनके सामने मारुति सुजुकी (पहले मारुति उद्योग) की सफलता की कहानी थी जिसके पास शुरुआती चरण में बाजार का 80 प्रतिशत तक हिस्सा था.

जीएम, फोर्ड और टोयोटा सरीखी जिन कंपनियों ने भारत में आधार बनाया उन्होंने भविष्य की संभावित मांग का दोहन करने के लिए व्यापक क्षमता स्थापित की. पर बाजार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा, खासकर बड़ी कारों के लिए. ऑटो इंटेलिजेंस फर्म, जाटो डायनेमिक्स इंडिया के अध्यक्ष और निदेशक रवि भाटिया कहते हैं, ''भारत जैसे महंगी पूंजी वाले देश में ऑटो जैसे ऊंचे पूंजीगत व्यय वाले उद्योग के लिए ज्यादा क्षमता गले में पड़े मरे सांप जैसी हो सकती है.'' मसलन, 1980 के दशक में मारुति के निर्धारित मूल्य—गैर-वातानुकूलित मॉडल के लिए 47,000 रुपए और वातानुकूलित मॉडल के लिए 70,000 रुपए—से बेहतर विकल्प दे पाना मुश्किल था. मारुति ने अच्छे वितरण और सेवा नेटवर्क के साथ उचित गुणवत्ता की सस्ती कार पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया. इसके अलावा, चार मीटर से छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क में कटौती से जापानी और कोरियाई कंपनियों को और मदद मिली. भाटिया बताते हैं कि अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को चार मीटर से कम की कार बनाना मुश्किल लगा क्योंकि उनकी विशेषज्ञता बड़े वाहनों में थी.

दूसरी ओर मांग भी नीची होती गई. पिछले पांच वर्षों में भारत में ऑटो बिक्री सिर्फ 1.5 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर दर्ज कर रही है, जिससे भारतीय बाजार में भारी निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं. सरकार ने एक स्क्रैपेज नीति का ऐलान किया है जिसमें पंजीकरण समाप्त होने पर कार का निरीक्षण करवाना अनिवार्य है. पर यह स्पष्ट नहीं कि इसका ऑटोमोबाइल की बिक्री पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा या नहीं.

अगस्त में ऑटो क्षेत्र की थोक बिक्री में पिछले साल की तुलना में 12 फीसद की गिरावट आई. उद्योग ने इसके लिए उत्पादन पर बुरा असर डालने वाले सेमी कंडक्टरों की कमी और वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वाहनों की लागत में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया. इसके साथ ही ईंधन की बढ़ती लागत के कारण भी वाहनों की मांग पर दबाव बना रहने का अंदेशा है जिसके चलते भारत जैसे 'लागत-सचेत' बाजार में कंपनियों को अपनी रणनीतियां बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

महामारी के दौरान राजस्व पर असर पड़ने के कारण दुनिया भर में ऑटो कंपनियां बड़े सुधार के दौर से गुजर रही हैं. इसके अलावा, दुनिया का रुझान एसीईएस (आटोनॉमस, कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक ऐंड शेयर्ड) वाहनों की ओर बढ़ रहा है. फर्मों को इसमें भारी निवेश करने की जरूरत है. पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, 2020 तक पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच गई थी जो 2019 की तुलना में 43 प्रतिशत ज्यादा है. 2020 में पंजीकृत हुए सभी नए विद्युतचालित वाहनों में से दो-तिहाई बैटरी कारें थीं. 45 लाख इलेक्ट्रिक कारों के साथ चीन इस क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि 2020 में सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि यूरोप में हुई जहां इनकी संख्या 32 लाख तक पहुंच गई.

कुछ ऑटो कंपनियों ने भारत छोड़ा है तो कुछ अन्य ने प्रवेश किया है. चीनी वाहन निर्माता एसएआइसी मोटर की सहायक कंपनी एमजी मोटर इंडिया ने 2019 में भारत में परिचालन शुरू किया. इस साल के शुरू में अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने भारतीय इकाई पंजीकृत कराई. उम्मीद की जा रही है कि यहां पर्याप्त मांग दिखने पर वह यहां एक मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करेगी. ■

अलविदा हिंदुस्तान

फोर्ड मोटर कं.

छोड़ा: 2021 में

कर्मचारी: 4,000

क्षमता: साणंद (गुजरात) संयंत्र में 2,40,000 कारें प्रति वर्ष; चेन्नै में 2,00,000 कारें प्रति वर्ष

छोड़ने की वजह: उसे चलाने पर 14,700 करोड़ रु. से ज्यादा का घाटा हो चुका था; मांग बहुत कम थी; महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के साथ साझा उपक्रम भी चल न पाया

हार्ले डेविडसन

छोड़ा: 2020

कर्मचारी: 70

क्षमता: बावल (हरियाणा) संयंत्र में 12,000 बाइक प्रति वर्ष

छोड़ने की वजह: अपनी रीवायर रणनीति के तहत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में चुनिंदा बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए

जनरल मोटर्स

छोड़ा: 2017 में

कर्मचारी: 5,000

क्षमता: हलोल (गुजरात) और तालेगांव दभाड़े (महाराष्ट्र) संयंत्रों में कुल 2,25,000 वाहन बनाने की

छोड़ने की वजह: भारत, रूस और पश्चिमी यूरोप समेत कुछ गैर-लाभकारी संचालन वाले क्षेत्रों में निवेश न करने के फैसले की वजह से

योगी के साढ़े चार साल, उत्तर प्रदेश बना बेमिसाल

ड्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण, यूपी ने थामी कोरोना की लहर

योगी का प्रयास है सच्चा, कोविड से बचेगा हर बच्चा

जीना हुआ आसान, अपराधी हुए परेशान, काम भी, लगाम भी

डबल इंजन की सरकार का दिखा असर, बेघर को घर, बिजली एवं नल

योगी ने दिया सम्मान, खुशहाल हुए किसान

ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण यूपी ने थामी कोरोना की लहर

कोविड की लड़ाई को व्यवस्थित बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'ट्रेस-टेस्ट-ट्रीट' की नीति अपना कर व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया.

मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना की लहर का मुकाबला करने के लिए हर जिले में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल (आइसीसीसी) सेंटर स्थापित कराया.

कोविड जांच के लिए कुल 400 से अधिक टेस्टिंग लैब काम कर रही हैं. इनमें 258 सरकारी और 132 निजी क्षेत्र की लैब हैं. रिकार्ड 7.5 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है.

देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद यूपी ने औसतन रोजाना 1.50 लाख आरटी-पीसीआर परीक्षण करके दूसरे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है.

माइक्रो मैनेजमेंट का ''यूपी माडल'' कोविड के खिलाफ जंग में कारगर हुआ. जिलों को सेक्टर में बांटा गया और फिर प्रत्येक सेक्टर हेतु प्रभारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए.

73,000 से अधिक निगरानी समितियों और 8800 से अधिक रैपिड रिस्पॉन्स करने वाली प्रशिक्षित टीमों के सहयोग से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए निर्णायक प्रयास हुआ.

कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश में एल-1, एल-2, एल-3 के कोविड अस्पतालों में करीब एक लाख 80 हजार बेड की व्यवस्था की गई.

नीति आयोग ने कोरोना मरीजों का पता लगाने, संक्रमण फैलने और रोकने के लिए उन्हें होम आइसोलेट करने के लिए चलाए गए योगी सरकार के ट्रिपल टी (ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट) महाभियान के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम की सराहना की है.

ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण, यूपी ने थामी कोरोना की लहर

> “योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का बहुत बड़ा प्रमाण है ‘सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन’ अभियान. प्रदेश में कोरोना के 08 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं. एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के नाम है.’’
>
> —नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

राजकीय क्षेत्र के **25** और निजी क्षेत्र के कुल **33** मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा विश्वविद्यालय और संस्थान में **18,181** बेड्स की व्यवस्था की गई.

प्रदेश की **97** चीनी मिलों और अन्य इकाइयों ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तीन करोड़ लीटर से अधिक सैनिटाइजर का उत्पादन किया है.

सैनेटाइजेशन अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में **86,700** और शहरी क्षेत्रों में **82,000** कर्मचारी लगाए गए हैं. इस अभियान की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री ने की.

कोरोना की पहली लहर की तरह दूसरी लहर के दौरान भी प्रवासियों और दैनिक यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम ने **10** हजार से अधिक बसें लगाईं.

सीएम योगी के निर्देश पर कोरोना काल में आयुष विभाग करीब **25** लाख लोगों तक पहुंचा, **20** लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क आयुष किट वितरित की गई.

योगी सरकार एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में कार्य कर रही है. प्रदेश के **59** जिलों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज क्रियाशील है तथा **16** ऐसे जिले जहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां थ्री-पी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है. लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारम्भ हो गया है.

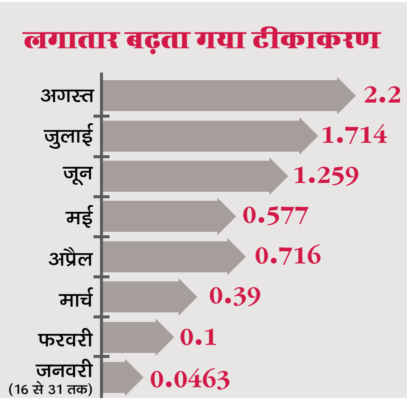

लगाए गए टीके (करोड़ में)

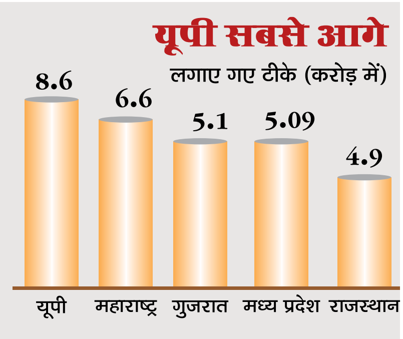

30 दिन में टीकाकरण की रफ्तार में 31 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई उत्तर प्रदेश में.

आंकड़े 11 सितंबर तक

योगी का प्रयास है सच्चा कोविड से बचेगा हर बच्चा

बाल सेवाः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल (मार्च 2020 से) में अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरूआत की. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से यूपी के 4000 से अधिक बच्चों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है.

पीकू प्रोजेक्टः इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभाने वाले पीकू (पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट) प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए लागू किया गया है. सभी मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के लिए 100 बेड का आईसीयू तैयार रखने का निर्देश दिया है.

आइसीयू सुविधाः मुख्यमंत्री ने हर मंडल मुख्यालय पर 100-100 बेड का और जिला अस्पतालों में 25-25 बिस्तरों की क्षमता वाले आईसीयू बनाने को कहा है. कोरोना की संभावित लहर से बच्चों को बचाने के लिए मेडिकल किट का वितरण हो रहा है.

जीनोम सिक्वेंसिंगः कोविड डेल्टा वेरियंट की जांच के लिए सरकार ने बीएचयू, केजीएमयू, सीडीआरआइ, राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में जीनोम परीक्षण की सुविधा दी है. जल्द ही नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआइ) में भी जीनोम सिक्वेंसिंग शुरू होगी.

टेस्टिंग पर जोरः कुल कोरोना टेस्टिंग की 70 फीसदी टेस्टिंग गांवों में की जा रहा है. यूपी के 75 जिलों के 97, 941 गांवों में स्क्रीनिंग टीम पहुंची है. 18 करोड़ लोगों की डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग की जा चुकी है. 8,124 रैपिड रेस्पांस टीम गांवों में मुस्तैद है.

लाइफ सपोर्ट एंबुलेंसः कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस में 24 घंटे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशयन (ईएमटी) और पायलटों की 23 हजार से अधिक लोगों की टीम दिन-रात काम में जुटी हैं.

पीएसए प्लांटः डीआरडीओ और एनएचएआई मिलकर यूपी के सभी जिलों में 127 प्रेशर स्विंग एडपर्शन (पीएसए) ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं. इससे अस्पतालों के कुल 6,225 बेड को 5650 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की उपलब्धता मिलेगी.

योगी का प्रयास है सच्चा, कोविड से बचेगा हर बच्चा

> “जहां बीमार-वहां उपचार के सिद्धांत पर माइक्रोकंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार शहरों और गांवों में घर-घर दवाएं वितरित कर रही है, यह बहुत अच्छी पहल है.”
>
> –नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ऑक्सीजन प्लांट: कोरोना महामारी से पहले प्रदेश में 25 ऑक्सीजन प्लांट थे. इसे बढ़ाकर 555 कर दिया गया है. इनमें से 409 प्लांट अब तक तैयार कर लिए गए हैं. प्रदेश में मांग से काफी अधिक एक हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता है.

हेल्थ एटीएम: प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयासों के क्रम में गांवों, छोटे कस्बों और महानगरीय क्षेत्रों में ‘‘हेल्थ एटीएम’’ की स्थापना की जाएगी. इनमें अत्याधुनिक मशीनों से लोगों के स्वास्थ्य की अलग-अलग पैरामीटर पर जांच की जाएगी.

गोल्डन कार्ड: आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अन्त्योदय कार्डधारकों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. किडनी ट्रांसप्लाण्ट, कार्नियल ट्रांसप्लाण्ट एवं म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) के उपचार के पैकेज को योजना में सम्मिलित किया जाएगा.

स्वच्छ पेयजल: प्रदेश वासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने समस्त नगर निगमों में कुल 11589 में से 629 नलकूपों की मरम्मत कर ठीक करा लिया है. जबकि 428 में से 71 नलकूलों को रीबोर करके चालू कराया गया है.

पोषण पर ध्यान: सीएम योगी ने ‘राष्ट्रीय पोषण माह, 2021’ की शुरुआत की है. पांच वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एक जुलाई से 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान चला रहा है.

आपदा विशेषज्ञ: योगी सरकार ने प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए 62 जिलों में संविदा के आधार पर आपदा विशेषज्ञ रखने का फैसला किया है. इन्हें हर माह 50,000 रुपए मानदेय मिलेगा. पहले से 13 जिलों में काम कर रहे विशेषज्ञों को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है.

हाइटेक ग्रामीण अस्पताल: प्रदेश के 3022 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं. पैथोलाजी और रेडियोलाजी विभाग में नए उपकरणों की स्थापना के साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है.

जीना हुआ आसान, अपराधी हुए परेशान, काम भी, लगाम भी

मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता संभालने के बाद प्रदेश के जोन में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी और रेंज में पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) स्तर के अधिकारियों की तैनाती शुरू की.

पिछले साढ़े चार वर्षों में 150 से अधिक अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं. 3400 से अधिक अपराधी घायल हुए. गैंगेस्टर एक्ट में 44,759 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 630 अभियुक्त रासुका में निरुद्ध हुए हैं.

पुलिस ने जिले स्तर पर सक्रिय 1800 आपराधिक माफिया को चिह्नित किया है और इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है, ताकि जिले स्तर पर भी कानून व्यवस्था बनी रहे.

प्रदेश में सक्रिय 382 आपराधिक माफिया की हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है और 274 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. 300 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस निरस्त भी किए गए हैं.

राजस्व विभाग के मुताबिक वर्ष 2017 से 15 अगस्त, 2021 तक करीब 62423.89 हेक्टेयर (1,54,249 एकड़) यानि करीब 624 वर्ग किमी से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है.

राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा है और 22,992 राजस्व वाद, 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4407 एफआईआर कराया है.

प्रदेश में 41 भूमाफिया की संपत्ति कुर्क की गई है. दो पर रासुका, 170 आरोपियों पर गैंगेस्टर और 399 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

लखनऊ में जेल मुख्यालय के कमांड सेंटर की एक दीवार पर 12 टीवी स्क्रीन लगाकर एक वीडियो वाल बनाई गई है. इस वीडियो वॉल को 48 स्क्रीन में तब्दील किया गया है.

यूपी की सभी जेलें ऑनलाइन हो चुकी हैं. पूरे प्रदेश की जेलों में कुल मिलाकर 2750 कैमरे लगाए गए हैं. कैमरों की लाइव फीड कमांड सेंटर के वीडियो वॉल पर आती है.

प्रदेश में 124 खनन माफिया को चिह्नित कर 843 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 80 को गिरफ्तार किया गया है. 74 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाले गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की गई है.

वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2020 में बदलाव

- 70.10% की कमी डकैती में.
- 69.30% की कमी लूट में.
- 29.10% की कमी हत्या में.
- 33.00% की कमी बलवा में.
- 100% की कमी रोड होल्डअप में.
- 41.51% की कमी अपहरण में.
- 11.60% की कमी दहेज मृत्यु में.
- 52.00% की कमी बलात्कार में.
- मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकारों में लूट का पर्याय बने खनन को सरकार की आय का बड़ा स्रोत बना दिया है. सरकार को सवा चार साल में 12 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है.

माफिया पर कार्रवाई से बढ़ी खनन की कमाई

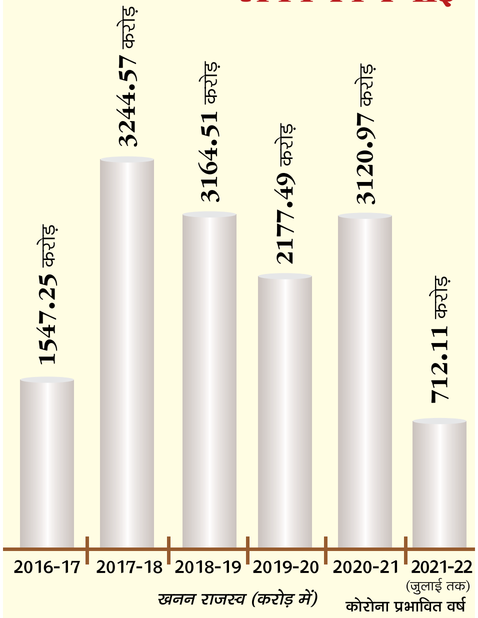

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ ने 21 अगस्त को रक्षा बंधन की पूर्व संध्या पर "मिशन शक्ति" अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की. इस अवसर पर 3 महिला पीएसी वाहिनियों का शिलान्यास हुआ.

मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत के मौके पर पहली बार 10,000 से अधिक महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई.

मिशन शक्ति अभियान में 8.50 करोड़ पुरुषों, महिलाओं और अन्य को जागरूक किया गया है. साथ ही सवा पांच लाख से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है.

एंटी रोमियो स्क्वायड द्वारा 98,55,867 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 9948 अभियोग पंजीकृत कर 14,958 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है.

वीमेन पावर लाइन पर मिली शिकायतों में से 99.6 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया है और महिला हेल्पलाइन 181 के तहत महिलाओं की सहायता की गई है.

महिला अपराधों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और महिलाओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के लिए हर जिले में डिप्टी एसपी स्तर की महिला नोडल अधिकारी की तैनाती की है.

पॉक्सो एक्ट में त्वरित न्याय दिलाने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय क्रियाशील हैं.

योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर समेत 13 शहरों को महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है.

जीना हुआ आसान, अपराधी हुए परेशान, काम भी, लगाम भी

को
र्मित आवासों
रण
मुख्यमंत्री
आवास योजना - ग्रामीण
योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0
ANI

डबल इंजन की सरकार का दिखा असर, बेघर को घर, बिजली एवं नल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी गरीबों की सच्ची हितैषी है. यह जोड़ी सदैव वंचितों, शोषितों और गरीबों की समस्याओं और सरोकारों का निरन्तर समाधान करने के लिए तत्पर है. गरीबों को आवास मुहैय्या कराने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की संकल्पना की और इसे 01 अप्रैल, 2016 से लागू किया. केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ 20 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूपी के जनपद आगरा से किया गया. मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना को नई ऊंचाइयां दी है. मुख्यमंत्री योगी ने 1 सितंबर को अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 6637.72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 5.51 लाख आवासों के लाभार्थियों को मकान की चाभी दी. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) तथा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पिछले चार वर्षों में लगभग 42 लाख आवास स्वीकृत किये गये. जबकि इसके सापेक्ष पूर्व के 30 वर्षो में कुल 53 लाख आवास बने. इससे पता चलता है कि पूर्व की सरकारों ने गरीबों की आवासीय समस्याओं के समाधान पर पूरा ध्यान नहीं दिया. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने इस योजना से यूपी के गरीबों, किसानों, महिलाओं, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य वर्गों को जोड़ा और लाभान्वित किया. आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के विकास के एजेण्डे का लाभ गरीबों को बिना भेदभाव के मिल रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, शौचालय निर्माण, निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना इत्यादि का भी लाभ दिया जा रहा है.

पूरे हो रहे गरीब परिवारों के सपने

प्रधानमंत्री आवास योजना में 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण.

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 1,08,495 आवासों का निर्माण.

मुसहर, वनटांगिया वर्ग व कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को मुफ्त आवास.

वनटांगिया गांवों को राजस्व गांवों का दर्जा, बुनियादी सेवाओं का विकास.

वरासत अभियान के तहत जमीन से जुड़े 13 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण.

30000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल योजना क्रियान्वित.

गरीबों के लिए अत्याधुनिक टाउनशिप

बाबा गोकर्णनाथ ग्रामीण आवासीय परिसर

''शानदार तोरण द्वार, चहारदीवारी के बीच करीने से बने मकान, चमचमाती सड़कें, सार्वजनिक पार्क, पूरे परिसर को रोशन करतीं स्ट्रीट लाइट, गोशाला, घर-घर शुद्ध पेयजल, हर घर बिजली, हर घर प्रदूषण मुक्त गैस सिलिंडर, हर परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा...और भी बहुत कुछ....'' इन शब्दों को एक साथ जोड़कर पढ़े तो जेहन में जो तस्वीर बनती है उसे ''लंदनपुर'' कहते हैं. ...और यह लदंनपुर किसी परीकथा का कोई अंजान शहर नहीं, यह लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी ब्लॉक में विकसित ''बाबा गोकर्णनाथ ग्रामीण टाउनशिप'' है. योगी सरकार में जिला लखीमपुर खीरी के लंदनपुर ग्रंट गांव में पीएम आवास योजना को केंद्र एवं राज्य सरकार की 30 अन्य योजनाओं का लाभ देते हुए एक मॉडल तैयार किया गया है. इसमें अनुसूचित जाति एवं भूमिहीन 26 अत्यंत गरीब परिवारों के लिए टाउनशिप विकसित की गई जिसमें सारी सुविधाएं हैं. यहां पर 10 विभागों की 30 योजनाओं का कन्वर्जेंस करते हुए हर घर बिजली, गैस कनेक्शन, पार्क, लाइट, गोशाला, गोवंश, सबका बंदोबस्त हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभिनव मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं.

लंदनपुर ग्रांट टाउनशिप की खूबियां

सभी परिवारों को उनके गांव में आवासीय भूमि का पट्टा.

टाउनशिप के लिए शासन से कोई अतिरिक्त ग्रांट नहीं ली गई.

पीएम आवास ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत आवास के लिए मुफ्त आवंटन.

हर घर में टैप वाटर व पानी की टंकी से घरों में जलापूर्ति.

हर घर में बिजली का कनेक्शन, अलग से ट्रांसफॉर्मर.

26 व्यक्तिगत शौचालय, 26 कम्पोस्ट पिट.

गोवंश सहभागिता के तहत सभी को गोवंश प्रदान किया गया.

सार्वजनिक पार्क, मनरेगा से ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक.

आजीविका मिशन के तहत महिलाओं का समूह, ऑफिस एवं स्टोर.

किसान भाइयों से
संवाद
योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
स्त, 2021 | समय :
बजे | स्थान : 5, कालि

योगी ने दिया सम्मान खुशहाल हुए किसान

“किसान अन्नदाता हैं और समाज के भाग्य विधाता हैं’’...यह विश्वास रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर परिस्थिति में किसानों के साथ है. योगी सरकारी किसानों के हितों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. किसानों के लिए खेत से खलिहान तथा बीज से बाजार तक चक्रीय श्रृंखला बनायी जा रही है. प्रदेश में किसानों के कल्याण एवं आय को दोगुनी करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जन-धन योजना द्वारा किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ते हुए डीबीटी के माध्यम से किसानों को धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है. एमएसपी को बढ़ाते हुए रिकॉर्ड खाद्यान्न की खरीद सरकार द्वारा की गई है तथा खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया है. वर्ष 2016-17 में 06 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया था. वहीं कोरोना संक्रमण के बावजूद इस वर्ष 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है. वर्ष 2016 में 16 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि विगत 01 वर्ष में 66 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद प्रदेश सरकार द्वारा की गई.

किसानों को रिकार्ड भुगतान

योगी सरकार ने वर्ष 2010 से लम्बित पड़े गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए बेहतर रणनीति बनाकर कार्य करते हुए 01 लाख 43 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है. गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान कराने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं. विगत डेढ़ वर्षों से देश और दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपी की चीनी मिलें सुचारु रूप से चलती रहीं तथा गन्ना किसान गन्ना बेचते रहे. रमाला, मुण्डेरवा व पिपराइच में नई चीनी मिलों की स्थापना की गई. खाण्डसारी उद्योग में लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त किया गया है. योगी सरकार ने तय किया है कि पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से तथा पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें नवम्बर के पहले सप्ताह से प्रारम्भ हो जाएंगी. गन्ना किसानों को एसएमएस पर्ची व्यवस्था उपलब्ध करायी गई तथा घटतौली को न्यूनतम स्तर पर लाया जा चुका है. प्रदेश में विगत 04 वर्षों में गन्ने की फसल के क्षेत्रफल में 08 लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी हुई है.

‘एस्क्रो एकाउंट’ का सहारा

योगी सरकार की ओर से गन्ना मूल्य का समय से भुगतान कराने की पहल ने किसानों के चेहरों पर खुशियां लौटाई हैं. सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार ने वर्ष 2017 से गन्ना मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश में एस्क्रो एकाउंट (अस्थाई अनुबंधित खाता) की व्यवस्था की. इस नई व्यवस्था से कृषकों को चीनी मिलों से गन्ना मूल्य मद की धनराशि मिलने में पारदर्शिता आई. अब गन्ना मूल्य का खाता मिल प्रतिनिधि, जिला गन्ना अधिकारी और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाने लगा है. पूर्व की सरकारों में चीनी के विक्रय मूल्य का 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान दिया जाता था वहीं 2017 के बाद से योगी सरकार ने गन्ना कृषकों को चीनी के साथ चीनी मिल के अन्य उत्पाद जैसे शीरा, खोई के विक्रय मूल्य का 85

योगी ने दिया सम्मान, खुशहाल हुए किसान

प्रतिशत मूल्य भी दिया है. इतना ही नहीं ऐसी चीनी मिलें जो सीधे गन्ने के रस से एथलॉन बना रही हैं उन मिलों में उत्पादित होने वाले एथनॉल के मूल्य का 55 प्रतिशत और सीधे गन्ने के रस से उत्पादित होने वाले एथनॉल के मूल्य का 80 प्रतिशत अंश गन्ना मूल्य भुगतान के लिए टैग किया है. मिलों द्वारा सैनेटाइजर उत्पादन हेतु उपयोग होने वाले एथनॉल के विक्रय मूल्य का 65 प्रतिशत धन भी गन्ना मूल्य भुगतान के लिए टैग दिया गया है जिससे किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में परेशानी आना खत्म हो गई है.

छोटे किसानों को बड़ा फायदा

योगी सरकार ड्रिप सिंचाई के जरिए किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है. प्रदेश में पहली बार वर्ष 2021-22 में 30 हजार हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. ड्रिप सिंचाई योजना के लिए प्रदेश के 2566 किसानों का चयन किया गया है. ड्रिप सिंचाई के जरिए सिंचाई जल के उपयोग में 50 से 60 प्रतिशत पानी की बचत होगी. इस तकनीक के प्रयोग से भूगर्भ जल के दोहन में काफी कमी आएगी. योजना का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा. इस योजना से छोटे गन्ना किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा. इस योजना से बीपीएल कार्ड धारक, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसान लाभान्वित होंगे. जल संसाधनों के बेहतरीन मैनेजमेंट से किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी. प्रदेश में गन्ना कृषकों को मजबूती देने के लिए योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203 जारी किया गया है. इतना ही नहीं गन्ना किसान सर्वे, सट्टा, कैलेंडर, पर्ची आदि की समस्या के लिए टोल-फ्री नम्बर 1800-103-5823 पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर उसका समाधान पा रहे हैं. सरकार की ओर से की गई इस पहल से अब तक 122125 शिकायतों में से 117926 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है.

कमाल कर रहे किसान

बाराबंकी की धरती पर चीन और अमेरिका में सुपर फ्रूट मानी जाने वाली चिया सीड को उगाने वाले किसान हरिश्चन्द्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ से उत्साहित होकर बाराबंकी के अमसेरुवा गांव में ड्रैगन फ्रूट उगाकर सूबे के किसानों को एक नई राह दिखाई है.

अन्नदाता का रखा ख्याल

36 हजार करोड़ रुपये से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण मोचन किया गया.

प्रदेश में पहली बार 'उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति 2020' लागू की गई है.

यूपी में 291 ई-नाम मंडी की स्थापना से 87 लाख किसान और 34 हजार व्यवसायी जुड़े.

किसानों को धान पर 250 व गेहूं के बीज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल विशेष अनुदान दिया जाएगा.

कृषि निवेशों पर देय 2151.30 करोड़ रुपये की अनुदान राशि किसानों के खाते में भेजी गई.

पहली बार प्रदेश में 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त हुए, मंडी शुल्क 1 प्रतिशत घटाया गया.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 2613 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की गई है.

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा इसका लाभ पट्टेदारों/बटाइदारों को भी दिया गया है.

गोवंश आश्रित स्थलों में 5,86,793 गोवंश संरक्षित, प्रति गोवंश 900 रुपये प्रतिमाह की सहायता.

46 वर्षों से लंबित बाण सागर सिंचाई परियोजना के अवरोध दूर कर योजना पूरी कराई गई.

पिछले तीन सालों में 300 करोड़ रुपये कृषि विज्ञान केंद्रों व अन्य कृषि संस्थाओं को मिले.

कोरोना काल में राज्य से 2000 कुंतल आम का निर्यात हुआ. दशहरी आम की गुणवत्ता बढ़ेगी.

जिलावार फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए ''एक जिला एक कृषि उत्पाद'' योजना लागू होगी.

गोरखपुर में तैयार हो रहा विश्व के सबसे लंबे प्रिलिंग टावर वाला खाद कारखाना

उद्योगों को लगे पंख

- यूपी में उद्योगों की राह आसान करने में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभिनव प्रयोगों ने प्रदेश में औद्योगिकीकरण की एक नई राह खोली है.
- उत्तर प्रदेश में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई) की संख्या **89.99** लाख है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है.
- प्रदेश सरकार ने कुल **200** करोड़ रुपये से अधिक की लागत से **40** कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना करने की योजना बनाई है.
- योगी सरकार ने 18 अगस्त,2021 को ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधि नियम-**2020**'' को मंजूरी दी है.
- इन्वेस्टर्स समिट में **4.68** लाख करोड़ रुपये के निवेश के एम. ओ. यू. हस्ताक्षरित हुए. लगभग **3** लाख करोड़ रुपये के निवेश की **371** परियोजनाएं क्रियान्वित.
- औद्योगिक विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में **40** विदेशी निवेशकों ने **56,000** करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रदेश सरकार को दिए हैं.
- राज्य में जापान की सात, कनाडा की दो, जर्मनी की चार, हांगकांग की एक, सिंगापुर की दो, यूके की तीन, यूएस की पांच तथा कोरिया की चार कंपनियां निवेश कर रही हैं.
- मथुरा, चित्रकूट, उन्नाव, गाजियाबाद समेत **15** जिलों में करीब **922** छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं और वे जल्द काम करना शुरू कर देंगी.
- प्रदेश में **40** हजार करोड़ रुपये की लागत से तीन इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है.

> ''ओडीओपी योजना उत्तर प्रदेश की कला और अद्वितीय हस्तशिल्प के उत्थान में मदद करेगी और कई कुशल कारीगरों को रोजगार प्रदान करेगी. मुझे उम्मीद है कि यह एमएसएमई सेक्टर सर्वांगीण विकास को साकार कर सकता है और दुनिया भर में राज्य की कला को ले जा सकता है.''
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

निवेश के लिए यूपी बना सबका पसंदीदा

ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की. उच्चायुक्त ने कहा कि ब्रिटेन और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं. इसके तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ाया जा सकता है. 'एक जनपद, एक उत्पाद योजना' के तहत डिजाइनिंग, पैकेजिंग और टेक्निकल सपोर्ट के क्षेत्रों में ब्रिटेन यूपी का सहयोग कर सकता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नीदरलैंड के राजदूत मार्टेन वैन डेनबर्ग ने 31 अगस्त को मुलाकात की. नीदरलैंड यूपी के डेयरी क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने को इच्छुक है. भेंट के दौरान राजदूत ने कहा कि यूपी के किसानों को आधुनिक डेयरी तकनीक में पारंगत बनाने के लिए नीदरलैंड द्वारा यूपी में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जा सकता है

राजस्थान

घर में ही दो-दो हाथ करती भाजपा

रोहित परिहार

दोनों फोटोः पुरुषोत्तम दिवाकर

असहमति
गुलाब चंद कटारिया (बाएं) और कैलाशचंद्र मेघवाल

मजबूत नेता की कमी की वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पिछले कुछ समय से अंदरूनी असंतोष से जूझ रही है. हाल की एक घटना में राज्य में अनुसूचित जाति के शीर्ष नेता 87 वर्षीय कैलाशचंद्र मेघवाल ने विपक्ष के नेता और आरएसएस के पसंदीदा 76 वर्षीय गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ धावा बोल दिया. मेघवाल विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री रह चुके हैं. कटारिया और मेघवाल दोनों उदयपुर से हैं और अपने राजनैतिक करियर के ज्यादातर वक्त उनमें असहमति रही है. लेकिन मेघवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर उनकी शिकायत की और उन्हें हटाने का भी सुझाव दे डाला. इस कारण आलाकमान को राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह को मामला शांत कराने के लिए नियुक्त करना पड़ा.

हालांकि अरुण सिंह ने मेघवाल को शांत करा दिया पर मेघवाल के उठाए मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं. मेघवाल की मुख्य आपत्ति हाल में कटारिया के विवादित बयान देने और भाजपा के वोट बैंक को नुक्सान होने को लेकर थी. उनके मुताबिक, हाल में कटारिया ने कहा कि अगर भाजपा न होती तो भगवान राम समंदर में पड़े होते. इसे पहले उन्होंने कहा था कि भाजपा न होती तो बेचारा महाराणा प्रताप जंगलों में रोता फिरता. ऐसे कुछ बयानों से भाजपा को वाकई नुक्सान हुआ है. इस साल अप्रैल में राजसमंद विधानसभा उपचुनाव वह मुश्किल से जीत सकी जबकि यह सीट उसकी सबसे सुरक्षित सीटों में हुआ करती थी.

मेघवाल का पत्र विस्फोट 9 सितंबर को विधानसभा का सत्र शुरू होने से दो दिन पहले हुआ और इसने जयपुर जिला परिषद में क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस की दलबदलू रमा देवी को जिला प्रमुख के तौर पर जिताने की खुशी को काफूर कर दिया. उससे कुछ रोज पहले एक अज्ञात-से समूह ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर दफ्तर खोल दिया.

अपनी बहू निहारिका की देखभाल में व्यस्त राजे राज्य की राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं. इस साल के शुरू से ही निहारिका गंभीर रूप से बीमार हैं. हालांकि राजे के आलोचक मेघवाल के पत्र जैसे मामलों के लिए उन पर उंगली उठाते हैं लेकिन राज्य में उनकी अनुपस्थिति में अच्छा नेतृत्व प्रदान करने में नाकाम रहने के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं. इसके अलावा, राज्य का मौजूदा भाजपा नेतृत्व अपनी साफ छवि पेश करने में नाकाम रहा है. हाल में राजे विरोधी गुट और आरएसएस के प्रमुख नेता की पसंद दंपति राजाराम गुर्जर और उनकी पत्नी सौम्या का विवाद सामने आ गया. सौम्या को ज्यादातर प्रमुख नेताओं की मर्जी के खिलाफ जयपुर ग्रेटर का मेयर नियुक्त कर दिया गया. राजाराम कूड़ा जमा नहीं करने की वजह से लटके पैसे जारी करने के लिए कथित तौर पर 20 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में जेल में बंद हैं जबकि उनकी पत्नी सौम्या को निलंबित कर दिया गया है.

ग्रामीण इलाकों में हुए हालिया चुनावों से पता चला कि कांग्रेस के वोट शेयर में भाजपा के मुकाबले दो फीसद इजाफा हुआ जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान यह अंतर 0.5 फीसद था और राज्य में कांग्रेस को भाजपा से महज 1.5 लाख ज्यादा वोट मिले थे.

फिर भी लगता है कि राजे उन्हें किनारे लगाने पर आमादा मौजूदा नेतृत्व और पार्टी के अपने पुराने समर्थकों के बीच खाई कम करने की कोशिश कर रही हैं. उनके वफादार, विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ समझौते के लिए मेघवाल के साथ भाजपा दफ्तर में अरुण सिंह से मिलने गए. उनके एक अन्य सहयोगी प्रताप सिंह सिंघवी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपने घर चाय पर बुलाया. पूनिया की छवि राजे विरोधी नेता के रूप में उभरी है.

पूनिया आरएसएस और पार्टी की पसंद हैं लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे सबको साथ लेकर नहीं चल पाते. गहलोत सरकार पर भाजपा के ज्यादातर हमलों का खास असर नहीं हो रहा है. न तो भाजपा अपने शासन के दौरान की उपलब्धियों को बता पा रही है क्योंकि वह राजे के शासन काल का गुणगान नहीं करना चाहती और न ही गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को उठाना चाहती है क्योंकि बयान देने वाले नेताओं का सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों के साथ करीब का रिश्ता है. भाजपा को लगता है कि चाहे जो हो, 2023 में विधानसभा चुनाव वही जीतेगी. जाहिर है, यह खामख्याली है. गहलोत सत्ता में वापसी के लिए अपने सहयोगियों और थिंक टैंक से गंभीर विचार विमर्श कर रहे हैं.

लिहाजा, भाजपा को अशोक गहलोत और सचिन पायलट से निबटने के लिए किसी मजबूत नेता की जरूरत है. भाजपा के पास राजे को राज्य की राजनीति में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. लेकिन राजे को भी अपने साथ और नेताओं को जोड़ना होगा, केवल उन्हीं के भरोसे नहीं बैठना होगा जो फिलहाल उनके साथ हैं. भाजपा में कलह से जाहिर है कि राज्य इकाई में सबको साथ लेकर चलने वाले मजबूत नेताओं की जरूरत है.■

> **भाजपा के पास राजे को राज्य की राजनीति में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन राजे को भी अपने साथ और नेताओं को जोड़ना होगा**

पंथ की राह!
सुखबीर बादल 30 अगस्त को माछीवाड़ा (लुधियाना) के गुरुद्वारा चरण कंवल साहिब में

एएनआइ

पंजाब विधानसभा चुनाव

वापसी के लिए बिछती सुखबीर की शतरंज

अनिलेश एस. महाजन

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्य के 117 में से 100 विधानसभा क्षेत्रों का अपना राज्यव्यापी दौरा 'गल पंजाब दी' 3 सितंबर को रोक दिया. 18 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से बार-बार व्यवधान पड़ रहा था. बीते 2 सितंबर को मोगा में ऐसी ही एक घटना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए. यात्रा को बीच में रोकते हुए बादल ने राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भूंडर, पूर्व लोकसभा सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा और शिअद प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा की तीन-सदस्यीय समिति की घोषणा कर दी जो पार्टी को लेकर किसानों के बीच 'गलतफहमियों' को दूर करेगी.

बत्तीस आंदोलनकारी किसान संघों के समन्वित मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 सितंबर को चेतावनी दी कि कृषि कानून रद्द होने तक वे राज्य में हर पार्टी की राजनैतिक गतिविधियों का विरोध करेंगे. 2022 के शुरू में होने वाले पंजाब विधानसभा के चुनावों में ये विवादास्पद कानून भावनात्मक मुद्दा होंगे. पिछले सितंबर में भाजपा का साथ छोड़ने के बाद से अकाली नेता बादल इस मुद्दे पर ग्रामीण किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रामीण किसान अकाली दल से छिटक गए पंथिक मतदाताओं का वह बड़ा हिस्सा हैं जिनका रुख सिख धार्मिक संगठनों के संकेतों से तय होता है.

पंथिक मतदाताओं की अकाली दल से नाराजगी की कई वजहें हैं. मसलन, 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं की जांच में कथित गड़बड़ी और मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध रेत खनन और भ्रष्टाचार में अकाली नेताओं की कथित संलिप्तता. 2017 के विधानसभा चुनाव में शिअद के पंथिक वोटर आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस की ओर गए थे. उग्रवाद के दौर के बाद से विधानसभा में सिर्फ 15 सीटें (अभी 14) हासिल कर पाना पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था.

पंथिक मतदाता लगभग 72 विधानसभा सीटों पर परिणाम तय करते हैं और बादल अपनी पार्टी के मुख्य पंथिक एजेंडे से भटक जाने की धारणा दूर करने को कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इस क्रम में सबसे पहले शिअद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बारे में अपना रुख पलटा. सन् 1973 में अकालियों के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, जिसमें राज्यों को शक्तियों के हस्तांतरण का आह्वान किया गया था, के बावजूद पार्टी ने संसद में इसके पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद शिअद ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से दूरी बना ली और मुसलमानों को अपने दायरे में लाने की कोशिश की. अकाली परंपराओं की ओर लौटने का भी प्रयास किया गया है. मसलन, पार्टी की बैठकें पांच सितारा होटलों से गुरुद्वारों में स्थानांतरित हो गई हैं.

जब तक पंथिक वोट बैंक वापस नहीं

मिल जाता, शिअद के सत्ता में लौटने की संभावना कम है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के 170 सदस्यीय शासी निकाय के लिए अरसे से लंबित चुनावों का होना मतदाताओं के इस हिस्से पर पकड़ का एक अच्छा संकेत होता. फिर भी अगस्त में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के चुनाव में मिली जीत ने उसमें कुछ उम्मीद जगाई है. पार्टी ने वहां 46 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की.

तीन दशकों में पहली बार ऐसा होगा कि शिरोमणि अकाली दल सुखबीर के पिता और पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल की नामौजूदगी में पंजाब का चुनाव लड़ेगी. 93 वर्षीय शिअद संरक्षक सक्रिय राजनीति से हट चुके हैं. सुखबीर ने यह नहीं बताया है कि सीनियर बादल चुनाव लड़ेंगे या नहीं अथवा मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा कौन होगा. चुनाव से पहले शिअद को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी सुखबीर पर है, जिन्होंने 64 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए इस काम की शुरुआत की है. इस पर पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष कुमार का कहना है कि ''इससे शिअद उम्मीदवारों को अपने अभियान और संसाधनों की योजना बनाने का समय मिलेगा और बागियों को पार्टी के बाहर अवसर तलाशने का.''

दलित वोटों पर नजरें गड़ाए बादल ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठजोड़ किया है और उसे 20 सीटों की पेशकश की है. बसपा 2017 में लड़ी सभी 111 सीटों पर हार गई थी और कुल वोटों में उसका हिस्सा 1.6 प्रतिशत था. शिअद को उम्मीद है कि इस गठबंधन से उसे ग्रामीण दोआबा और माझा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में रविदासी और रामदासी सिखों के बीच बसपा के आधार का लाभ मिलेगा. 2017 के विधानसभा और 2019 के आम चुनावों में दोनों दलित समुदायों ने कांग्रेस का समर्थन किया था. हालांकि, स्वतंत्र विश्लेषकों को इस पर संदेह है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोधका कहते हैं, ''अतीत में बसपा पंजाब में सहयोगियों को अपना वोट हस्तांतरित करने में विफल रही है. 2022 के चुनाव इससे अलग नहीं होंगे.''

बादल ने ऐलान किया है कि शिअद सरकार में दो उपमुख्यमंत्री होंगे—एक दलित और एक हिंदू. पंजाब की तीन करोड़ आबादी में करीब 32 फीसद दलित हैं. इनमें मजहबी सिख (सिख धर्म अपनाने वाले दलित) शामिल हैं. पंजाब में अधिकांश कृषि भूमि पर नियंत्रण रखने वाले जाट सिखों के साथ तनाव के कारण शिअद के मजहबी सिख समर्थकों में असंतोष पैदा हो रहा है. यहां केवल 3.5 प्रतिशत निजी खेत दलितों के हैं.

जंग पंजाब दी

विधानसभा की स्थिति

कुल सीटें 117

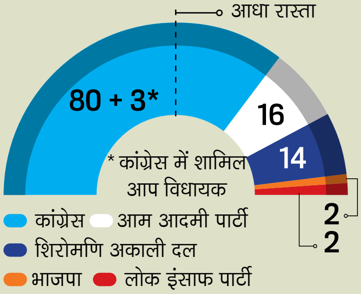

जातियों/समुदायों का जाल

मालवा (69 सीटें)
जाट सिख, हिंदू (सवर्ण), मजहबी सिख, बाजीगर, राय सिख, राजपूत सिख, वाल्मीकि

दोआबा (23 सीटें)
जाट सिख, रामदासी, रविदासी, वाल्मीकि, हिंदू (सवर्ण), सिख (सवर्ण), मजहबी सिख, सैनी, गुर्जर

मांझा (25 सीटें)
हिंदू (सवर्ण), राजपूत, आर्य, महाश, सैनी, मजहबी सिख, वाल्मीकि, जाट सिख

वोटों का रुझान

2017 विधानसभा चुनाव (% में)

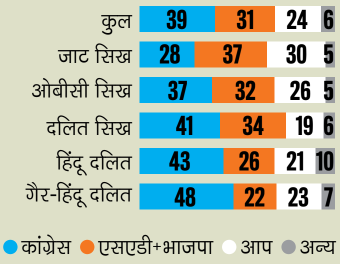

स्रोतः सीएसडीएस

ग्राफिकः अजित राय

1961 में पारित पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट ने गांवों में सामान्य कृषि भूमि का 33 प्रतिशत अनुसूचित जातियों को पट्टे पर देने के लिए आरक्षित किया था. लेकिन जाट सिख कथित तौर पर एवजी लोगों के जरिए ऐसी जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं. भाजपा ने कहा है कि वह सुनिश्चित करेगी कि गांवों की अतिरिक्त भूमि भूमिहीन दलित किसानों को मिले. पार्टी ने किसी दलित को मुख्यमंत्री चुनने की प्रतिबद्धता भी जताई है. इस तरह के आश्वासन शिअद की चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं.

सहयोगी के रूप में भाजपा की अनुपस्थिति शहरी इलाकों और हिंदू गढ़ों में शिअद को जरूर चुभेगी. पंजाब में 45 शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में उच्च जाति के हिंदू बड़े पैमाने पर कांग्रेस और भाजपा समर्थक हैं. गठबंधन में रहते हुए इन क्षेत्रों में भाजपा के वोटों के हस्तांतरण से शिअद उम्मीदवारों को फायदा होता था. अलगाव के बाद बादल धार्मिक हस्तियों और भाजपा के पूर्व नेताओं अनिल जोशी और आर.के. गुप्ता तथा कांग्रेस के हंसराज जोसन आदि से संपर्क करते हुए हिंदू समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. मालवा इलाके में वे अपनी ही पार्टी के हिंदू नेताओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं.

जोशी और गुप्ता के शिअद में शामिल होने से बसपा से मनमुटाव हो गया था. बादल ने एकतरफा रूप से दोनों को क्रमशः अमृतसर उत्तर और सुजानपुर से अकाली दल का उम्मीदवार घोषित किया था. जाहिरा तौर पर दोनों सीटों का वादा बसपा को किया गया था. बदले में बादल ने सहयोगी दल को शाम चौरासी और कपूरथला की सीटें दी हैं.

शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए बादल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठकें की हैं और उनके लिए अलग से घोषणापत्र जारी किया है. किसानों की हड़ताल का असर शहरी इलाकों पर भी पड़ा है. कुछ कॉर्पोरेट घराने कानून-व्यवस्था की समस्या का हवाला देते हुए बाहर निकल गए हैं. ऐसी बदहालियों के लिए बादल अमरिंदर सिंह सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं. वे सत्तारूढ़ कांग्रेस पर घोटालों और राज्य को बिजली संकट में धकेलने का भी आरोप लगाते हैं.

कह नहीं सकते कि अकाली दल के लिए बादल के प्रयासों का नतीजा क्या निकलेगा. 10 सितंबर को वे फतेहगढ़ साहिब जिले में कांग्रेस के गढ़ अमलोह से अपने 'गल पंजाब दी' दौरे को फिर से शुरू करने की योजना पर आगे नहीं बढ़ सके. शिअद नेताओं को उम्मीद है कि देर-सबेर किसान संघ शांत हो जाएंगे और उनके कार्यक्रम रोकना बंद कर देंगे. फिलहाल, बादल का राज्य का 100 दिवसीय दौरा पूरा होना दूर की बात है. अगले साल चुनाव की राह भी कम कठिन नहीं. ■

संजय नेगी

उत्तराखंड

अपने ही करा रहे फजीहत

अखिलेश पांडे

उत्तराखंड में भाजपा आलाकमान किसी भी तरह दोबारा सत्ता में आने की जी तोड़ कोशिश में लगा है. उसने इसी धुन में चार महीने में एक-एक करके राज्य के तीन मुख्यमंत्री बदल डाले. अब भाजपा आलाकमान निर्दलीय और मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाकर चुनाव जीतने की नई बिसात बिछा रहा है. इसी के तहत पार्टी ने चुनाव प्रभारी के रूप में इस तरह की नाराजगी से निबटने की जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी बनाकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और सरदार आर.पी. सिंह को भी उत्तराखंड में सिख और बंगाली समुदायों को साधने के लिए भेजा है. अब तक एक निर्दलीय और एक कांग्रेस के विधायक को भाजपा में लाकर पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जुटी भीड़ की हवा निकालने की कोशिश की है. लेकिन, आलाकमान की इस जीतोड़ मेहनत पर भाजपा के मंत्री और विधायक ही पानी फेरते दिख रहे हैं.

दरअसल, कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि ढैंचा बीज मामले में वे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात मान लेते तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर मुकदमा दर्ज हो जाता, और वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते. उनके अनुसार, हरीश रावत ने बतौर मुख्यमंत्री एम्स में भर्ती रहने के दौरान ढैंचा बीज मामले की फाइल मंगवाई थी. लेकिन हरक सिंह ने उस फाइल पर त्रिवेंद्र के पक्ष में दो पेज का नोट लिखा था, जिससे हरीश रावत कुछ कर नहीं पाए. हरक सिंह ने कहा कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का हमेशा साथ दिया, पर हरीश रावत को समझना बहुत मुश्किल है, हरीश रावत आज त्रिवेंद्र की तारीफ कर रहे हैं.

असल में हरीश रावत भाजपा में आग लगाने के लिए समय-समय पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बतौर मुख्यमंत्री तारीफ करते रहे हैं. उनकी तारीफ का असल मकसद त्रिवेंद्र के कार्यकाल में दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए गए कांग्रेस के उन बागी नेताओं के जख्मों पर नमक छिड़कना होता है जो कि भाजपा सरकार में मंत्री तो बन गए, लेकिन प्रचंड बहुमत के चलते बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने उनको कोई लिफ्ट नहीं दी थी. कांग्रेस से 2016 और 2017 में बगावत कर ये नेता तब हरीश रावत के लिए मुसीबत बन गए थे. इसी के चलते हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करते हुए इनके जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश करते हैं.

इसी तारीफ के चलते भाजपा सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने एक इंटरव्यू में एक तीर से दो निशाने साधे हैं. एक तरफ उन्होंने प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के कृषि मंत्री के कार्यकाल में हुए ढैंचा बीज घोटाले के जिन्न को फिर से बोतल से बाहर निकालते हुए कहा है कि हरीश अपने मुख्यमंत्रित्व काल में त्रिवेंद्र सिंह को जेल भेजना चाहते थे. वहीं, हरक सिंह यह भी कह दिया कि इस फाइल में उन दिनों बतौर कृषि मंत्री उन्होंने दो पेज का सकारात्मक नोट लिखकर त्रिवेंद्र सिंह को जेल जाने से बचा दिया था. साथ ही, ढैंचा बीज प्रकरण की चर्चा करके हरक सिंह ने त्रिवेंद्र सिंह को असहज भी कर दिया है.

अमित शाह

बाएं: देहरादून के धरमपुर विधानसभा से भाजपा विधायक के घर के बाहर धरना देने आई क्षेत्र की जनता के बीच स्वयं धरने पर बैठ गए चमोली
ऊपर: उत्तरकाशी के पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार भाजपा की सदस्यता लेते हुए

हरक सिंह के इस खुलासे पर जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सफाई देते यह कहकर प्रकारांतर में हरक सिंह पर निशाना साध रहे हैं कि उत्तराखंड में ढैंचा ढैंचा गधा करता है. वहीं हरीश रावत भी कहने लगे हैं कि रावतों की क्रॉस फायरिंग में उन्हें न घसीटा जाए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने यहां ऐसे बहुत से लोग इकट्ठा कर रखे हैं, जो एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं. अपनी सफाई में उन्होंने कहा, ''मैं उस वक्त एम्स में भर्ती था. जिंदगी और मौत से जूझ रहा था. इतना समय नहीं था कि मैं इन चीजों पर विचार कर पाता कि किसको जेल भेजना है और किसको नहीं. जब मैं स्वस्थ्य हो गया तो मैं फाइल का अध्ययन कर पाया कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्री और सचिव पर भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता है.''

हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने हरक सिंह को उनके बयानों पर आलाकमान की नाराजगी के बारे में बता दिया लेकिन उनके तेवर नरम नहीं हुए. हरक सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस से बगावत की थी. यह संकेत है कि वे एक बार फिर से जोखिम लेने के मूड में हैं.

इस बयान के सार्वजनिक होते ही उत्तराखंड में अपना जनाधार खड़ा करने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी बीच में कूद पड़ी. आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि हरक सिंह रावत के बयान से जाहिर हो चुका है कि कैसे कांग्रेस-भाजपा की अंदरखाने एक-दूसरे से मैच फिक्सिंग है और कैसे हरक सिंह ने मंत्री रहते हुए ढैंचा बीज घोटाले में त्रिवेंद्र सिंह पर कार्रवाई को रोका था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पर खुलकर विरोध इसी मिलीभगत के कारण नहीं कर पाती. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब भाजपा भी उसके भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध लेती है. आम आदमी पार्टी इस प्रकरण को भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनावी मुद्दा बनाने की जुगत में जुट गई है.

उधर, देहरादून के धरमपुर से भाजपा विधायक और पूर्व मेयर रहे विनोद चमोली ने भी पार्टी की किरकिरी करा दी. दरअसल, 12 सितंबर को उनकी विधानसभा में पड़ने वाले ऋषि विहार के नाले को उनके कार्यकाल के साढ़े चार साल पूरे होने के बाद भी अंडर ग्राउंड न किए जा सकने पर उस क्षेत्र के लोगों ने उनके घर के बाहर धरना देना शुरू कर दिया. आगामी चुनाव के सिर पर होने और मौके की नजाकत को भांपते हुए खुद विनोद चमोली अपने ही विरोध में चल रहे धरने में बैठकर यह जताने लगे मानो उस मांग के पक्षधर वे खुद हों और मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं, किसी और की हो. इससे भाजपा की खूब किरकिरी हुई.

इसके दो दिन पहले राज्य के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी ऐसा पैंतरा अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनाते दिखे. 10 सितंबर की रात को वे अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग के खिलाफ गांव वालों की ओर से दिए जा रहे धरने में बैठ गए. इससे प्रदेश की धामी सरकार की किरकिरी होना स्वाभाविक थी. इसको लेकर हरीश रावत और कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, दोनों ने ही भाजपा सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया. असल में हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर में बिजली गुल रहने से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया तो मौके की नजाकत भांपकर स्थानीय विधायक होने के चलते भगत ने भी धरने में ही शामिल होना उचित समझा. हरीश रावत ने उनके धरने पर बैठने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंशीधर भगत ने चौराहे पर सरकार की हांडी फोड़ दी है. हरीश रावत ने ट्वीट किया, ''बंशीधर भगत धरने पर हैं, कह रहे हैं बिजली विभाग चोर है. विपक्ष कहे बात समझ में आती है. अब तो सरकार ही अपने एक हिस्से को चोर बता रही है. ऐसे में 'हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या' यह सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है. बंशीधर भगत ने चौराहे पर इस सरकार की हांडी फोड़ दी है.''

राज्य में भाजपा के विभिन्न नेता अपनी हरकतों से पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं जो उसे भारी पड़ सकता है

असल में भाजपा में यह चर्चा आम है कि आगामी चुनाव में पार्टी से आम लोगों की नाराजगी के चलते पार्टी 20 से अधिक विधायकों के टिकट काटने जा रही है. इसी भय और अपना टिकट बचाने की कोशिश में विधायकों ने यह पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया है और जनता के बीच बने रहने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. ऐसा करते हुए दिखाई देने के लिए वे सरकार को भी असहज करने से नहीं चूक रहे. देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ, जो कांग्रेस से बगावत करके भाजपा में आए थे, की मुख्यमंत्री के क्षेत्र में उनके कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं से औकात देखने और दिखा देने की धमकियों को बयान करतीं तस्वीरें और वायरल वीडियो दिल्ली आलाकमान तक पहुंचा दी गईं. उमेश शर्मा काऊ खुद भी दिल्ली में आलाकमान से मिलकर आ गए. दिल्ली से लौटते ही न केवल उन्हें उनके साथ कांग्रेस से बगावत कर आए हरक सिंह का साथ मिला, बल्कि मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल का भी समर्थन मिला. इसने पार्टी के अंदरूनी झगड़े को चौराहे पर ला दिया.

इसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है. रायपुर क्षेत्र में भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक के खिलाफ महापंचायत कर डाली और विधायक को पार्टी से निकालने की मांग भी की. जाहिर है, ठीक चुनाव से पहले ऐसी हरकतों से भाजपा और उसके संगठन को तो नुक्सान होगा ही, सरकार को भी इससे असहज होना पड़ रहा है. यह राज्य की सत्तारुढ़ भाजपा को भारी पड़ सकता है. ■

एएनआइ

नई मंजिल
पानागढ़ में 10 सितंबर को पॉलीफिल्म फैक्ट्री परियोजना के उद्घाटन के दौरान ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल

दीदी मतलब अब कारोबार

रोमिता दत्ता

ममता बनर्जी सरकार को टाटा के लिए फिर से रेड कार्पेट बिछाने में एक दशक और तीन विधानसभा चुनावों में जीत का समय लगा. ममता नंदीग्राम-सिंगूर में टाटा नैनो फैक्ट्री (2006-08) के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दम पर सत्ता में आई थीं और उनकी सरकार लंबे समय तक अपनी उद्योग विरोधी छवि से मुक्त नहीं हो पाई.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कहते हैं कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (2015-19) के पांच संस्करणों से 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की चर्चा के बावजूद वास्तविक निवेश ''पिछले दशक में लगभग 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए का ही था.'' वे बताते हैं, ''इसमें से, केंद्र का योगदान लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए था. जहां तक नौकरियों का सवाल है, शायद बड़े उद्योगों में 1,00,000 और अन्य 3,00,000 एमएसएमई में सृजित किए गए.'' हालांकि पूर्व उद्योग मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री अमित मित्रा दावा करते हैं कि 40 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं.

6,000
एकड़
जमीन पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के पास है 12 औद्योगिक पार्कों के रूप में

तीसरे और निर्णायक जीत के साथ ममता बनर्जी को लगता है कि अब उद्योग को राज्य में लाने के लिए ठोस पहल करने का समय आ गया है. यह नए उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के इस बयान में दिख जाता है कि टाटा ''देश के सबसे सम्मानित व्यापारिक घरानों में से है और बंगाल आने और निवेश करने के लिए उसका स्वागत है.'' कोलकाता के पास राजारहाट में टाटा एक आइटी हब खोलने आ रहा है, और सरकार एसएसकेएम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को उन्नत बनाने के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई के साथ गठजोड़ कर रही है.

युवाओं के पलायन को रोकने के लिए ममता आइटी और आइटीईएस के दायरे का विस्तार कर रही हैं. सरकारी दावों के अनुसार, इनमें पांच गुना वृद्धि हुई है और इन इकाइयों की संख्या 500 से बढ़कर 2,600 हो गई है तथा निर्यात भी दोगुना (2018-19 में 29,000 करोड़ रुपए) हो गया है, जबकि पिछले दस वर्षों में रोजगार सृजन (90,000 से 2,10,000 नौकरियां) में भी बढ़ोतरी हुई है.

ममता अपने नए कार्यकाल में कुछ बड़े निवेश के साथ औद्योगीकरण अभियान शुरू करने की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन उन्हें पश्चिम बर्दवान के पानागढ़ में कोलकाता स्थित धनसेरी समूह के 1,250 करोड़ रुपए के पॉलीमर फिल्म निर्माण कारखाने के लिए समझौता करना पड़ा. यह 38 एकड़ में बनेगा, जो पानागढ़ औद्योगिक पार्क के 1,458 एकड़ भूमि बैंक से लिया गया है.

भूमि अधिग्रहण राज्य में अब भी एक प्रमुख बाधा है. टीएमसी सरकार ने 2015 में, निजी खिलाड़ियों की ओर से मालिकों/रैयतों से जमीन की सीधी खरीद की नीति अपनाई. राज्य की हस्तक्षेप न करने की नीति औद्योगिक घरानों के लिए उत्साहजनक नहीं है, लेकिन अधिकारी उन्हें 12 औद्योगिक पार्कों के रूप में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के पास पड़ी 6,000 एकड़ जमीन की ओर जाने की बात कह रहे हैं. निजी निवेशकों के लिए अपनी जमीन पर औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की स्वीकृत

औद्योगिक पार्क (एसएआइपी) योजना भी है, जिन्हें करों, बिजली आदि में छूट दी जाएगी.

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक निलांजन घोष कहते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हो सकता है. वे कहते हैं, ''मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निवेश तब तक नहीं आएगा, जब तक कि राज्य भूमि अधिग्रहण सुविधा के लिए सहमत नहीं हो जाता है.''

कोलकाता और उत्तर व दक्षिण 24 परगना के उपनगरीय जिलों में भूमि संकट को हल करने के लिए, राज्य निवेशकों की ओर से 5 एकड़ के छोटे भूखंडों पर स्थापित इकाइयों को भी औद्योगिक पार्क का दर्जा दे रहा है. इसमें निवेशकों को जमीन पर स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, बिजली सबस्टेशन बनाने के लिए ऋण, मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए 1.5 किमी का संपर्क मार्ग और 2 करोड़ रुपए के कैशबैक जैसे प्रोत्साहन मिलते हैं. इससे पांच एकड़ के कोल्ड चेन, मछली/पोल्ट्री फार्म और गोदामों को औद्योगिक पार्क का दर्जा और प्रोत्साहन मिल सकेगा. मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी का कहना है कि राज्य की योजना 100 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की है.

ममता ने सभी बाधाओं को दूर करने और मामलों में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक संवर्धन बोर्ड नामक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है. और इसका असर दिख रहा है. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के व्यापार सुगमता सूचकांक में, बंगाल अब गुजरात से आगे नौवें स्थान पर है. घोष आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और पर्यटन के ''सेवा क्षेत्रों में काफी संभावनाएं'' देख रहे हैं.

व्यापार सुगमता सूचकांक में, बंगाल अब गुजरात से भी आगे नौवें स्थान पर पहुंच गया है

सेवा क्षेत्र पहले से ही एनएसडीपी (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) में 53-55 फीसद का योगदान कर रहा है. पिछले दशक में, यह 6.5-7 फीसद बढ़ा है, जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग से सेवाओं की ओर ध्यान केंद्रित हो रहा है. आइटीईएस ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई. राजारहाट में सिलिकॉन वैली टेक हब के 200 एकड़ में से 160 एकड़ पर इसका कब्जा है. पार्थ चटर्जी कहते हैं, ''न्यू टाउन में बंगाल सिलिकॉन वैली तेजी से एक सैटेलाइट शहर बन रहा है.'' इन्फोसिस ने यहां अपने कार्यालयों में काम शुरू कर दिया है, विप्रो एक दूसरे परिसर में अपना विस्तार कर रहा है और दोनों परिसर 10,000 नौकरियों का वादा कर रहे हैं. बंगाल की योजना वर्ष 2030 तक देश के आइटी निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 फीसद करने की है.

उम्मीद का गलियारा

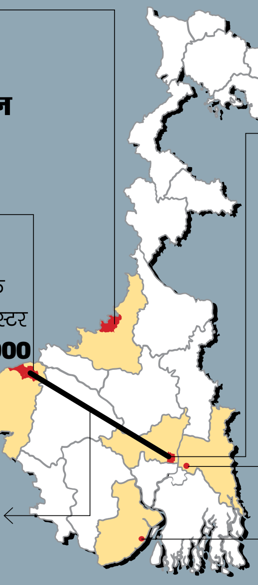

मुहम्मद बाजार
(बीरभूम जिला)
देवचा पचमी ओपन कास्ट माइन जिसमें **2.1 अरब टन** कोयले का भंडार है. निवेश: **12,000 करोड़ रु.**

रघुनाथपुर
(पुरुलिया जिला)
जंगल सुंदरी कर्मनगरी, एक एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर औद्योगिक टाउनशिप. **72,000 करोड़ रु.** निवेश और **70,000 नौकरियां** पैदा करने का अनुमान

डानकुनी से अमृतसर तक **1,856 किमी** लंबा फ्रेट कॉरिडोर, वाया रघुनाथपुर

डानकुनी
(हुगली जिला)

राजारहाट
(उत्तर 24 परगना जिला)
बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब में टीसीएस, रिलायंस जियो, एयरटेल, इन्फोसिस और विप्रो समेत 24 आइटी कंपनियों के कार्यालय हैं. राज्य का आइटी निर्यात 2024 तक **40,000 करोड़ रु.** पहुंच सकता है

ताजपुर
(पूर्व मेदिनीपुर जिला)
15,000 करोड़ रु. के निवेश से डीप सी पोर्ट प्रस्तावित है

ग्राफिकः असित रॉय

ममता ने पुरुलिया के रघुनाथपुर में एक औद्योगिक टाउनशिप—जंगल सुंदरी कर्मनगरी (जेएसके) शुरू किया है; यह अमृतसर और डानकुनी के बीच फ्रेट कॉरिडोर से ओवरलैप होगा. जेएसके रघुनाथपुर में 2,483 एकड़ जमीन को एक एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में विकसित करेगा. राज्य सरकार और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम बंगाल को पंजाब से जोड़ने वाले 1,856 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर का लाभ लेने के लिए 50:50 एसपीवी बनाएंगे. 1 सितंबर को पानागढ़ में लॉन्च के मौके पर ममता ने कहा, ''औद्योगिक गलियारा 72,000 करोड़ रुपए का निवेश लाएगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा.''

सरकार की उम्मीदें दुनिया के 'सबसे बड़े कोयला ब्लॉक' पर भी टिकी हैं—देवचा पचमी ओपन कास्ट खदान, जिसमें बीरभूम जिले के मुहम्मद बाजार में अनुमानित 2.1 अरब टन कोयले का भंडार है. इसको विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की एक योजना भी तैयार है. पर इस खदान से कोयला निकालना एक चुनौती होगी, क्योंकि भंडार बेसाल्ट चट्टान की एक मोटी परत के 200-300 मीटर नीचे है. यही वजह है कि अन्य राज्यों को संयुक्त रूप से ब्लॉक की पेशकश की गई थी.

व्यवसाय विशेषज्ञ प्रतिम रंजन बोस को लगता है कि राज्य के औद्योगिक विकास में एक बड़ी बाधा ममता और केंद्र सरकार के बीच खराब रिश्ते हैं. वे कहते हैं, ''जब वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट में कोलकाता-सिलीगुड़ी राजमार्ग की घोषणा की, तो राज्य में हड़कंप मच गया. इसका इसलिए विरोध किया गया कि यह उत्तर बंगाल के विकास को रोक देगा. इसलिए, सिलीगुड़ी के एक लॉजिस्टिक हब बनने के बजाए, पूरे पूर्वोत्तर और पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल और भूटान का ध्यान धीरे-धीरे गुवाहाटी में स्थानांतरित हो रहा है, जो तेजी से एक व्यापार और पारगमन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. यहां तक कि त्रिपुरा भी अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लिए बंगाल के बजाए गुवाहाटी पर निर्भर है.'' बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को भारत के 16 अरब डॉलर (1.18 लाख करोड़ रुपए) के निर्यात में पश्चिम बंगाल का योगदान बहुत कम है (चावल में 15 फीसद और इस्पात में करीब 10 फीसद). जाहिर है, बंगाल को अभी लंबा सफर तय करना है. ■

गेट्टी इमेजेज

तनावपूर्ण राज्य
तत्कालीन नागरिकता संशोधन कानून विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद 12 दिसंबर, 2019 को असम के गुवाहाटी में गश्त लगाते भारतीय सैनिक

आफ्सपा

युद्ध या शांति?

कौशिक डेका

असम सरकार ने 11 सितंबर को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, (एएफएसपीए), 1958 के तहत राज्य के 'अशांत क्षेत्र' के दर्जे को फिर से अगले छह महीने के लिए विस्तार दे दिया है. राज्य सरकार ने इस विस्तार के पीछे की वजह को अभी तक नहीं बताया है. वहीं, इस कदम को ऐसे समय में उठाया गया है जब केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की अगुआई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कर रही है, और जिसका लगातार यह दावा रहा है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में अब शांति वापस आ गई है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर को यह ऐलान किया कि केंद्र, राज्य और असम के कर्बी आंगलांग जिले में सक्रिय छह उग्रवादी समूहों के बीच त्रिपक्षीय समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'उग्रवादमुक्त, समृद्ध पूर्वोत्तर' की उनकी दृष्टि का एक अन्य मील का पत्थर है. फरवरी, 2020 में, केंद्र सरकार ने बोडो उग्रवादी समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सभी गुटों के साथ एक अन्य समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसको बोडो उग्रवाद का अंत बताया गया था. इस हफ्ते की शुरुआत में, असम के सबसे खतरनाक उग्रवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (आइ) (उल्फा) के मुखिया परेश बरुआ ने भी पहली बार शांति वार्ता के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है और इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है.

इन घटनाक्रमों से राज्य से एएफएसपीए को हटाने की मांग तेज हो गई है और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि राजनैतिक लाभ के लिए इस कठोर कानून का दुरुपयोग किया जाता रहा है. गुवाहाटी स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. दिव्यज्योति सैकिया कहते हैं, ''सरकार राज्य में शांति स्थापित करने के दावे का कोई मौका जाने नहीं देना चाहती, तो इसको एएफएसपीए की क्या जरूरत है? यह खुला रहस्य है कि बहुत सारे हितधारक हैं, जो चाहते हैं कि आतंक खत्म करने के नाम पर आने वाला केंद्रीय फंड नहीं रुके.''

एएफएसपीए को नगालैंड में उग्रवाद से निबटने के लिए 1950 के दशक में लागू किया गया और इसको असम में 1990 के दशक में लागू किया गया जब उल्फा के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू हुआ था. तब से, इसको हर छह महीने तक बढ़ा दिया जाता है. केंद्र और राज्य सरकार, दोनों को एएफएसपीए के तहत अधिसूचना जारी करने का समवर्ती अधिकार है. असम के साथ ही, यह नगालैंड, मणिपुर (इम्फाल नगरपालिका परिषद का क्षेत्र छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लांगडिंग और तीरप जिलों तथा असम से लगने वाले अरुणाचल के विभिन्न जिलों के आठ पुलिस थानों में लागू है.

यहां तक कि एएफएसपीए के जारी रहने के द्वंद्व को जुलाई, 2018 में संसद के दोनों सदनों में ''भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति'' पर घरेलू मामलों पर विभाग संबंधित स्थायी समिति की 213वीं रिपोर्ट में भी उजागर किया गया था: ''समिति असम की स्थिति की अलग-अलग धारणाओं को समझने में असमर्थ है. एक तरफ मंत्रालय ने दावा किया

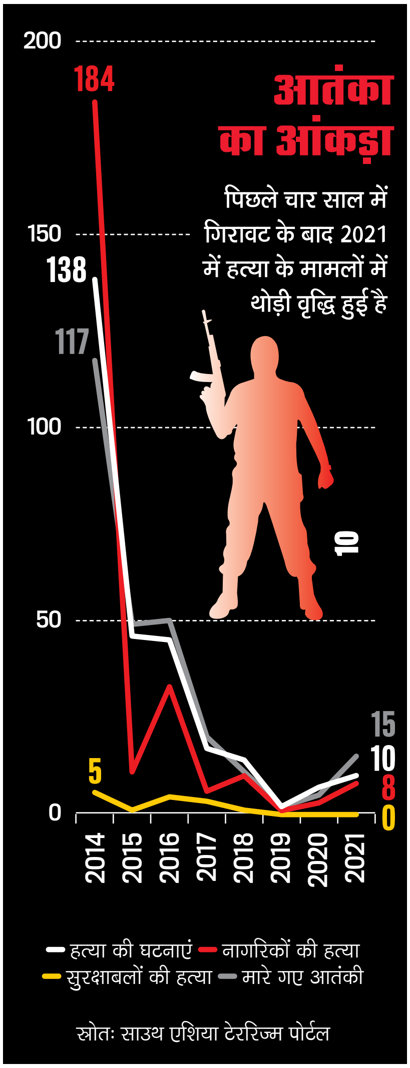

आतंक का आंकड़ा

पिछले चार साल में गिरावट के बाद 2021 में हत्या के मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई है

स्रोतः साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल

186

मानवाधिकार उल्लंघन के मामले (अकेले असम में 58) सशस्त्र बलों की ओर से 2012 से 2016 के दौरान

स्रोतः आरटीआइ

114

सशस्त्र बल के जवानों के खिलाफ कथित यौन हिंसा के मामले 11 राज्यों में (2000-20). असम 21 मामलों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर

स्रोतः नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर

> 2000 और 2020 के बीच 11 राज्यों में सशस्त्र बलों की ओर से किए गए कथित 114 यौन हिंसा के मामले सामने आए

है कि असम में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एएफएसपीए के तहत अशांत घोषित क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है... यह विरोधाभासी स्थिति है जिसका समाधान करने की जरूरत है. इसलिए, यह समिति, इस बात की सिफारिश करती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले पर गहन विचार-विमर्श करना चाहिए और असम में एएफएसपीए की जरूरत पर अपने नजरिए को बदलना चाहिए.''

एक साल के बाद, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में पिछले पांच साल की तुलना में 'व्यापक सुधार' हुआ है और उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 66 फीसद की कमी आई है. साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल (एसएटीपी) के आंकड़े बताते हैं कि असम में आतंकवादी घटनाओं में हत्याओं की संख्या साल 2014 में 138 से घटकर 2020 में महज 7 रह गई हैं. हालांकि इस साल हत्याओं में थोड़ा इजाफा हुआ है और अभी तक 10 हत्याएं हो चुकी हैं.

इन संख्याओं के बावजूद, राज्य सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि उल्फा और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) जैसे हथियारबंद गुट अभी भी पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं, ऐसे में एएफएसपीए अभी हटाया नहीं जा सकता. सरमा कहते हैं, ''लेकिन इससे उग्रवादी संगठनों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के लिए राज्य या केंद्र सरकार के रास्ते बंद नहीं होते.'' एक सरकारी अधिकारी इस साल की शुरुआत में अपहरणों की एक शृंखला और पिछले महीने दिमासा उग्रवादियों की ओर से पांच ट्रक ड्राइवरों की हत्या की ओर इशारा करते हुए एएफएसपीए की अहमियत जताते हैं.

हालांकि, केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के लिए समीक्षा कर रही है, असम और मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करने का काम राज्य सरकारों ने साल 2017 के बाद से खुद कर रखा है जो एएफएसपीए लागू करने के लिए पूर्वशर्त है. यह प्रावधान मेघालय से 2018 में (28 साल के बाद) और त्रिपुरा से भी उसी साल यानी 2018 में (18 साल के बाद) हटा लिया गया था. वास्तव में, 2018 में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि त्रिपुरा में एएफएसपीए को हटाने की कार्यवाही से शांति स्थापित करने में काफी मदद मिली है.

असल में एएफएसपीए को इस तरह से तैयार किया गया था कि सशस्त्र बलों को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया जा सके क्योंकि यह इलाका हथियारबंद प्रतिरोध झेल रहा था और हर वक्त न्यायिक अधिकारी की उपलब्धता मुश्किल हो सकती थी. इस अधिनियम का खंड 4 सैन्य अधिकारियों को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जिसे लेकर इस बात के पर्याप्त शक हो कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है. यह सेना को इस बात के भी विशेष अधिकार देता है कि वह ऐसे ढांचों को तोड़ दे जो छिपने के स्थान या प्रशिक्षण शिविर या ऐसी जगह के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हों जहां से हमला संचालित किया जा सके. सशस्त्र बलों को नतीजों की चिंता किए बगैर फायरिंग करने की अनुमति है, बशर्ते वहां पर पांच या अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए जा चुके हों. इस कानून का सेक्शन 6 सैन्य बलों को मुकदमे की कार्रवाई या कानूनी प्रक्रियाओं से तब तक सुरक्षित रखते हुए अपनी ड्यूटी निभाने की सुरक्षा प्रदान करता है, जब तक कि कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी न मिल जाए.

केंद्र सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि इस तरह की व्यापक शक्तियों के नतीजतन कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है. साल 2017 में, एक आरटीआइ आवेदक ने पाया कि साल 2012 और 2016 के बीच, एएफएसपीए वाले राज्यों में सशस्त्र बलों के खिलाफ हत्या और यौन अपराधों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन की 186 शिकायतें दर्ज की गईं.

इस सूची में 58 शिकायतों के साथ, असम दूसरे स्थान पर था. नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि साल 2000 और 2020 के बीच 11 राज्यों में यौन हिंसा के 114 मामले कथित रूप से सशस्त्र बलों की ओर से किए गए. ऐसे 21 मामलों के साथ असम इस सूची में सबसे ऊपर है. ■

बातचीत

“हमने ज्यादा जोर जमीनी स्तर पर बदलाव लाने पर दिया है”

संदीप सहदेव

कोविड महामारी ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को तो बुरी तरह प्रभावित किया लेकिन राज्य का सेब कारोबार सुरक्षित रहा. ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर **राज चेंगप्पा** और वरिष्ठ संपादक **अनिलेश एस. महाजन** ने राज्य के मुख्यमंत्री, 56 वर्षीय **जयराम ठाकुर** से बातचीत की और उनकी सरकार की अपने नागरिकों के टीकाकरण में प्रभावशाली प्रगति के बारे में जाना और समझने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री आखिर क्यों इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि राज्य में पर्यटन और अन्य उद्योग जल्द अपनी पूरी गति से शुरू हो जाएंगे. बातचीत के प्रमुख अंश:

● बागबानी आपकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. क्या आप महामारी के बावजूद उत्पादन को बनाए रखने में सक्षम थे? स्थिति में सुधार के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

लगभग 4,500 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ सेब की खेती हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है और हमने पिछले साल कोविड प्रतिबंधों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया था. अधिकांश बाग मालिकों के सामने चुनौती यह है कि जब सेब बाजार में पहुंचने लगते हैं, तो एकाएक बहुतायत पैदा हो जाती है और कीमतें गिर जाती हैं. सरकारी एजेंसियों के अलावा, हम निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कोल्ड चेन सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं. हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन इकाइयों को अगले सीजन में चालू कर दिया जाएगा और हमारे पास फलों की प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) की क्षमता होगी. ओलावृष्टि से फलों को सुरक्षित रखने के लिए हम बाग मालिकों को सुरक्षा जाल खरीदने में भी 80 प्रतिशत की सब्सिडी देकर सहायता कर रहे हैं. इसके अलावा, जंगली जानवरों को उनके फलों के पेड़ों से दूर रखने के लिए सोलर बाड़ लगाने में भी हम उनको मदद दे रहे हैं.

> “हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी वयस्क आबादी के कोविड टीकाकरण का पहली खुराक का लक्ष्य 100 फीसद प्राप्त कर लिया है”

● कोविड की दो लहरों में हिमाचल का पर्यटन आखिर कितना प्रभावित हुआ?

इसने बहुत बुरी तरह प्रभावित किया. पिछले साल पर्यटन राजस्व में कोई 75 प्रतिशत की गिरावट आई थी. लेकिन इस साल धीरे-धीरे चीजें सुधर रही हैं और राजस्व में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य हो जाएं. हमने पहले राज्य में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को आरटी-पीसीआर जांच और टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने के प्रतिबंधों में ढील दी थी. लेकिन

अचानक पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इससे कोविड के सक्रिय मामलों में भी वृद्धि हुई. इसलिए हमें फिर से प्रतिबंध लगाने पड़े. हमने 2 अगस्त से राज्यों में शिक्षण संस्थान भी खोले थे, लेकिन उन्हें फिर से बंद करना पड़ा. हम अभी पूरा जोर टीकाकरण पर दे रहे हैं.

● राज्य में कोविड टीकाकरण की क्या स्थिति है?

हिमाचल प्रदेश अपनी वयस्क आबादी का 100 प्रतिशत टीकाकरण (पहली खुराक) करने वाला देश का पहला राज्य है. शुरू में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जब टीके के साइड इफेक्ट की भ्रामक अफवाहें फैलने लगीं. इसलिए, हमने अपने स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से, साथ ही वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया. मैंने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों से दो बार बात की और उनको अपने-अपने वार्डों और पंचायतों में हर घर तक पहुंचने को कहा. इलाका चाहे कितना भी दुर्गम हो, हम राज्य के कोने-कोने में पहुंचे हैं और कई मामलों में स्वास्थ्य कर्मियों ने दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए तीन-चार दिनों तक ट्रेकिंग की है. नवंबर के अंत तक हमारे राज्य में पूर्ण टीकाकरण हो जाएगा.

● महामारी के दौरान राज्य के अन्य उद्योगों की क्या स्थिति रही?

अन्य राज्यों की तरह हमारी अर्थव्यवस्था भी कोविड के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई थी. 2019 में आर्थिक मंदी के बावजूद हमें 96,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू मिले थे, लेकिन इन परियोजनाओं पर कोविड का असर पड़ा. आखिरकार अब वे शुरू हो रही हैं. साथ ही, उत्पादन मोटे तौर पर संतोषजनक गति से हो रहा है.

● आप राज्य में कनेक्टिविटी (संपर्क मार्ग) बढ़ाने के लिए क्या रहे हैं?

कीरतपुर—मनाली एक्सप्रेस वे सहित चार लेन के राजमार्गों की कुछ परियोजनाएं हैं, जिनमें कुछ दिक्कतें थीं और उसके कारण थोड़ा विलंब हुआ. अब हमने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के साथ, इन्हें सुलझा लिया है और हाल ही में नए टेंडर जारी किए गए थे. अब हम सभी राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी ला रहे हैं.

जहां तक हवाई संपर्क की बात है, हमारे पास शिमला, धर्मशाला और कांगड़ा में तीन हवाई अड्डे हैं लेकिन ये सारे छोटे हवाई अड्डे हैं और वहां लोड पेनाल्टी लगती है जिससे टिकट की कीमतें बढ़ जाती हैं. टिकट महंगे हो जाने से यात्री हवाई यात्राओं के लिए हतोत्साहित होते हैं. समाधान के तौर पर हम मंडी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी विकसित कर रहे हैं. संबंधित एजेंसियों ने उस स्थान का सर्वेक्षण किया है और मैंने इसे आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में केंद्रीय वित्त और नागरिक उड्डयन मंत्रियों से मुलाकात की थी. लेकिन समस्या यह है कि भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य को पैसे खर्च करने होंगे. अकेले इस एयरपोर्ट की जमीन पर 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा. हमें आर्थिक मदद की जरूरत होगी.

● इस साल आपके राज्य में भूस्खलन की कई घटनाएं हुईं और कई लोगों की जान गई...

> **"राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसका वह सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सके"**

इस बार बारिश सामान्य और अपेक्षा के अनुरूप रही पर भूस्खलन असामान्य रूप से हुआ. यहां तक कि शुष्क और खिली धूप के दिनों में भी भूस्खलन की कुछ घटनाएं हुईं, जो असामान्य हैं. हमने गृह मंत्रालय के सामने मुद्दे को रखते हुए इन मामलों के वैज्ञानिक अध्ययन का अनुरोध किया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या भूस्खलन की अग्रिम चेतावनी की कोई व्यवस्था बन सकती है.

● आपकी तत्काल प्राथमिकताएं क्या हैं?

चूंकि कोविड प्रतिबंधों के कारण बहुत-से संवाद और संपर्क आभासी तरीके से हो रहे थे इसलिए हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि लोगों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव फिर से कैसे शुरू किया जाए. राज्य इस वर्ष अपनी स्थापना के 50वें वर्ष का जश्न मना रहा है और जनवरी 2022 में हम विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करेंगे जिसके लिए हमने राष्ट्रपति महोदय को संबोधन के लिए आमंत्रित किया है. 2 अक्तूबर से हम 'हिमाचल तब और हिमाचल अब' यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो राज्य के 68 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी. यह जनता को समर्पित होगी और इसमें उन्हें राज्य में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण का श्रेय दिया जाएगा.

● अगले साल होने वाले चुनावों में फिर से अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं?

ऐसा पहली बार है कि सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है. कुछ सत्ता विरोधी भावना हो सकती है लेकिन ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं जिसका विपक्ष फायदा उठा सके. जहां तक चुनाव की योजना और रणनीति बनाने का सवाल है, पार्टी के पास इसके लिए अभी पर्याप्त समय है. हिमाचल में हमने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया है. हमारी सरकार ने इस बार यह सुनिश्चित किया कि विकास अंतिम दरवाजे तक पहुंचे और उसके रास्ते में कोई अड़ंगा न लगने पाए. विकास कार्यों के आवंटन में कोई क्षेत्रीय पूर्वाग्रह (ऊपरी और निचले हिमाचल के बीच) नहीं है. राज्य में कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं हो रही. मेरा एकमात्र ध्यान विकास पर है और यह पक्का करना है कि परियोजनाओं को कुशलता से क्रियान्वित किया जाए. हम सर्वसुलभ हैं. मेरे सभी मंत्री नियमित रूप से लोगों के साथ संवाद करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता हैं और उन्होंने देश में भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है. वे निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर होंगे और मतदाता राज्य के विकास में सरकार के योगदान को देखकर वोट करेंगे.

● आगामी उपचुनावों के बारे में क्या कहेंगे?

चार उपचुनाव होने हैं, तीन विधानसभा सीटों के लिए और एक लोकसभा के लिए. अकेले मंडी लोकसभा क्षेत्र 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है. हम सीट बरकरार रखने को लेकर आश्वस्त हैं. विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से थोड़ा अधिक शेष है और अगर उपचुनाव नवंबर तक नहीं हो पाते, तो चुनाव आयोग शायद खुद ही इन चुनावों को कराने के बारे में दोबारा सोचे. हम चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं. ■

पुरुषोत्तम दिवाकर

< मजा के बाद सजा पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया

राजस्थान

पुलिस का अश्लील पक्ष

रोहित परिहार

यह साल राजस्थान पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक रहा है क्योंकि उसके जवान लगातार अश्लील और भ्रष्ट हरकत वाले मामलों में लिप्त पाए गए. नवीनतम मामले में कुछ वीडियो वायरल हो गए हैं, जिनमें कथित तौर पर बड़े लोगों से बेहतर संबंध रखने वाला पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी एक महिला कांस्टेबल के साथ यौन संबंध बनाते दिख रहा है. यही नहीं, पुष्कर के एक पांच सितारा रिजॉर्ट के एक्सक्लूसिव स्विमिंग पूल वाले रूम में उस कांस्टेबल का बच्चा भी पूल में नंगा है. वह यह सब देख रहा है और जाने-अजाने वह भी उन दोनों के साथ शामिल हो जाता है.

पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को उन दोनों पुलिसवालों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा. उन्हें उदयपुर के एक आलीशान रिजॉर्ट में गिरफ्तार किया गया और उन पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज समेत कई आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच से पता चला है कि वह महिला अपने पति से अलग रह रही थी और जब दोनों पुलिसवाले जयपुर में तैनात थे तो सैनी से उसके संबंध बन गए. सैनी ने कथित तौर पर उसे जयपुर में एक फ्लैट दिला दिया. बाद में भाजपा के शासन के दौरान सैनी का तबादला ब्यावर में हो गया और सरकार बदलने के बाद भी वह वहीं नियुक्त था, अब इसके तीन साल हो गए.

जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि जाहिरा तौर पर वह महिला पहले भी इस तरह के वीडियो बनाकर एक फोल्डर में रख रही थी. उसने या उसके बच्चे ने गलती से व्हाट्सऐप स्टैटस पर अपलोड कर दिया. महिला के पति ने इसे देखा और दो पुलिस थानों में इसकी शिकायत दर्ज कर दी. दोनों के परिवार वालों ने ये वीडियो देख लिए. पुलिस अधिकारियों ने एफआइआर दर्ज करने के बजाए पति और पत्नी के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास किया और अगस्त के आखिर में उन्हें आपसी सहमति से तलाक के लिए राजी कर लिया. इस बीच महिला के एक संबंधी ने उसे फोन करके फिरौती की मांग की. इस पर उस महिला ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. लेकिन कुछ ही रोज बाद कुछ वीडियो वायरल हो गए.

पुलिस महानिदेशक लाठर ने कहा कि राजस्थान पुलिस में जबरदस्त बदलाव की जरूरत है. हाल में जब उन्हें जांच से पता चला कि कई पुलिसवाले बेजा हरकतों और अपराधियों से मिलीभगत में शामिल हैं तो उन्होंने 300 पुलिसवालों का तबादला कर दिया. उनका कहना है, ''मैंने इस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश की पर राजस्थान हाइकोर्ट ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक की रैंक के करीब 250 तबादलों को यह कहते हुए रोक दिया कि उन्हें नियुक्ति वाले जिले से बाहर नहीं भेजा जा सकता.'' वे डबल बेंच में इसे ले जाने वाले हैं. वहीं, प्रमुख आरटीआइ एक्टिविस्ट और वकील गोवर्धन सिंह ने बताया, ''सैनी को सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन उसके संबंधों को देखते हुए मुझे संदेह है कि सरकार ऐसा करेगी.''

> **पिछले एक साल में राजस्थान पुलिस में यौन हमले, रिश्वत और अपराधियों से मिलीभगत के कई मामले सामने आए हैं**

लाठर ने बीते एक साल में अपने बल में यौन हमले और भ्रष्टाचार के ऐसे कई शर्मनाक मामले देखे हैं. पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नदी से बालू की अवैध ढुलाई में रिश्वतखोरी पर चिंता जाहिर की थी. मार्च में एसीबी ने एक असिस्टेंट पुलिस कमिशनर कैलाश बोहरा को एक महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया. महिला ने शिकायत की थी कि बोहरा ने उसके बलात्कार के मामले की जांच करने के एवज में यौन संबंध बनाने की मांग की थी. गहलोत ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया. उसी समय वरिष्ठ अधिकारियों को एक सब इंस्पेक्टर भरत सिंह की गिरफ्तारी के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा. अपने पति के खिलाफ अलवर थाने में शिकायत दर्ज कराने आई महिला के साथ उसने बलात्कार किया था. इस साल फरवरी में एसीबी ने दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे ठेकेदार से मोटी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया.

पिछले हफ्ते गहलोत ने हिम्मत अभिलाष टाक को निलंबित किया जिन पर जुलाई में सिरोही के एसपी पद से हटाया गया था. उन पर शराब तस्करों से मिलीभगत का आरोप है. अप्रैल में कुछ पुलिस वालों की मुखबिरी के कारण अफीम तस्करों पर धावा बोलने गए दो कांस्टेबल मारे गए थे. एक अन्य मामले में, अप्रैल में बारमेड़ के अफीम तस्कर कमलेश प्रजापत की हत्या की सीबीआइ जांच को गहलोत को मजबूर होना पड़ा. स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रजापत को कुछ नेताओं के इशारे पर मारा गया, जिसमें उससे लाभ उठाने वाले एक मंत्री भी शामिल हैं. ■

अर्थात्

तेल की चौसर

अंशुमान तिवारी

भारत में क्या लोग महंगा पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए अभिशप्त हैं? या अगर सरकार टैक्सखोरी छोड़ दे तो दुनिया में कई ताजा करवटों की मदद से हमारी जिंदगी जीने की लागत सस्ती हो सकती है? सवालों के जवाब पांच ताजा घटनाओं में छिपे हैं.

पहली करवट

अगस्त 1946—अमेरिका में फिलाडेल्फिया के तट पर 1,15,000 बैरल तेल लेकर आया टैंकर लंगर डालने की तैयारी में था. कुवैत से चले इस टैंकर के तेल पहुंचते ही अमेरिका आधिकारिक तौर पर के तेल आयातक हो गया. दो साल के अंदर सऊदी अरब का तेल भी अमेरिका पहुंचने लगा.

दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक अमेरिका तेल का इतना बड़ा निर्यातक था कि जंग में मित्र देशों की तेल खपत का 90 फीसद हिस्सा अमेरिका से आया. अलबत्ता युद्धोत्तर मांग और ऑटोमोबाइल उद्योग की उड़ान के साथ 1948 में अमेरिका प्रमुख आयातक हो गया. दुनिया की सियासत पर, इस करवट का असर अगले सत्तर साल तक रहने वाला था.

2014 में अमेरिका के (सऊदी अरब और रूस के बाद) तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बनने के साथ तेल कीमतों में निर्णायक ढलान शुरू हो गई थी. लेकिन 2019 का नवंबर में वक्त ने सबसे बड़ी करवट ली. अब अमेरिका तेल (रिफाइनरी उत्पाद और कच्चा तेल) का शुद्ध निर्यातक बन गया है. वह अपने यहां गैसोलीन सस्ता रखते हुए ओपेक कार्टेल का दबदबा तोड़ रहा है. कनाडा और लैटिन अमेरिका के बाजारों को अमेरिकी आपूर्ति के बाद 2020 से तेल की कीमतों ने उबलना बंद कर दिया. अमेरिका अब दुनिया के अन्य बाजारों को तेल निर्यात के लिए तैयार है.

दूसरी करवट

मार्च 2020—कोविड के कहर के बीच सऊदी अरब ने एशिया, अमेरिका व यूरोप के लिए कच्चे तेल की कीमत 6-8 डॉलर प्रति बैरल कम कर दी. ब्रेंट क्रूड, 1991 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करता हुआ 34 डॉलर प्रति बैरल से नीचे चला गया. इस फैसले से क्रूड ही नहीं टूटा बल्कि तेल उत्पादक देशों के 60 साल पुराने कार्टेल यानी ओपेक की एकजुटता भी दरक गई. ओपेक का सितारा अमेरिका के टेक्सस में कच्चे तेल का उत्पादन गिरने के बाद (1970) बुलंद हुआ था.

सऊदी अरब ने 2021 में भी सस्ता तेल बेचने का ऐलान किया. ओपेक प्लस (रूस) में असहमतियां बढ़ रही हैं. इस कार्टेल के सदस्य अब एक साथ उत्पादन घटाने-बढ़ाने पर राजी नहीं हैं. वे कीमतें घटाकर बाजार बचाने की गलाकाट होड़ में उतर रहे हैं. भारत जैसों के लिए इसे अच्छी खबर क्या हो सकती है?

तीसरी करवट

मार्च 2018—चीन ने शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज पर युआन आधारित ऑयल फ्यूचर्स सौदों की शुरुआत की. यह पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन के दौर का ऐलान था. खाड़ी में चीन की सक्रियता तेजी से बढ़ी है. वह सऊदी अरब का सबसे बड़ा व्यापारिक दोस्त है. तेल बाजार में चर्चा है कि सऊदी अरामको (विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी) चीन की कंपनी को अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है.

चौथी करवट

इंटरनेशल एनर्जी एजेंसी बता रही है कि तेल की मांग अब उबलने वाली नहीं है. महामारी ने जिंदगी बदल दी है. सभी देश ऊर्जा के नए गैर हाइड्रोकार्बन स्रोत पर काम कर रहे हैं. 2026 में विश्व में तेल की खपत का स्तर 2019 के बराबर ही रहेगा. तेल कंपनियां नया निवेश नहीं कर रही हैं. रिफाइनिंग उद्योग अब शायद कभी अपनी पूरी क्षमता (अभी 68-75 फीसद) का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

यह चारों करवटें बता रही हैं कि

- कच्चे तेल की तेजी के दिन गए. होड़ बढ़ी तो कीमतें और टूटेंगी.
- कच्चे तेल की कीमत अब कार्टेल के जरिए नहीं बल्कि देशों के दोतरफा कूटनीतिक रिश्तों से तय होगी.

इन करवटों की धमक के बीच भारत के पेट्रोल-डीजल बाजार में भी सरकारी कार्टेल टूटने वाला है. जुलाई में सरकार ने छह निजी कंपनियों को पेट्रोल पंप खोलने की छूट दी. पहले यह लाइसेंस लेने के लिए तेल उद्योग में 2,000 करोड़ रुपए के निवेश की शर्त थी लेकिन अब केवल 250 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कोई कंपनी पेट्रोल पंप खोल सकती है. उन्हें सीधे आयातित तेल बेचने की छूट भी होगी. इसी व्यवस्था में रिलायंस ने बीपी के साथ नया लाइसेंस लिया है.

भारत में सस्ता पेट्रोल-डीजल संभव है. रिलायंस का रिफाइनिंग मार्जिन (एक बैरल कच्चे तेल को ईंधन में बदलने पर कमाई) करीब 12 डॉलर प्रति बैरल है जो सरकारी कंपनियों से दो डॉलर ज्यादा है. तेल विक्रेता देशों के बीच होड़ और अग्रिम खरीद का लाभ लेकर कंपनियां पेट्रोल-डीजल बाजार में होड़ शुरू कर सकती हैं. सऊदी अरामको तो रिलायंस की भागीदार है जो सस्ता तेल बेच रही है.

विनिवेश के बाद भारत पेट्रोलियम के निजी कंपनी में बदलते ही प्रतिस्पर्धा का चेहरा बदल जाएगा. बस दुआ कीजिए कि सरकार को पेट्रोल-डीजल पर टैक्सखोरी छोड़ने की सद्‌बुद्धि मिले. हमारी महंगाई का सबसे बड़ा अभिशाप खत्म होने को है.

@anshuman1tiwari

अगर सरकार टैक्सखोरी छोड़ दे तो दुनिया में कई ताजा करवटों की मदद से जीने की लागत सस्ती हो सकती है

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

एसेट मॉनिटाइजेशन

इस बार बड़ा ख्वाब

मोदी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों के 'मॉनिटाइजेशन' यानी निजी क्षेत्र को लंबे वक्त के लिए लीज पर देकर अगले चार वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए उगाहने की ख्वाहिश, क्या वह इस बड़े बदलाव में कामयाब हो पाएगी?

एम.जी. अरुण और श्वेता पुंज / इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली, तो उनके बड़े वादों में एक ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम राजकाज'' भी था. उम्मीद यह थी कि उनकी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ संपत्तियों से अपना नियंत्रण हटा लेगी. उन्हें सीधे निजी क्षेत्र को बेच दिया जाएगा या उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रबंधन/संचालन में निजी क्षेत्र को शामिल कर लिया जाएगा. अपने पहले कार्यकाल में उनकी सरकार इस मोर्चे पर कुछ खास नहीं कर सकी. विपक्ष के 'सूट-बूट की सरकार' के ताने से वह घिर जो गई थी.

इस साल फरवरी में केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने विनिवेश और सरकारी परिसंपत्तियों के मॉनिटाइजेशन या मौद्रीकरण की दो जोरदार घोषणाएं कीं, जो निजी क्षेत्र से जुड़ी थीं. विनिवेश की उसकी कोशिशों के शुरुआती नतीजे मिले-जुले रहे.

एयर इंडिया की बिक्री में कुछेक निजी आवेदकों ने दिलचस्पी दिखाई और इसकी बोली की प्रक्रिया इसी वित्त वर्ष में पूरी होनी है, वहीं एलआइसी (जीवन बीमा निगम) इस साल शेयर सूचीबद्ध करवाने की तैयारी में जुटा है. हालांकि बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आइडीबीआइ बैंक सरीखे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री अधर में लटकी है. यही वह मोड़ है, जब सरकार ने अपना अगला बड़ा अभियान—परिसंपत्तियों का मॉनिटाइजेशन—शुरू करने का फैसला किया. इसके तहत सरकारी संपत्तियां अग्रिम शुल्क के एवज में निजी कंपनियों को दी जाएंगी. सरकार का मानना है कि इस तरह

फेहरिस्त में क्या-क्या

केंद्र की योजना 13 क्षेत्रों में मॉनिटाइजेशन के जरिए वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 25 के बीच अनुमानित 6 लाख करोड़ रुपए हासिल करने की है. इसके तहत फेहरिस्त में सबसे ऊपर सड़कें, रेलवे, टेलीकॉम, बिजली उत्पादन और पारेषण परियोजनाएं हैं

सड़कें

▶1,60,200 करोड़ रु.

26,700 किमी.
सड़कों का मॉनिटाइजेशन

20%
लंबी सड़कें, मॉनिटाइजेशन की संभावना वाली कुल सड़कों की लंबाई में

विमानन*

▶20,782 करोड़ रु.

वि.व. 22: 3,600 करोड़ रु.
भुवनेश्वर, वाराणसी, त्रिच्चि, अमृतसर, इंदौर, रायपुर

वि.व. 23: 4,295 करोड़ रु.
कालीकट, कोयंबतूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर

वि.व. 24: 4,193 करोड़ रु.
चेन्नै, विजयवाड़ा, तिरुपति, वडोदरा, भोपाल, हुबली

वि.व. 25: 1,857 करोड़ रु.
इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून, राजमुंदरी

रेलवे

▶1,52,496 करोड़ रु.

रेलवे स्टेशन
400 (कुल स्टेशनों का 5.5%)

पैसेंजर ट्रेनें
90 (कुल ट्रेनों का 5%)

रेलवे ट्रैक
~1,400 किमी का 1 रूट (कुल नेटवर्क का 2%)

कोंकण रेलवे
741 किलोमीटर

पर्वतीय क्षेत्र का रेलवे
4,244 किलोमीटर

मालगोदाम
265 (रेलवे के स्वामित्व वाले मालगोदामों का 21%)

खनन

▶28,747 करोड़ रु.

160 परियोजनाएं
मॉनिटाइजेशन के लिए चिन्हित

761
खनिज ब्लॉकों की वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 के बीच नीलामी होने की संभावना है

दूरसंचार

▶35,100 करोड़ रु.

भारतनेट फाइबर
~2.86 लाख रूट किमी दूरसंचार विभाग के पीपीपी मॉडल के जरिए नीलामी को प्रस्तावित. इसके नौ पैकेज में 16 राज्य शामिल

बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावर
~14,900 टावरों के मॉनिटाइजेशन की योजना

बंदरगाह

▶12,828 करोड़ रु.

बड़े बंदरगाहों की 31 परियोजनाएं

पारादीप पोर्ट **4**
दीनदयाल पोर्ट (कांधला) **4**
जेएनपीटी (मुंबई) **3**
मोरमुगांव पोर्ट **3**
मुंबई पोर्ट **2**
एस.पी. मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (खिदरपुर) **4**
एस.पी. मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (हल्दिया) **3**
विशाखापत्तनम पोर्ट **4**
वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट **3**
न्यू मंगलौर पोर्ट **1**

विद्युत पारेषण

▶45,200 करोड़ रु.

4,13,407
सर्किट किमी
कुल ट्रांसमिशन की संपत्ति थी, 31 मार्च 2019 तक

~28,608
सर्किट किलोमीटर
कुल इतनी संपत्ति के मॉनिटाइजेशन की योजना

बिजली उत्पादन

▶39,832 करोड़ रु.

पनबिजली संपत्तियां (मौजूदा): **3,355 मेगावाट**

रिन्यूएबल ऊर्जा संपत्तियां (मौजूदा): **1,962 मेगावाट**

पनबिजली संपत्तियां (ऑनलाइन आने को): **117 मेगावाट**

रिन्यूएबल ऊर्जा संपत्तियां (ऑनलाइन आने को): **532 मेगावाट**

कुल **5,970 मेगावाट**

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

▶24,462 करोड़ रु.

7,928 किमी
ऑपरेशनल पाइपलाइन मॉनिटाइजेशन के लिए प्रस्तावित

~200 किमी
की नई पाइपलाइन (जिसे अभी चालू होना है) भी मॉनिटाइज होनी है

पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन

▶24,462 करोड़ रु.

पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन: **3,196 किमी**

एलपीजी पाइपलाइन: **733 किमी**

हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र: **2**

▶ संपत्तियों का मूल्य

* इन शहरों के हवाई अड्डे

भंडारण
▸28,900 करोड़ रु.

भंडारण का ढांचा (एफसीआइ): **17,500 करोड़ रु.**

भंडारण का ढांचा (सीडब्लूसी): **11,400 करोड़ रु.**

कुलः **28,900 करोड़ रु.**

(एफसीआइः भारतीय खाद्य निगम;
सीडब्लूसीः केंद्रीय भंडारागार निगम)

खेल के स्टेडियम
▸11,450 करोड़ रु.

महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का विकास

7,853 करोड़ रु.
संकेतात्मक कैपेक्स निवेश

मौजूदा सुविधाएं

मुख्य क्षेत्र	सभागार	छात्रावास परिसर
60,000 दर्शक क्षमता	**2,172** लोगों के लिए बैठने की क्षमता	**140** कमरे + **100** निर्माणाधीन

शहरी अचल संपत्ति
▸15,000 करोड़ रु.

32,276 करोड़ रु.
दिल्ली में जनरल पूल की सात आवासीय कॉलोनियों का पुनर्विकास

15,000 करोड़ रु.
घिटोरनी (दिल्ली) में 240 एकड़ में आवासीय/कमर्शियल इकाइयों का विकास

हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की संपत्तियां

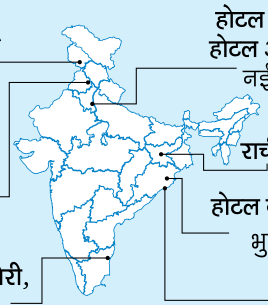
होटल जम्मू अशोक, जम्मू
होटल आनंदपुर साहिब, रूपनगर
होटल पांडिचेरी, पुदुच्चेरी
होटल सम्राट, होटल अशोक, नई दिल्ली
होटल राची, राची
होटल कलिंग, भुवनेश्वर
होटल नीलाचल, पुरी

स्रोतः नीति आयोग

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

लक्ष्य हासिल करना आसान होगा. उसने निजीकरण के उस भारी विरोध को भी दरकिनार कर दिया, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों से राजस्व उगाहने की पिछली कोशिशों को पलीता लगाया था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को केंद्र की राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) लॉन्च करने का ऐलान किया. इसके तहत सरकार का इरादा अगले चार वर्षों में बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं को 15 से 30 साल तक की अवधि के लिए निजी कंपनियों को लीज पर देने का है. बदले में वह 6 लाख करोड़ रु. उगाहने की उम्मीद कर रही है, जो देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट के जोड़ के बराबर है. इससे वह अपनी महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में धन लगा पाएगी, बजट घाटे की भरपाई कर पाएगी और उम्मीद यह है कि निजी क्षेत्र में नई जान फूंक पाएगी. केंद्र को यह उम्मीद भी है कि इस तरह वह अपने उस सुधार एजेंडे को पूरा नहीं कर पाने की आलोचनाओं से भी पिंड छुड़ा लेगा, जिसका मकसद सरकारी प्रबंधन के नाकारापन की वजह से अपनी क्षमता से कमतर प्रदर्शन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को नई जिंदगी देना था. इससे उसे पिछली यूपीए सरकार के उस पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल की खामियों को दुरुस्त करने का भी मौका मिलेगा, जिसका खाका 2015 में विजय केलकर समिति की सिफारिशों में पेश किया गया था.

तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहते हैं कि सरकार को मॉनिटाइजेशन और निजीकरण दोनों की पहल करनी चाहिए ''क्योंकि हमें नहीं पता कि बेहतर क्या है.'' निजीकरण को लोगों के गले उतारना ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें जमीन सरीखी सरकारी संपत्तियों की मिल्कियत छोड़नी पड़ती है, जबकि 30 साल की लीज को सही ठहराना ज्यादा आसान है. एनएमपी तैयार करने वाला नीति आयोग यह भी बताता है कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में टोल रोड, बंदरगाहों और हवाई अड्डों सरीखी मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में संस्थागत निवेशकों और फंडों के निवेश का इतिहास रहा है. अभी कुछ वक्त पहले ऐसे निवेश एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भी हुए हैं.

केंद्र की संपत्ति मौद्रीकरण योजना के तहत सड़क, रेलवे, बिजली पारेषण, विमानन और बंदरगाह सहित 13 क्षेत्रों की पहचान (देखें *फेहरिस्त में क्या-क्या*) की गई है, जिनकी संपत्तियां निजी क्षेत्र को लीज पर दी जाएंगी. ये प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की प्रक्रिया के तहत दी जाएंगी, और मिल्कियत सरकार के पास रहेगी. एनएमपी का लक्ष्य करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए सड़क परियोजनाओं से, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे से, 45,000 करोड़ रुपए बिजली पारेषण से, 40,000 करोड़ रुपए बिजली उत्पादन से और इसी तरह अन्य परियोजनाओं के मॉनिटाइजेशन से हासिल करना है. इसमें 27,000 किमी सड़कें, 25 हवाई अड्डे और 21 लाख टन क्षमता के गोदाम तथा अन्य शामिल हैं.

सरकार की पेशकश ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की है. मतलब जो पूरी हो चुकी हैं और सुचारु ढंग से काम कर रही हैं. सीतारमण ने कहा, ''एनएमपी (में केवल वही) परियोजनाएं (हैं), जिनमें निवेश हो चुका है, जिनमें संपत्तियां तैयार हो चुकी हैं, जो या तो धूल खा रही हैं, पूरी तरह मॉनिटाइज नहीं की जा सकी हैं या जिनका इस्तेमाल कम हुआ है. निजी भागीदारी लाकर हम (इन्हें) बेहतर मॉनिटाइज कर पाएंगे और इन्फ्रास्ट्रक्चर में आगे भी निवेश पक्का कर पाएंगे.'' कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी नीलेश शाह कहते हैं कि एनएमपी 'गेमचेंजर' है. हालांकि वे जोर देकर यह भी कहते हैं कि इस पर अमल बेहद अहम है, खासकर ''विनिवेश की नाकामियों से सीखना होगा.''

संपत्तियों का मॉनिटाइजेशन कोई नया विचार नहीं है. पिछली सरकारें और कुछ हद तक मौजूदा सरकार भी पहले इसे लागू कर चुकी है. विशालकाय वैश्विक वित्तीय समूह मैक्वायरी ने 2018 में 9,681.5 करोड़ रुपए की बोली से टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल के तहत एनएचएआइ (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के मातहत सड़कों की नौ पट्टियों के संचालन का अधिकार हासिल किया था. 2004 में टोल अधिकार हासिल करके 15 साल तक मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का संचालन करने के बाद आइआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने पिछले साल महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को 6,500 करोड़ रुपए चुकाकर टीओटी के तहत 30 साल के लिए टोल वसूलने का अधिकार प्राप्त किया. मार्च में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एनएचएआइ की योजना अगले पांच साल

में टीओटी के तहत 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की है. इसी तरह कई हवाई अड्डे मौजूदा मॉनिटाइजेशन प्रक्रिया में कामयाब रहे हैं.

मोदी सरकार की योजना जिस मायने में नई जमीन तोड़ती है, वह है इसका पैमाना. पहचान की गई संपत्तियां 12 मंत्रालयों और महकमों से जुड़े क्षेत्रों की हैं और इनमें 20 श्रेणियों की संपत्तियां हैं. क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी कहते हैं, “मौद्रीकरण योजना जरा महत्वाकांक्षी मालूम देती है. इसे कामयाब बनाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा.” तो भी यह आकर्षक विकल्प नजर आता है. पहले तो निवेशक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े निर्माण में देरी सरीखे वित्तीय जोखिमों से बच जाएंगे, वहीं सरकार देश की संपत्तियां बेचने के आरोप से बच जाएगी. जोशी कहते हैं, “यह (निजीकरण के मुकाबले) ज्यादा खुशगवार समाधान मालूम देता है.” दूसरे, ये संपत्तियां बाकायदे मौजूद हैं और निजी क्षेत्र को दक्षता से बस इनका संचालन भर करना है, जबकि सरकार को और ज्यादा बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए पैसा मिल जाएगा. सरकार ने 2024-25 तक 111 लाख करोड़ रुपए के खर्च वाली राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआइपी) से लेकर पीएम गतिशक्ति योजना—जिसकी घोषणा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने की और जिसमें 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च शामिल बताया जाता है—तक कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का ऐलान किया है. जोशी कहते हैं, “हमें देखना होगा कि सरकार इसे कैसे पूरा करती है. पिछला अनुभव उत्साहवर्धक दिखाई देता है.” केंद्र को उम्मीद है कि वह संपत्तियों के मॉनिटाइजेशन से एनआइपी की 14 फीसद लागत जुटा लेगा. वह लंबे वक्त की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में पैसा लगाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी से विकास वित्त की एक संस्था भी बना रहा है.

केंद्र ने राज्यों को पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के बदले प्रोत्साहन लाभ देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए रखे हैं. अगर कोई राज्य अपनी पूरी हिस्सेदारी छोड़ देता है, तो केंद्र विनिवेश मूल्य के बराबर रकम देगा. अगर राज्य पीएसयू को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करता है, तो केंद्र उसे इससे जुटाए गए धन का 50 फीसद देगा. अगर राज्य परिसंपत्ति का मौद्रीकरण करता है, तो उसे उगाहे गए धन का 33 फीसद मिलेगा.

परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के कई अलग-अलग मॉडल पर काम चल रहा है. इनमें टीओटी मॉडल, ओएमटी (ऑपरेट-मेनटेन-ट्रांसफर) रियायतें, इन्फ्रास्ट्रक्चर/रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और अन्य हैं. नीति आयोग का कहना है परिसंपत्ति, लक्षित निवेशक, परियोजना का दायरा और जोखिम में साझेदारी की सीमा पर यह निर्भर करेगा कि आखिर कौन-सा मॉडल इस्तेमाल किया जाए. कामकाज के सुस्पष्ट मानदंडों के साथ अनुबंध के साफ और दोटूक ढांचे के तहत सुव्यवस्थित भागीदारियों के जरिए योजना लागू की जाएगी. नीति आयोग ने अमल का जो खाका बनाया है, उसमें मंत्रालयों के सालाना लक्ष्य, सलाहकारों को साथ लेना और ‘वैकल्पिक/ताकतवर’ तंत्र के जरिए मंजूरियों को आसान और कारगर बनाना भी है.

एनएमपी कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्सुक एक निवेश फर्म के बड़े एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि सड़क और रेल परियोजनाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखती है. सड़कें, रेलवे और बिजली मिलकर कुल एनएमपी के करीब 65 फीसद हैं. इन तीन क्षेत्रों में कार्यक्रम जैसे आगे बढ़ेगा, उसी से अन्य क्षेत्रों के लिए रुझान तय हो सकेगा. हवाई अड्डों और सड़कों के मामले में तो कुछ समझ है कि चीजें किस तरह हो सकती हैं, पर रेलवे काफी हद तक नई शै है. आम जन की भलाई और मुनाफे के बीच संतुलन कैसे साधा जाता है, इसको लेकर भी सवाल हैं.

केयर रेटिंग्ज के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस कहते हैं, “एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसी परिसंपत्तियों के लिए कितनी भूख है. फिर, जहां परिसंपत्ति पर मालिकाना हक पीएसयू का है, राजस्व उस पीएसयू को जाएगा, सरकार को नहीं.” जो भी हो, कुछ लोगों का कहना है कि विचार के स्तर पर यह कदम रोमांचक है. वे आइपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) बाजार में मौजूद जबरदस्त फंडिंग की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि बीमा कंपनियों और पेंशन फंड सरीखे निवेशक लंबे वक्त के ऐसे निवेशों की तलाश में हैं जो उन्हें स्थिर सालाना रिटर्न दे सकें. उम्मीद की दूसरी वजह है वैश्विक वित्तीय बाजारों में इन दिनों मौजूद जबरदस्त फंडिंग. पूर्व वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा बताते हैं कि

> **“एनएमपी बेशक गेमचेंजर है लेकिन हमें विनिवेश में मिली नाकामियों को भूलना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सबक लेना चाहिए”**
>
> **नीलेश शाह**
>
> *एमडी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी*

कहीं तो कुछ कम है

मोदी सरकार 2014-15 से 2020-21 के बीच विनिवेश के अपने महत्वाकांक्षी किस्म के लक्ष्यों को हासिल कर पाने में बार-बार नाकाम रही है

6.57
लाख करोड़ रु.
इतना धन उगाह लेने की उम्मीद थी मोदी सरकार को 2021-15 से 2020-21 के बीच

2.1
लाख करोड़ रु.
केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इतना धन तो वह 2020-21 में ही विनिवेश के जरिए उगाह लेगी

4.04
लाख करोड़ रु.
इतना ही जुटा पाने में कामयाब रही मोदी सरकार

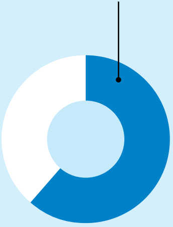

21,000
करोड़ रु.
वह इस वित्तीय वर्ष में अब तक जुटा पाने में कामयाब रही है

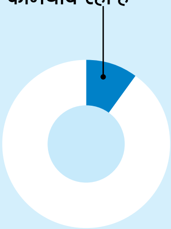

केंद्र ने तय कर लिया है विनिवेश का अपना जो लक्ष्य

एयर इंडिया
केंद्र सरकार ने बोली लगाने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय कर रखी थी; अब टाटा समूह और स्पाइसजेट को इसे खरीदने की रेस में बताया जा रहा है

वे फर्म जिनके विनिवेश की 2021-22 में योजना बनी है

- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
- भारतीय नौवहन निगम
- भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
- आइडीबीआइ बैंक
- पवन हंस
- नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

इनके अलावा, सरकार ने 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव दिया है

आइपीओ लाने की तैयारी

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) इस वित्तीय वर्ष में अपने 5-10 प्रतिशत शेयर के लिए आइपीओ लाने की योजना बना रहा है और इस मकसद से एक निवेश बैंकर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है

- केंद्र ने नेशनल फर्टिलाइजर्स, मिश्र धातु निगम और राष्ट्रीय केमिकल्स ऐंड फर्टिलाइजर्स में अपनी 10-20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है

स्रोतः सरकारी आंकड़े, मीडिया रिपोर्ट्स

वैश्विक वित्तीय बाजारों में फिलहाल 18 ट्रिलियन डॉलर की प्रचुर धनराशि है. ऐसे में भारतीय कंपनियों के सामने यह विकल्प है कि वे इस फंडिंग को अपने खातों में कर्ज की तरह लें और कम जोखिम वाली एनएमपी परियोजनाओं में लगा दें. आरबीआइ (भारतीय रिजर्व बैंक) के एक बड़े अफसर कहते हैं, ''बाजार में तरलता की कोई कमी नहीं है. तमाम वित्तीय संस्थाएं कारगर परियोजनाएं चाहती हैं. एनएमपी उन्हें यही देगा.''

सत्तारूढ़ भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि उसकी संपत्ति मौद्रीकरण योजना को उसकी वैचारिक मातृ संस्था आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) का समर्थन मिल गया है. आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के कई लोगों का कहना है कि सरकार को संपत्ति मौद्रीकरण योजना का पारदर्शी और खरा होना पक्का करना चाहिए और यह भी कि सही मूल्य निर्धारण हो. अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में और मोदी के पहले कार्यकाल में भी इस मंच ने निजीकरण की कोशिशों का विरोध किया था. आरएसएस के शीर्ष नेता बताते हैं कि वे सार्वजनिक क्षेत्र में निजी पूंजी के खिलाफ नहीं हैं, वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक बिक्री के खिलाफ हैं. एक नेता ने कहा, ''यही रुख जारी है.'' एसजेएम के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन कहते हैं कि निजी क्षेत्र की फर्म अगर सार्वजनिक संपत्तियों में निवेश करने को उत्सुक हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, पर रणनीतिक बिक्री ''राजनैतिक और कारोबार दोनों के लिहाज से बुरी पेशकश है.''

भारत में भीड़ भरी सड़कों और धीमी ट्रेन सेवाओं से लेकर नाकाफी अस्पतालों तक में झलकने वाली बुनियादी ढांचे की कमी आर्थिक वृद्धि और नौकरियों के सृजन में भारी अड़चनें पैदा करती है. केलकर समिति की रिपोर्ट कहती है कि कम उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा की दयनीय क्षमता, ऊंची लागतें और शहरीकरण की सुस्त रफ्तार इसके कुछ नतीजे हैं. यहीं निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना बेहद अहम हो जाता है. मगर जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मिलकर काम करने की बात आती है, तब भारत का रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा मिला-जुला ही रहा है.

पीपीपी मॉडल 21वीं सदी के पहले दशक में विकास का सबसे पंसदीदा मॉडल बनकर

Framework for Monetisation of Core Infra Assets

चंद्रदीप कुमार

> ''निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित कर हम संपत्तियों को बेहतर ढंग से मॉनेटाइज कर पाएंगे और बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश को पक्का कर पाएंगे''
>
> **निर्मला सीतारमण**
> *केंद्रीय वित्त मंत्री*

उभरा. भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बरास्ते पीपीपी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की बहार आ गई. अलबत्ता उनमें से कई जमीन अधिग्रहण और मंजूरियों में देरी में फंसकर रह गईं और पर्याप्त तत्परता न बरते जाने की वजह से कई डूबत खाते के कर्ज बन गए. एक सरकार की मंजूर परियोजनाओं को अगली सरकार ने रद्द कर दिया. बुनियादी ढांचा मुहैया नहीं करवाया गया. मसलन, अडानी ग्रुप ने अपने बंदरगाहों में सुचारु कामकाज के लिए खुद अपनी रेललाइन बिछाईं, पर दूसरे डेवलपरों के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी. जीएमआर और जीवीके सरीखी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां दिवालिया हो गईं, जिसके पीछे एयरपोर्ट फीस न बढ़ा पाना, जमीन अधिग्रहण न कर पाना और ऐसी ही कई दूसरी वजहें थीं. मगर विश्लेषकों का कहना है कि इस बार जोखिम खासे कम हो गए हैं. फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन विनायक चटर्जी बताते हैं, ''बुनियादी ढांचे के मौद्रीकरण में, जो मोटे तौर पर एनएमपी का कुल जमा मतलब है, तीन किस्म के जोखिम हैं—विकास जोखिम, निर्माण जोखिम और परिचालन जोखिम. निवेशकों की एक पसंदीदा कंपनी अब ब्राउनफील्ड संपत्तियों का अधिग्रहण कर रही है, क्योंकि इसमें जोखिम शृंखला की पहली दो कड़ियां हट गई हैं.'

पीपीपी के जमाने की तबाही की कहानियों के साथ नई दिल्ली के ताज मानसिंह होटल सरीखी कामयाबी की कहानियां भी हैं. इस होटल को टाटा ग्रुप ने दशकों की मेहनत से हॉस्पिटैलिटी आइकन के तौर पर विकसित किया था और शुरुआती लीज खत्म होने पर 2018 में प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए दोबारा लीज हासिल की. (आलोचक हालांकि इसे ऐसा मामला बताते हैं जिसमें कभी सार्वजनिक रही संपत्ति तकरीबन निजी बन गई.) एक और मिसाल वाल स्ट्रीट की बड़ी कंपनी ब्लैकस्टोन है, जिसका कहना है कि प्रतिफल के लिहाज से भारत सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बाजार है—इसका 25 अरब डॉलर का बीज निवेश अब 50 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य का हो गया है. इनमें दो रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट हैं जो आमदनी देने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के मालिक, संचालक या वित्तपोषक हैं और ये इसे ऑफिस रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक और खुदरा तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का अगुआ खिलाड़ी बनाते हैं.

अलबत्ता, जहां एनएमपी की कामयाबी इसके अमल में है, वहीं अहम चुनौतियों से भी पार पाना होगा. और इनमें शामिल हैं:

संपत्ति का मूल्य निर्धारण: यह अहम मुद्दा है. परियोजना का वास्तविक मूल्य कैसे तय किया जाए? इसे उसके मौजूदा मूल्य से आंका जाए या उसके भावी संभावित मूल्य से? यही नहीं, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को मुनाफा देने में कई साल लगते हैं, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने की गरज से परिसंपत्ति मौद्रीकरण अनुबंधों की आयु या जीवनकाल को लचीला रखने की

कैसे तय हो संपत्तियों का मूल्य

परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारण कई तरह से किया जा सकता है. इसमें बराबर की कीमत वाली दूसरी परिसंपत्तियों के लेनदेन के साथ तुलना से लेकर किसी परिसंपत्ति को अपग्रेड करने के लिए जरूरी अनुमानित निवेश तक के तरीके शामिल हैं

सीधी बाजार दरः इस प्रणाली में इसी के बराबर की संपत्ति के हाल के बाजार लेनदेन के आधार पर किसी संपत्ति की कीमत का अनुमान लगाया जाता है. मिसाल के तौर पर, राजमार्ग के एक खंड का मूल्य निकालने के लिए कोई किसी अन्य सड़क मार्ग के प्रति किलोमीटर लागत के हिसाब से मूल्य पर विचार कर सकता है. दूसरे पहलू, मसलन भुगतान शर्तें और प्राप्त बोलियां भी एक भूमिका निभाती हैं.

कैपेक्स लागतः कई संपत्तियों को उत्पादन में सुधार या उन्हें मुनाफा देने लायक बनाने के लिए महत्वपूर्ण पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) की आवश्यकता होती है. ऐसे मामलों में आवश्यक निवेश का आकार एक संदर्भ बिंदु बन जाता है. इस निवेश की समयावधि भी एक भूमिका निभाती है. उसी तरह अनुबंध की शर्तें, जैसे मुनाफे का बंटवारा, रियायत शुल्क, प्रीमियम और बाकी पहलुओं की भी भूमिका होती है.

बैलेंस शीट में कीमतः इस तरीके का उपयोग दो स्थितियों में किया जाता है—जब किसी संपत्ति के बराबर की किसी संपत्ति का बाजार लेनदेन न हुआ हो जिससे कि तुलना करके मूल्य आंका जा सके या फिर उस परिसंपत्ति के लिए अनुमानित पूंजी निवेश का आंकड़ा भी उपलब्ध न हो. यह मूल्यांकन एक समान परिसंपत्ति के निर्माण के लिए जरूरी औसत निवेश पर भी विचार करता है, जिसमें मौजूदा संपत्ति की आयु, उसके परिचालन की अवधि आदि के लिए समायोजन भी किया जाता है.

उद्यम मूल्यः इस तरकीब का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति के मौजूदा राजस्व स्रोतों का आंकड़ा उपलब्ध होता है, या फिर जब प्रचलित टैरिफ/अन्य धारणाओं के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है. मौद्रीकरण (मोनेटाइजेशन) मूल्य प्राप्त करने के लिए डिस्काउंटेड कैशफ्लो के शुद्ध वर्तमान मूल्य का आंकलन किया जाता है. लेकिन यह सिर्फ एक सांकेतिक आंकड़ा होता है.

स्रोतः नीति आयोग

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पीपीपी प्रोजेक्ट

सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी भारत में कोई नई बात नहीं है

प्रोजेक्ट जो हो चुके पूरे # **1,115**

कुल निवेश # **20 लाख करोड़ रु.**

सबसे बड़ी परियोजनाएं

परियोजना का नाम	साल	निवेश *
मुंदड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट	2008	31,080
ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट	2009	29,495
जिंदल तमनार पॉवर प्लांट फेज1 और 2	2007	29,471
मुंदड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	2006	29,371
कृष्णपत्तनम अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट	2010	28,312
एलऐंडटी हैदराबाद मेट्रो रेल प्राइवेट लिमिटेड	2011	26,932
केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	2010	26,161
जीएमआर किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस वे लि.	2012	25,016
एनटीपीसी लिमिटेड	2004	22,170
ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2011	18,653

#1990 से; *आंकड़े करोड़ रु. में; स्रोतः पीपीपी नॉलेज लैब

जरूरत है. नीति आयोग ने परियोजनाओं का मूल्य तय करने के कई तरीके प्रस्तावित किए हैं (देखें: कैसे तय हो संपत्तियों का मूल्य). इन अनुबंधों को कैसे गढ़ा जाता है, उससे भी मूल्य निर्धारित होगा. मसलन, सरकार खेल के अलावा दूसरे जमावड़ों के लिए स्टेडियमों के इस्तेमाल की इजाजत देकर उनमें निवेश को ज्यादा आकर्षक बना सकती है. एक स्वतंत्र नियामक होगा या नहीं, इस पर भी स्पष्टता जरूरी है, क्योंकि निवेशक 'कमान और कंट्रोल' वाला या नीति में रातोरात बदलाव वाला माहौल कतई नहीं चाहेंगे. समूची व्यवस्था को पारदर्शी और लाभदायक होना ही नहीं बल्कि दिखना भी होगा.

अतीत की नाकामियां: इसी से जुड़ी एक और कोशिश—विनिवेश—में सरकार लक्ष्य पूरे करने में बार-बार नाकाम हुई है. 2014-15 और 2020-21 के बीच मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया से 6.57 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, मगर वह 4.04 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 60 फीसद ही जुटा सकी. 2020-21 में केंद्र ने 2.1 लाख करोड़ उगाहने की उम्मीद की और महज 21,000 करोड़ रुपए उगाह पाई, बावजूद इसके कि उस वित्तीय साल के दूसरे आधे हिस्से में ज्यादातर समय शेयर बाजार उछाल से चहक रहे थे. 2021-22 के लिए केंद्र ने पीएसयू के विनिवेश, निजीकरण और संपत्ति मौद्रीकरण से 1.75 लाख करोड़ रु. जुटाने का लक्ष्य रखा, पर अभी तक किसी भी संपत्ति का निजीकरण मुश्किल से ही हो पाया है. बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरीखी फर्मों का विनिवेश अभी फलीभूत होना है. सरकार ने 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का भी प्रस्ताव रखा था, पर अभी प्रगति सुस्त ही है. इसे देखते हुए फिक्र यह है कि कहीं संपत्ति मौद्रीकरण यानी एसेट मॉनिटाइजेशन का हश्र भी यही तो नहीं होगा.

एकाधिकार को रोकना: कइयों को फिक्र है कि संपत्ति मौद्रीकरण एकाधिकारों का निर्माण कर सकता है, जिससे क्रोनीइज्म यानी चहेतों के साम्राज्य फलेंगे-फूलेंगे. अभी हाल ही हुई हवाई अड्डों की नीलामी एक ही संचालक—अडानी ग्रुप—के हाथ में गई, इससे यह तर्क मजबूत ही हुआ. (अडानी ग्रुप भारत में सबसे ज्यादा सात हवाई अड्डों का अकेला संचालक है.) हालांकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कहते हैं कि एनएमपी की प्रक्रिया पारदर्शी होगी. वे कहते हैं, ''यह सब पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के तहत है.'' चटर्जी की राय है कि अगर पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएं हैं तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सरीखे नियामकों को इनकी जांच-पड़ताल करनी चाहिए. एकाधिकारों को रोकने के लिए अनुबंधों में धाराएं जोड़ी जा सकती हैं. मसलन, अगर किसी एक क्षेत्र में छह परियोजनाओं का मौद्रीकरण होना है, तो एक ही बोली लगाने वाले के एक या दो से ज्यादा परियोजनाओं के अधिकार हासिल करने पर पाबंदी की धारा जोड़ी जा सकती है.

सुस्पष्ट रुख और पर्याप्त जांच-पड़ताल: बेंगलूरू स्थित डॉ. बी.आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स युनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर प्रो. एन.आर. भानुमूर्ति कहते हैं, ''मोटे तौर पर मैं सरकारी परिसंपत्तियां निजी क्षेत्र को देने के फलसफे का समर्थक हूं. एनएमपी कार्य कुशलता का मुद्दा हल करेगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के मुकाबले नाकाम रहा है.'' भारतीय रेल नेटवर्क पर ट्रेन मार्गों के निजीकरण की हालिया कोशिश से सबक सीखने की जरूरत है. शुरुआत में हालांकि दर्जन भर दावेदार

> **“एसेट मॉनिटाइजेशन का विकास और रोजगार सृजन के मामले में कई स्तरों पर असर पड़ने वाला है”**
>
> **अमिताभ कांत**
> *सीईओ, नीति आयोग*

कुछ देशों ने किस तरह से किया अपनी संपत्तियों का मौद्रीकरण

ऑस्ट्रेलिया: अपने 2014-15 के बजट में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पैकेज (बुनियादी ढांचा विकास पैकेज) की घोषणा की, जो बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक 10-वर्षीय योजना है. एक प्रमुख घटक एसेट रिसाइक्लिंग इनिशिएटिव (एआरआइ) था. इसका मकसद था राज्यों को परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग के लिए प्रोत्साहित करना, निजी कंपनियों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में पूंजी लगाने और चलाने के लिए प्रोत्साहित करके उससे प्राप्त आय का उपयोग नए बुनियादी ढांचे के लिए करना. 2018 तक 12 प्रमुख सार्वजनिक संपत्तियां एआरआइ के दायरे में लाई गईं. इसमें भाग लेने वाले राज्यों और क्षेत्रों को प्रोत्साहन भुगतान के रूप में लगभग 3 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भुगतान किया गया. इसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में नए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 17 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक का प्रबंध करने में मदद की.

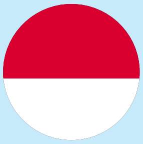

इंडोनेशिया: फरवरी 2020 में इंडोनेशिया ने अपनी सीमित रियायत अधिकार योजना लागू की, जिसमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाता है. इसके तहत निजी फर्मों को मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संचालन, रखरखाव और विस्तार के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिसके बदले उन्हें सरकार एक अग्रिम रियायत शुल्क देगी या मिले पैसे को साझा करेगी. सरकार को इससे जो राजस्व हासिल होगा वह उसे अपने बड़े बुनियादी ढांचा कार्यक्रम को पूरा करने में सक्षम बनाएगा, जिनमें ट्रांस-सुमात्रा राजमार्ग जैसी परियोजनाएं और कम विकसित क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं.

अमेरिका: 2005-06 में शिकागो स्काइवे को ओहायो टर्नपाइक से जोड़ने वाली 157 मील लंबी इंडियाना ईस्ट वेस्ट टोल रोड का मौद्रीकरण किया गया था ताकि पूरे राज्य में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 10 वर्षीय योजना को धन उपलब्ध कराया जा सके. परियोजना में सड़क के प्रबंधन और संचालन के लिए 75 साल की रियायत का प्रावधान किया गया था और एक प्राप्त अग्रिम राशि के एवज में मोटर चालकों से टोल एकत्र करने की अनुमति दी गई थी. सड़क पर स्वामित्व सरकार का ही रहेगा.

थे पर केवल दो ने बोली लगाई. राजस्व में साझेदारी और मार्गों के मामले में लचीलेपन के अलावा नियामक का न होना और ढुलाई के शुल्कों का भुगतान जैसी वजहों से बोली लगाने वाले छिटक गए.

लाल फीते की कतरब्योंत: निवेशकों को जरूरी मंजूरियां लेने के लिए बरसों लटकाया जाएगा तो परिसंपत्ति का मूल्य मिट्टी में मिल जाएगा. दिलचस्पी जगाने के लिए परिसंपत्ति को टुकड़ों में भी बांटना पड़ सकता है. एक निवेश बैंकर कहते हैं कि बीपीसीए का विनिवेश इसलिए धीमा रहा क्योंकि फर्म के रिफाइनरी कारोबार में दिलचस्पी रखने वाला निवेशक हो सकता है कंपनी की भारी-भरकम रियल एस्टेट संपत्तियां लेने का इच्छुक न रहा हो. विवाद समाधान तंत्र दूसरी चुनौती हो सकती है. भारत को अनुबंध प्रवर्तन में अभी बहुत काम करना है. इसी तरह, बिजली क्षेत्र में शुल्क नियम-कायदों के अधीन हैं, जिससे निवेशकों का उत्साह फीका पड़ सकता है. शाह एनएमपी की साज-संभाल के लिए टुमासेक होलडिंग्ज, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, सरीखी कंपनी के गठन का सुझाव देते हैं. दूसरों का कहना है कि एनएमपी के विशाल पैमाने के चलते इसे कामयाब बनाने के लिए भारत को भारी बौद्धिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2014 के अपने बजट में 500 करोड़ रुपए के कोष से पीपीपी थिंक टैंक—3पी इंडिया—बनाने का ऐलान किया था. यह अब तक नहीं बना.

परिसंपत्ति का मूल्य ह्रास: दूसरी चिंता की बात यह पक्का करना है कि सरकार को लौटाए जाते वक्त परिसंपत्तियां उतनी ही कीमती हों जितनी वे लीज पर दिए जाते वक्त थीं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में कहा, ''जब वित्त मंत्री कहती हैं कि हम मालिक हैं और संपत्ति हमें लौटा दी जाएगी, तब वे किस संपत्ति की और किस रूप में उसकी बात कर रही हैं?'' उनका प्रस्ताव है कि संपत्तियों का अवमूल्यन एक मूल्य ह्रास आरक्षित कोष में जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल संपत्ति को अच्छी हालत में रखने में हो.

सार्वजनिक संपत्ति पर तंग नजरिया: शेल इंडिया के पूर्व चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता कहते हैं कि उन्हें चिंता यह है कि एनएमपी मॉडल सार्वजनिक उपयोगिता संपत्तियों को वित्त या रोकड़े के संकीर्ण चश्मे से देखता है और जनकल्याण में उनके संभावित योगदान को कम करके आंकता है. नीति आयोग के मुताबिक, कोई सार्वजनिक संपत्ति मॉनिटाइजेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह इससे तय होता है कि वह सक्रिय और बेहतर इस्तेमाल की संभावना के साथ राजस्व देने वाली है या नहीं. अगर ऐसा है, तो मौद्रीकरण के लिए उस पर विचार किया जा सकता है.

मेहता ने 6 सितंबर को एक लेख में लिखा, ''मुझे चिंता है कि यह मॉडल लगता है सरकार को इन संपत्तियों की स्वाभाविक सामाजिक अहमियत को बाहर लाने की जिम्मेदारी से मुक्त करता है.'' मगर कांत कहते हैं कि केंद्र ने निजी क्षेत्र के सलाहकारों को लेकर एक पीपीपी प्रकोष्ठ बनाया है, जो एनएमपी पर अमल के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. वे यह भी कहते हैं कि सालाना लक्ष्यों के साथ परियोजनाओं की कड़ी निगरानी की जाएगी. इससे सरकार के मौद्रीकरण लक्ष्यों और जनकल्याण के उद्देश्यों के बीच संतुलन साध पाने की भी उम्मीद है.

कुल मिलाकर, संपत्ति मौद्रीकरण निजी क्षेत्र को साथ लाने के लिए सरकार का जबरदस्त फैसला है. अगर इसे अच्छे से लागू किया जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कई गुना असर हो सकता है. सरकार आज जिन हालात से गुजर रही है, उनको देखते हुए उसके पास कम ही दूसरे विकल्प बचे थे. ऐसे में इस कोशिश को कामयाब बनाना बेहद जरूरी है.

—साथ में **अनिलेश महाजन**

देश का नं. 1
हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

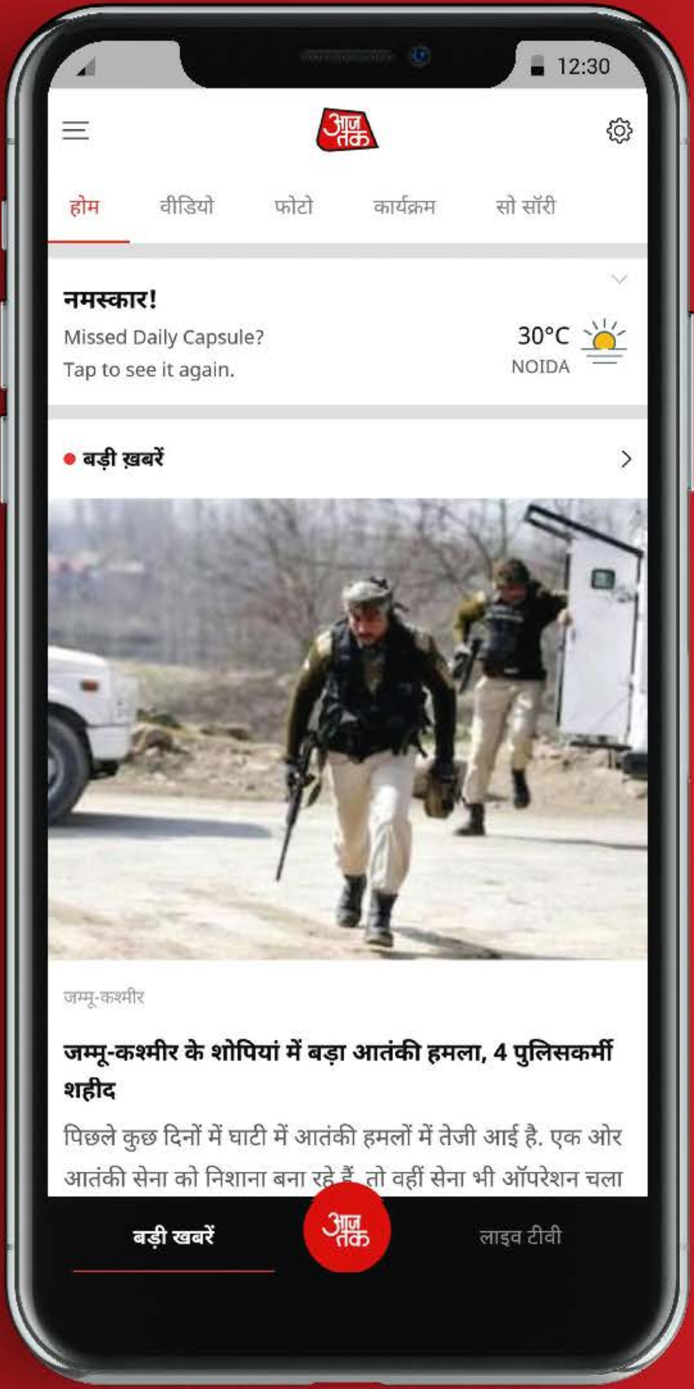

12:30

होम वीडियो फोटो कार्यक्रम सो सॉरी

नमस्कार!
Missed Daily Capsule?
Tap to see it again.
30°C
NOIDA

● **बड़ी ख़बरें**

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बड़ा आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मी शहीद

पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकी हमलों में तेजी आई है. एक ओर आतंकी सेना को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सेना भी ऑपरेशन चला

बड़ी खबरें
लाइव टीवी

MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम
मानानीय मुख्यमंत्री, बिहार
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार
माननीया उप मुख्यमंत्री, बिहार
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
21 फरवरी, 2021
तारकिशोर प्रसाद
नीतीश कुमार

अगल-बगल पटना में एक कल्याण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान उप-मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

एएनआइ

प्रदेश | बिहार/भाजपा

दो नायबों की दास्तान

उत्साह से भरी भाजपा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 'आत्मनिर्भर' योजना तैयार की है. दो वर्तमान उप-मुख्यमंत्री इसके लिए मंच तैयार कर रहे

अमिताभ श्रीवास्तव

तारकिशोर प्रसाद फोन रिसीवर उठाते हैं और कहते हैं, ''डीएम साहब, मैं आपके पास किसी को भेज रहा हूं. उसकी समस्या का समाधान करें और काम हो जाने के बाद मुझे सूचित करें.'' उसके बाद, स्वभाव से मृदुभाषी और मिलनसार तारकिशोर प्रसाद जिन्हें उनसे मिलने वाले सभी लोग प्यार से तारकिशोर भैया कहते हैं, उस बातचीत में थोड़ी नरमी वाले शब्द जोड़ते हैं, ''गरीब की मदद प्रायोरिटी (प्राथमिकता) से होनी चाहिए. याद रखें, अब वो पुराने दिन नहीं रहे. ''

'पुराने दिन' से उनका क्या आशय था, भाजपा के 65 वर्षीय नेता और बिहार के उप-मुख्यमंत्री इसे खुलकर तो नहीं बताते लेकिन अराजकता के दौर की डरावनी यादों से लेकर बाद के दौर की भी बहुत सी बातों तक, बिहार में इस वाक्य के कई मतलब लगाए जाते हैं. लेकिन कमरे में बैठा हर कोई यह समझ रहा था कि वास्तव में उनका क्या आशय है—भाजपा के नेताओं को अब सरकारी अधिकारी हल्के में नहीं ले सकते हैं.

नीतीश कुमार के शासनकाल में एक आम धारणा यह रही है कि नौकरशाही बस मुख्यमंत्री की बात सुनती है—महत्वपूर्ण गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अब भी उन्हीं ही पास है—और उनके

इंडिया टुडे

देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

यूपी की धान खरीद व्यवस्था में कई छेद
लालफीताशाही के शिकंजे में कारोबार
सरना: पुराने धर्म पर नई बहस
इंडिया टुडे
कोविड-19 वैक्सीन
कितनी सुरक्षित? कितनी कारगर?
बाजार में आने के लिए तैयार नई वैक्सीन से जुड़े सारे अहम सवालों के जवाब

राम मंदिर को माना गया मोदी की प्रमुख उपलब्धि
अनुच्छेद 370 हटाने को मिला जोरदार समर्थन
बेरोजगारी मानी गई सबसे बड़ी समस्या
इंडिया टुडे
देश का मिज़ाज सर्वेक्षण
मोदी और हिंदुत्व का बोलबाला
देशव्यापी छमाही सर्वेक्षण से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं और संघ परिवार के एजेंडे को मिली जबरदस्त बढ़त

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या......................है और इसे दिनांक................ को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में .... (बैंक का नाम)......................रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम.. पता...

.... शहर...................... राज्य...................... पिन......................

मोबाइल... ईमेल...

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

☎ **हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें**
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

अलावा कुछ शक्तिशाली मंत्रियों की. लेकिन बिहार विधानसभा और कैबिनेट में अब भाजपा की बढ़ी ताकत को देखते हुए, 'पुराने दिन' धीरे-धीरे अतीत की बात होते जा रहे हैं. इस बीच, उत्तर बिहार के किसी जिले से आया वह परेशान शख्स उप-मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहकर डीएम के लिए एक चिट लेकर जा चुका है, और तारकिशोर अगले शिकायतकर्ता से मिल रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने साप्ताहिक जनता दरबार में हैं, और अब भी 250 से अधिक लोग उनसे फरियाद के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

उप-मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, भाजपा के ये तीनों नेता एक साथ मिलकर जातीय पहचान के आधार पर बिहार के लगभग 20 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं

सोनू किशन

दो उप-मुख्यमंत्री पर दांव

कटिहार से चौथी बार विधायक तारकिशोर प्रसाद कभी चुनाव नहीं हारे. वे नई विधानसभा के चुनाव के बाद नवंबर 2020 में भाजपा की ओर से चुने गए दो उप-मुख्यमंत्रियों में से एक हैं. पार्टी नेतृत्व ने बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी को राज्यसभा भेज दिया और नीतीश कुमार सरकार में दो नए उप-मुख्यमंत्री बनाए. बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है.

62 वर्षीया रेणु देवी बिहार की दूसरी उप-मुख्यमंत्री हैं. पांच बार की विधायक और पूर्व मंत्री (2008-10) रेणु देवी का ताल्लुक नोनिया जाति से है जो बिहार में एक प्रभावशाली और संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण अत्यंत पिछड़ी जाति है.

लेकिन तारकिशोर, जिनके पास वित्त, वाणिज्यिक कर और शहरी विकास और आवास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, के विपरीत रेणु देवी के पास ज्यादा कुछ नहीं है. उनके पास सिर्फ आपदा प्रबंधन और पिछड़ा वर्ग (बीसी) और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) कल्याण विभाग हैं. बाद के कैबिनेट विस्तार में दो महत्वपूर्ण विभाग, पंचायती राज और उद्योग उनसे वापस ले लिए गए थे.

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने 'नीतीश कुमार मॉडल' को अपनाते हुए रेणु देवी का चयन चुनावी रूप से दो महत्वपूर्ण वर्गों, महिलाओं और ईबीसी को साधने के लिए किया था. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता समझाते हैं, ''रेणु देवी के पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो या सरकार में बहुत दखल भले ही न हो, लेकिन उन्हें उप-मुख्यमंत्री का ओहदा मिला है. वे सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री के बगल में बैठती हैं और इससे लोगों के बीच अच्छा संदेश जाता है कि भाजपा बिहार में ईबीसी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है.''

इसके विपरीत, वैश्य (बनिया) जाति जिसकी राज्य में आबादी करीब 6 से 7 प्रतिशत है, से ताल्लुक रखने वाले तारकिशोर प्रसाद का रुतबा, चाहे वह शासन हो या राजनीति, बहुत बड़ा है. उनके पास सरकार में शामिल रहने का कोई पुराना अनुभव नहीं है. इसके बावजूद, उन्होंने इस साल फरवरी में राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. नौकरशाहों के साथ देर तक बैठने से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश के मन की बात को भांपने और बजट में उनके विचारों को शामिल करने तक, और महिला उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक निगम की स्थापना जैसे कई नवीन विचारों को पेश करने का श्रेय तारकिशोर प्रसाद को दिया जाता है.

तारकिशोर और रेणु देवी के अलावा, भाजपा ने अपने कोटे से पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सवर्ण भूमिहार जाति के विजय सिन्हा को मौका दिया है. तीनों नेता एक साथ मिलकर जातीय पहचान के आधार पर बिहार के लगभग 20 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं.

वर्तमान विधानसभा की स्थिति

कुल विधानसभा सीटें **243***

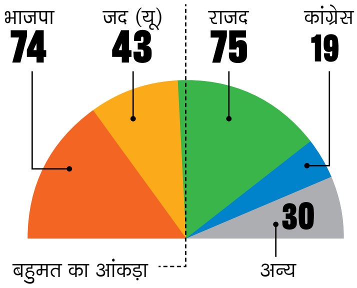

*मौजूदा सदस्यों की संख्याः 241

गुजरात मॉडल

पटना में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि अलग-अलग लोगों के जरिए अलग-अलग हितों पर नजर, बिहार के लिए भाजपा की रणनीति का बस आधा हिस्सा है. वे कहते हैं, ''अभी तक, बिहार एकमात्र प्रमुख राज्य है जहां भाजपा सरकार में तो है लेकिन नेतृत्व नहीं कर रही है. पार्टी की योजना अपने आधार का विस्तार करने, जैसा हमने उत्तर प्रदेश में किया है, और 2025 के विधानसभा चुनावों तक आत्मनिर्भर बनने की है.''

नई भाजपा की खातिर कुछ जमीन तैयार करने के लिए इन तीनों नेताओं को नौ महीने का समय देने के बाद, 'प्लान बिहार' को 18 अगस्त को तब अगले गियर में डाल दिया गया जब भगवा एजेंडे को जोर-शोर से आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात भाजपा के पूर्व संगठन सचिव भीखुभाई दलसानिया को राज्य में अहम जिम्मेदारी सौंपी.

जामनगर के लो-प्रोफाइल आरएसएस प्रचारक दलसानिया, जो नब्बे के दशक के मध्य में भाजपा में शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वासपात्र हैं. उन्होंने अब बिहार भाजपा के संगठन महासचिव के रूप में पदभार संभाला है. दलसानिया का काम यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में भाजपा की सभी राजनैतिक

टी प्रकोष्ठ
वाजपेयी

< **आखिरी जोर** सड़क मंत्री नितिन नवीन के साथ भाजपा के महासचिव भीखुभाई दलसानिया

गतिविधियां केंद्रीय नेतृत्व की जानकारी में रहे. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बेहतर परिणाम हासिल करने के बाद पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाजपा आखिरी जोर लगाने की तैयारी कर रही है और इसमें दलसानिया को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. साल 2020 में पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीतीं जबकि 2015 में इसका स्ट्राइक रेट एक-तिहाई रहा था और वह 157 सीटों पर लड़कर सिर्फ 53 सीटें जीत सकी थी.

भाजपा ने पहले ही लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से प्रमुख प्रतिद्वंद्वी का स्थान हथिया लिया है. और अगर बिहार में राजद के पास मजबूत वोट बैंक है, तो उसके विरोधियों के पास भी अलग-अलग सामाजिक स्तर के मतदाताओं के बीच अपना जनाधार है. भाजपा के एक नेता का कहना है, ''यह वह वोट आधार है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं. हमें राजद का पहला और सबसे पसंदीदा विकल्प बनना है.'' यहां अंदरूनी विरोधाभास यह है कि पार्टी गठबंधन सहयोगी, नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) के वोट आधार में सेंध लगाएगी, जिससे मौजूदा सरकार में दबदबे के लिए आपसी खींचतान और बढ़ सकती है.

लेकिन भाजपा एक दूसरे विकल्प को भी टटोलेगी और वह है तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले राजद के यादव वोट बैंक में सेंध की कोशिश. लेकिन जैसा कि पहले कई लोग महसूस कर चुके हैं, यह बहुत टेढ़ा काम है. दिल्ली में एक भाजपा नेता कहते हैं, ''यादव वोटों को हथियाने के लिए जोर लगाना व्यर्थ है. भाजपा ने उसे लुभाने के लिए कई दांव खेले लेकिन वह लालू यादव के परिवार के साथ मजबूती से बना हुआ है. मौजूदा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जैसे यादव नेता को पेश करने का सबसे अच्छा समय शायद 2015 के विधानसभा चुनावों में था, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 25 प्रतिशत यादवों ने भाजपा को वोट दिया था. लेकिन हम ऐसा करने में नाकाम रहे और लालू यादव ने अपने यादव वोट बैंक को और मजबूत किया. अब सबसे अच्छी रणनीति यह होगी कि हम 'नीतीश मॉडल' को अपना लें, भले ही वह हमारे गठबंधन सहयोगी के लिए नुक्सानदेह ही क्यों न साबित होती हो.''

इन वर्षों में, अगर राजद का दुर्जेय समझा जाने वाला एम-वाइ समीकरण (14 प्रतिशत यादव वोट और 16 प्रतिशत मुस्लिम वोट) भी नीतीश को रोकने में विफल रहा है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री के पास भी ईबीसी और महादलितों का ऐसा ही मजबूत वोट बैंक है. नीतीश ने अपने दम पर अपना मजबूत आधार तैयार किया है, और इस बात की संभावना बहुत कम है कि वे अपने गठबंधन सहयोगी को उन्हीं की चाल से उन्हें ही मात देने देंगे.

एक उच्च नैतिक आधार भी है, जो मुख्यमंत्री नीतीश के पक्ष में काम करेगा. राम मनोहर लोहिया-जयप्रकाश नारायण-कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद की पाठशाला के विद्यार्थी नीतीश, भाजपा की हिंदुत्ववादी विचारधारा को बिहार पर शायद ही हावी होने देंगे. बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर कटाक्ष करने के साथ ही, दोनों सहयोगियों के बीच पहले से ही कड़वाहट दिख रही है. कई लोग इसे नीतीश के धैर्य की परीक्षा लेने की भाजपा की योजना के रूप में देखते हैं. नीतीश ने भले ही पलटवार नहीं किया हो, लेकिन जद (यू) के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार में अपने सहयोगी पर आक्षेप का कोई मौका नहीं छोड़ा है.

भाजपा को मालूम है कि यादव वोटों को पाने की कोशिश करना उसके लिए टेढ़ी खीर है. ऐसे में उसके लिए अगला सबसे बेहतर विकल्प है: नीतीश कुमार के ईबीसी और महादलित आधार में सेंध लगाने की कोशिश करना

लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा है, फिलहाल भाजपा का दारोमदार इसके दो उप-मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन पर टिका है जिन्हें छवि निर्माण और 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में पार्टी का आधार मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. और राज्य में भाजपा की भविष्य की योजनाओं के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है.

अगर रेणु देवी प्रतीकात्मक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, तो तारकिशोर सुशील मोदी के अवतार में अधिक नजर आते हैं लेकिन हिंदुत्व पर थोड़े अधिक बल के साथ. वे 2005 से लगातार अल्पसंख्यक समुदाय की खासी संख्या वाली कटिहार सीट जीत रहे हैं. हालांकि उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि वे अपनी लोकप्रियता और छवि की वजह के साथ धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण चुनाव जीतते रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री समझते हैं कि उन्हें प्रदेश के एक कद्दावर नेता की जगह भरने की जिम्मेदारी दी गई है, और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अपने परिश्रम की बदौलत नीतीश का विश्वास जीत लिया है.

दरअसल, जब जद (यू) के विवादास्पद विधायक गोपाल मंडल ने पिछले महीने तारकिशोर की आलोचना की थी और यह आरोप लगाते हुए उप-मुख्यमंत्री के भागलपुर के दौरों की जांच कराने की मांग की कि ये दौरे 'जबरन वसूली' के लिए थे, तो पार्टी नेतृत्व ने तुरंत ही अपने विधायक को आड़े हाथों लिया. जद (यू) के वरिष्ठ मंत्री और नीतीश के विश्वासपात्र विजय चौधरी ने मंडल को तलब किया और झाड़ लगाई. मंडल ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बयान के लिए खेद व्यक्त किया और स्वीकार किया कि वह 'तारकिशोरजी को बहुत प्यार करते हैं.' बिहार में भगवा विस्तार की योजना के मद्देनजर यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी पार्टी का प्यार, अपने सहयोगी दल के लिए कब तक बना रहता है. ■

बड़ी जिम्मेदारी भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी ओर देखते पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (दाएं)

नंदन दवे

गुजरात का गेमप्लान

गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के पीछे दो मकसद हैं: पाटीदार समुदाय को संतुष्ट करना और भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष से निपटना. क्या नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 2022 के चुनाव से पहले सबको एकजुट रख पाएंगे?

किरण डी. तारे

पहाड़ सी चुनौतियां

पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल के सामने चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल का भारी भरकम लक्ष्य है. उनकी प्रमुख चुनौतियां हैं:

मॉनसून की मार

पिछले हफ्ते भारी बारिश से सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी तबाही हुई है. इसके लिए जल्द राहत पैकेज की घोषणा होनी चाहिए

लंबित कार्य

वित्त और राजस्व सबसे नाकारा विभाग हैं, इन विभागों में करीब 600 फाइलें लंबित पड़ी हैं

हतोत्साहित कार्यकर्ता

पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी से मुलाकात और संपर्क स्थापित करने में नौकरशाही के अड़ंगों से भाजपा कार्यकर्ता निराश हैं

नाराज पाटीदार

समुदाय को आरक्षण देने की मांग को भाजपा की तरफ से दरकिनार करने के कारण प्रभावी पाटीदार समुदाय नाराज है

वरिष्ठ नाराज

कुछ वरिष्ठ नेताओं के रहते भूपेंद्र पटेल को तरजीह दी गई है, इससे पहले दिन से उन पर दबाव रहेगा

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे की घोषणा के अगले दिन 12 सितंबर को जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नया नेता 'चुनने' के लिए गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय 'कमलम' पर इकट्ठा हुए, तो माहौल फीका ही था. दोपहर करीब चार बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर ने रूपाणी के उत्तराधिकारी के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा की तो चकाचौंध से दूर रहने वाले इस विधायक को खोजने के लिए अफरा-तफरी मच गई. हॉल के कोने में अकेले बैठे पटेल को ढूंढने में पार्टी कार्यकर्ताओं को करीब पांच मिनट लगे. वे मंच पर आए तो सबसे पहले रूपाणी ने उनका अभिवादन किया. तोमर ने उनसे आग्रह किया कि विधायकों से दो शब्द कहें. नए मुख्यमंत्री इस कदर अभिभूत थे कि ज्यादा कुछ नहीं कह पाए. उन्होंने सबको दिल खोलकर धन्यवाद दिया और बैठ गए.

शीर्ष पद के लिए पहली-बार विधायक और आरएसएस के अंशकालिक कार्यकर्ता 59 वर्षीय भूपेंद्र पटेल का चयन गुजरात में भाजपा की कार्यप्रणाली में एक और बदलाव का इशारा है. अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र की किस्मत तब पलटी जब गुजरात की मुख्यमंत्री (2014-16) और उत्तर प्रदेश की मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें ज्यादा बड़ी राजनैतिक भूमिका के लिए चुना. इंजीनियर से बिल्डर और फिर नेता बने भूपेंद्र 2010 तक थलतेज नगर परिषद के अध्यक्ष थे जब इस क्षेत्र को अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) में मिला दिया गया. इस तरह 2010 में अभूतपूर्व स्थिति में पहली बार एएमसी में आने के बाद भूपेंद्र इस ताकतवर निकाय की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने.

एएमसी में उनके बेदाग कार्यकाल की बदौलत 2015 में उन्हें एयूडीए के अध्यक्ष की कुर्सी मिली. दो साल बाद आनंदीबेन जब मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनकर भोपाल गईं तो उन्होंने अहमदाबाद के घटलोदिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना. भूपेंद्र ने यह सीट 1,17,000 वोटों से जीती. 2017 के चुनाव में कोई और उम्मीदवार इतने ज्यादा वोटों के अंतर से नहीं जीता.

दरियापुर और घटलोदिया इलाकों के बाशिंदे भूपेंद्र को संघ के आम स्वयंसेवक के तौर पर जानते हैं जो साल के सभी छह 'उत्सवों' में भाग लेना कभी नहीं भूलता. कारोबारी दर्शन सोलंकी कहते हैं, ''भूपेंद्रभाई एकदम सीधे-सादे आदमी हैं. एएमसी में मैं जब भी उनसे टकरा जाता और यूं ही पूछ लेता कि 'केम छो काका? (कैसे हो काका?)', वे जवाब देते, 'मजा मा (मैं अच्छा हूं).' उनके नाज-नखरे नहीं हैं और हमेशा यहां तक कि अजनबियों के साथ भी विनम्रता से पेश आते हैं.''

यही वह गैर-विवादित पृष्ठभूमि और हर जगह नए दोस्त बनाने की फितरत है, जिससे वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंसद के तौर पर उभर पाए. राज्य भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं कि फिलहाल पार्टी को ऐसे शख्स की जरूरत थी जो सबको साथ लेकर चले और कार्यकर्ताओं में भरोसा कायम कर सके. वे कहते हैं, ''कार्यकर्ता विजयभाई रूपाणी से मायूस हो गए थे. वे गैर-विवादित और बहुत भले इनसान हैं... लेकिन अफसरशाही पर निर्भर रहने के चलते कार्यकर्ताओं से जुड़ाव गंवा बैठे.''

भाजपा नेतृत्व ने शीर्ष पद के लिए दिग्गज पाटीदार नेता और उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल के नाम पर भी विचार किया. मगर उन्हें लगा कि वे अंततः बोझ साबित हो सकते हैं. वही भाजपा नेता कहते हैं, ''अगर नितिन भाई को मुख्यमंत्री बनाते तो उत्तर गुजरात के ठाकोर और चौधरी समुदाय भाजपा के खिलाफ चले जाते, खासकर दोनों समुदायों के साथ उनकी अदावत को देखते हुए. हम उन्हें नाराज करने की स्थिति में नहीं थे.''

नजर पाटीदारों पर

आबादी में 18 फीसद हिस्सेदारी वाले पाटीदार समुदाय में गुजरात के चार में से तीन क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता है. पहले खेती-किसानी तक सीमित इस समुदाय के लोग अब व्यापार और कारोबार में भी अगुआ हैं. आरक्षण की मांग पर पार्टी की हिचकिचाहट देखकर 2017 में यह समुदाय भाजपा से छिटक गया. कीमत भाजपा को कम से कम सात सीटों से चुकानी पड़ी. 2017 का चुनाव भाजपा करीब 47 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के पारंपरिक वोटों में फूट डलवाने के बाद भी महज 99 सीटों के साथ जीत सकी.

भाजपा को अपने चुनावी प्रदर्शन में सुधार लाना है तो भूपेंद्र को, जो पाटीदारों के कड़वा पंथ से आते हैं, समूचे समुदाय को साथ लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी. पटेल को कई पाटीदार संगठनों के साथ अपने करीबी रिश्तों का फायदा मिल सकता है. राज्य सरकार के एक सूत्र कहते हैं कि सुलह की प्रक्रिया के पहले चरण में मुख्यमंत्री शायद कई पुलिस थानों के क्षत्रिय प्रमुखों को पाटीदारों से बदल दें. गुजरात में गृह

फिसलती बढ़त

पाटीदारों के दबदबे वाले सौराष्ट्र क्षेत्र में पिछड़ने के कारण 2017 में भाजपा केवल 99 सीटें जीत सकी थी

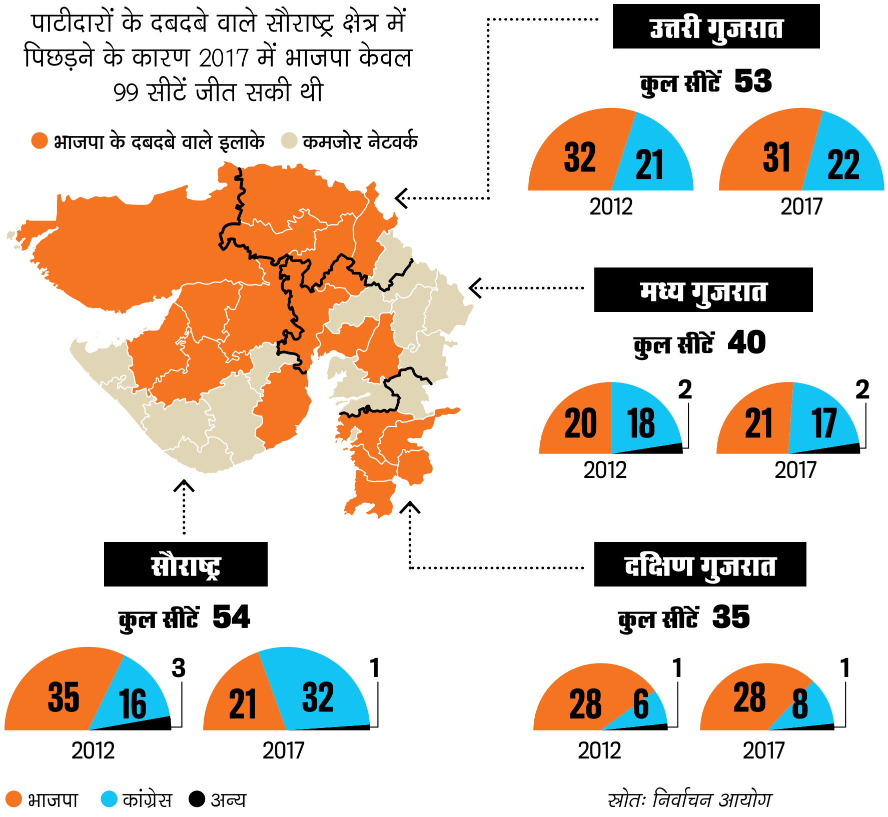

स्रोतः निर्वाचन आयोग

जातीय कारक

पिछड़े वर्ग या ओबीसी परंपरागत रूप से भाजपा के समर्थक हैं जबकि मुस्लिम और अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस के साथ हैं

(आबादी प्रतिशत में)

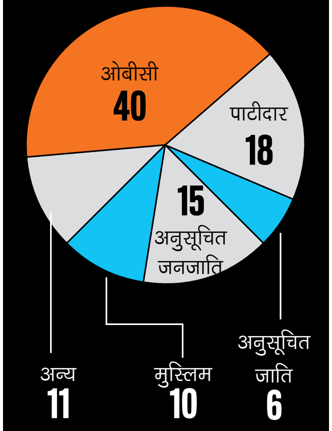

स्रोतः जनगणना 2001

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

मंत्री आम तौर पर पाटीदार समुदाय का होता है. 2001 से 2014 के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ऐसे तीन डिप्टी होम मिनिस्टर बनाए थे. उनमें से दो, गोवर्धन जडफिया और प्रफुल्ल के. पटेल, पाटीदार थे. राज्य भाजपा में धारणा यह है कि बीते पांच सालों में क्षत्रिय समुदाय से आने वाले मौजूदा जूनियर गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के मातहत पुलिस बल में पाटीदारों की उपेक्षा हुई. क्षत्रिय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया से बचने के लिए जाडेजा को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. साथ ही, एक और क्षत्रिय नेता और सबसे वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे अहम कुर्सी है.

पाटीदार समुदाय को मनाने की भाजपा की कोशिश गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) की बढ़त की भी प्रतिक्रिया है. फरवरी में आप ने पाटीदार आंदोलन समिति (पीएएस या पास) के समर्थन से सूरत नगर निगम की 25 सीटें जीतकर खासी सुर्खियां बटोरी थीं. कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली. पीएएस ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए आप का समर्थन किया. अनजाने में इसकी गाज कांग्रेस पर गिरी. सूरत हालांकि भाजपा की झोली में गया, पर इस कदम ने हीरों के शहर में कांग्रेस का सफाया कर दिया.

पाटीदार आरक्षण आंदोलन की अगुआई करने वाले हार्दिक पटेल अब कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं. राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भूपेंद्र को उदार-समावेशी नेता के तौर पर पेश करने की रणनीति कांग्रेस को और नुक्सान पहुंचा सकती है. हार्दिक इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते. 11 सितंबर को उन्होंने रिपोर्टरों से कहा, ''भाजपा तेजी से जमीन खो रही है. अभी चुनाव हों तो कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करेगी और भाजपा घटकर 40 सीटों से नीचे आ जाएगी.'' प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यमल व्यास हार्दिक की बात को हंसी में उड़ा देते हैं. वे कहते हैं, ''भूपेंद्र भाई खासे पढ़े-लिखे और साफ-सुथरे नेता हैं. हमने उन पर जुआ नहीं खेला है.''

2017 में भाजपा ने कांग्रेस की 77 के मुकाबले 99 सीटें जीती थीं. बीते चार सालों में भाजपा ने कांग्रेस के 12 विधायकों को तोड़कर अपनी ताकत 111 तक बढ़ा ली. 40 विधायक चुनने वाला मध्य गुजरात भाजपा की सबसे कमजोर रग है. यहां क्षत्रियों, अनुसूचित जातियों और मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया. भाजपा ने अब एक होनहार पाटीदार नेता खोज लिया है, लेकिन क्षत्रिय, अनुसूचित जाति और मुसलमान चेहरों के लिए वह अब भी हाथ-पैर मार रही है. भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं, 'इन्हीं समुदायों ने गुजरात में कांग्रेस को जिंदा रखा है. वे कांग्रेस को कम से कम 40 सीटें दिलाते हैं. फिलहाल यह सबसे बड़ी चिंता है.''

राजनैतिक विश्लेषक शिरीष काशिकर का कहना है कि भाजपा के रेवड़ और खासकर मंत्रिमंडल के महत्वाकांक्षी साथियों को एकजुट रखना भूपेंद्र पटेल की मुख्य चुनौती होगी. उन्हें साबित करना होगा कि वे सधे-सधाए टास्कमास्टर हैं. वे कहते हैं, ''वे पार्टी कार्यकर्ताओं की बारीक से बारीक बातें जानते हैं, पर उनकी रूपाणी या नितिन पटेल सरीखी गुजरात व्यापी अपील नहीं है. बचे हुए कार्यकाल में अगर उन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला तो शायद वे पार्टी को फिर सत्ता में ला सकते हैं. अभी तो यह बेहद मुश्किल काम मालूम देता है.'' ■

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

9:41
INDIA TODAY
LIVE
TOP NEWS
VIDEOS
PROGRAMMES
TOP STORIES

LOK SABHA 2019

Narendra Modi Live: By Congress-mukt India we will fulfil Gandhi's dream

PM Narendra Modi was speaking in Lok Sabha

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

दिक्कत भरी शुरुआत

सेना के हवाले सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे (बीच में) ने 18 फरवरी, 2021 को गुजरात के हजीरा में एलऐंडटी के कारखाने से 100वें के-9 वज़्र टैंक को रवाना किया

सिंगल डिफेंस डील या एकल रक्षा सौदा, भारत की रक्षा आधुनिकीकरण योजना को प्रभावित करने वाली देरी का द्योतक है. 8 सितंबर को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एयरबस इंडस्ट्रीज से भारतीय वायु सेना के लिए 56 सी-295 सैन्य परिवहन विमान खरीदने के 20,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2015 में ही इस सौदे के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर भी इसे आखिरी हरी झंडी के लिए छह साल तक इंतजार करना पड़ा. अनुबंध पर अंतत: हस्ताक्षर हो जाने के बाद, एयरबस अपने भारतीय सहयोगी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) के साथ 56 सैन्य परिवहन विमानों में से 40 को भारत में असेंबल करेगा.

यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि सरकार के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एकमात्र भारतीय कंपनी है जो सैन्य विमान बनाती है. यह सौदा भले ही

रक्षा मंत्रालय की पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, युद्धक टैंक और हेलिकॉप्टर निर्माण के लिए दूसरी उत्पादन श्रृंखला बनाने की महत्वाकांक्षी योजना सुस्ती का शिकार हो गई है

संदीप उन्नीथन

बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह देश के भीतर रक्षा स्वदेशीकरण के उस अभियान को बढ़ावा नहीं देगा जिसे सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान कहती है. अभियान के तहत सरकार चाहती है कि भारतीय रक्षा कंपनियां न केवल सैन्य साजो-सामान का देश में उत्पादन करें बल्कि निर्यात भी करें. उदाहरण के लिए, टीएएसएल, सी-295 की अनुकृति या कॉपी बनाने, इसे अपग्रेड करने या यहां तक कि अपने विदेशी भागीदार के बिना निर्यात करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि इसके पास डिजाइन का स्वामित्व नहीं है. लाइसेंस प्राप्त उत्पादन से बाहर निकलने में असमर्थता ऐसी समस्या है जिसने भारत की रक्षा स्वदेशीकरण प्रक्रिया को पंगु बना दिया है. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व वाले बेकार सैन्य औद्योगिक परिसर और स्वदेशी डिजाइन तैयार के लिए आवश्यक स्वदेशी रक्षा अनुसंधान एवं विकास की कमी से लेकर सशस्त्र बलों की स्वदेशी उत्पादों में कम रुचि, इसके मुख्य कारण कहे जा सकते हैं.

इसका परिणाम क्या हुआ? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है. 2016 और 2020 के बीच, अमेरिका, रूस, फ्रांस और इज्राएल से लड़ाकू जहाज, युद्धपोत और मिसाइलों की खरीद के सौदों के साथ, हथियारों के कुल वैश्विक आयात में भारत का हिस्सा 9.5 प्रतिशत रहा.

इस दशक में तीनों सेवाएं अपने पुराने हथियारों को उन्नत करने के लिए 100 अरब डॉलर (7 लाख करोड़ रुपए) से अधिक के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक और पनडुब्बियां खरीदेंगी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनका उत्पादन भारत के भीतर किया जाए—लागत कम करने और स्थानीय निर्माण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से—सरकार ने 2017 में रणनीतिक साझेदारी (एसपी) मॉडल सामने रखा था. इसके तहत जो प्रावधान तय किए गए वे कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को निर्धारित प्रक्रिया के बाद निजी क्षेत्र से एक निर्माता को रणनीतिक साझेदार के रूप में चुनना होगा. रणनीतिक साझेदार को देश में ही निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला, आधुनिकीकरण, और अपग्रेड, शोध व अनुसंधान और आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक ईकोसिस्टम बनाने की खातिर विदेशी ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की साझेदारी करनी होगी.

2017 में, रक्षा मंत्रालय ने अपनी चार सबसे बड़ी खरीद जरूरतों की पहचान की, जिनकी संयुक्त रूप से कीमत 2.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की थी और इन्हें निजी क्षेत्र को सौंपा जाना था. इनमें छह पनडुब्बियों और युद्धपोतों से संचालित करने के लिए 123 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की नौसेना की योजना, 1,700 टी-72 टैंकों के बेड़े के प्रतिस्थापन की भारतीय सेना की योजना और अपने घटते लड़ाकू स्क्वाड्रनों को बदलने के लिए 110 लड़ाकू जहाजों की वायु सेना की मांग शामिल हैं.

हालांकि, यह साझेदारी मॉडल अनावश्यक देरी का शिकार हो गया है. पांच साल बाद भी चार परियोजनाओं में से तीन, अपने उस पहले चरण में ही हैं जिसमें एक रक्षा सेवा आरएफआइ या सूचना के लिए अनुरोध भेजती है. (किसी खरीद के लिए बातचीत शुरू होने से लेकर सौदे के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर होने तक में, पांच से सात साल लग जाते हैं.) पनडुब्बियों के निर्माण के लिए नौसेना की पी-75 (आइ) परियोजना ही एकमात्र ऐसी परियोजना है जो दूसरे चरण में है जिसमें उत्पादन साझेदारों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. हालांकि पहली पनडुब्बी के लिए निर्माण कार्य शुरू होने में अभी भी कई साल लगेंगे.

नौसेना के लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के निर्माण की एक अन्य परियोजना भी अधर में फंस गई है. सार्वजनिक क्षेत्र का

> **लाइसेंस प्राप्त उत्पादन से बाहर निकलने में असमर्थता ऐसी समस्या है जिसने भारत की रक्षा स्वदेशीकरण प्रक्रिया को पंगु बना दिया**

एचएएल अपने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एएलएच ध्रुव के एक नए संस्करण के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरने को इच्छुक है, लेकिन नौसेना एचएएल को इससे बाहर ही रखना चाहती है. इसके लिए नौसेना यह हवाला दे रही है कि रणनीतिक साझेदारी का मॉडल केवल निजी क्षेत्र के लिए है और एचएएल सार्वजनिक फर्म है. वहीं एचएएल ने सरकारी स्वामित्व वाले मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल) की ओर से पी-75 (आइ) पनडुब्बी दौड़ में शामिल होने की स्थापित मिसाल का हवाला देकर अपने दावे को सही ठहराया है. माना जाता है कि सरकार ने एनयूएच (नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर) कार्यक्रम को अभी रोक दिया है और नौसेना को इसकी कमी से निपटने के लिए लीज पर हेलिकॉप्टर लेने की अनुमति दी है.

निर्माण का व्यावहारिक कौशल और तकनीक का ज्ञान

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, सरकार अपने 41 आयुध कारखानों को सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा निगमों में बदल रही है, रक्षा उद्योगों को विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए भूमि देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे बना रही है. रक्षा मंत्रालय ने एक सूची जारी की है जिसमें युद्धपोतों से लेकर हॉवित्जर तक 209 वस्तुओं के देश में ही निर्माण का फैसला किया गया है. इस सूची में अधिसूचित साजो-सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और अगले पांच से सात वर्षों में घरेलू रक्षा उद्योग को 4 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर का आश्वासन दिया गया है.

इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग की स्थानीय निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने की पहल को प्रोत्साहित करना है. सरकार ने 2025 तक हर साल 35,000 करोड़ रुपए (5 अरब डॉलर) के निर्यात का लक्ष्य तय किया है. एसपी मॉडल को इस नीति के साथ फिट होना चाहिए था, लेकिन रक्षा मंत्रालय को लगता है कि महत्वाकांक्षी स्वदेशीकरण नीति के साथ उसका तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है.

रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ''एसपी मॉडल एक अलग युग का है. यह लाइसेंस प्राप्त उत्पादन का उन्नत संस्करण है. जबकि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियों के पास तकनीक भी हो और उसे व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित करने की क्षमता भी.'' व्यावहारिक ज्ञान या कुशलता लाइसेंस प्राप्त उत्पादन में सक्षम बनाता है जबकि तकनीक किसी भी सामग्री को स्वतंत्र रूप से डिजाइन करने की क्षमता लाता है, जो तब संभव है जब डिजाइन तकनीक का हस्तांतरण किया जाए. एयरबस सी-295 सौदे के मामले में तय है कि तकनीक विदेशी ओईएम के पास ही बनी रहेगी.

रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह एसपी मॉडल में संरचनात्मक खामी का नतीजा है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से नियुक्त कई समितियों द्वारा अनुशंसित मूल 'कॉस्ट प्लस' मॉडल (जिसमें किसी उत्पाद का उसके पूरे जीवन चक्र में कुल लागत का अनुमान लगाया जाता है) को 'एल 1' मॉडल में बदल दिया गया, जिसके तहत मंत्रालय सबसे कम बोली लगाने वाले को ठेका देता है. इस प्रकार, एक एल1 मॉडल किसी भी अन्य रक्षा अनुबंध से अलग नहीं है और भारतीय तथा विदेशी साझेदार के बीच सहयोग एक बार होता है. इसमें स्वदेशी हथियार विकसित करने के लिए भारतीय कंपनी के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है.

रक्षा मंत्रालय, निजी रक्षा उद्योग के साथ अपने गठजोड़ को 'रणनीतिक साझेदारी' तो बताता है लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि निजी क्षेत्र के लिए यह सिर्फ व्यावसायिक निवेश भर है. रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, ''निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए रक्षा उद्योग, कई अन्य व्यवसाय विकल्पों में से एक है. वे अपने संसाधनों का निवेश रियल एस्टेट

> **सरकार का रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम विलंब में फंस गया है, चार में से तीन परियोजनाएं अभी अपने पहले चरण में हैं**

खरामा-खरामा बढ़ती भागीदारियां

रणनीतिक भागीदारियों का मतलब था भारत की हथियार का खरीदार होने की स्थिति का फायदा उठाकर देश में टेक्नोलॉजी लाना. मगर बजट की कमी और अफसरशाही के अड़ंगों का नतीजा यह है कि कुल मिलाकर 2.2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं

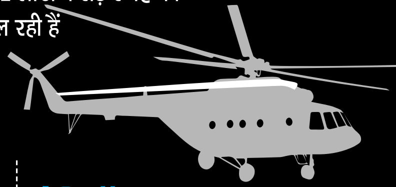

पनडुब्बियां

प्रोजेक्टः 75 (आइ)

संख्याः 6 पारंपरिक पनडुब्बियां

बजटः 60,000 करोड़ रुपए

स्थितिः नौसेना ने 20 जुलाई 2021 को आरएफपी (प्रस्तावों के लिए निवेदन) जारी किए; मूल्यांकन पूरा करने की प्रक्रिया जारी

● ● ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

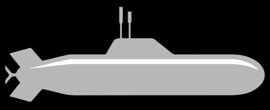

हेलिकॉप्टर

प्रोजेक्टः नौसैन्य उपयोगिता हेलिकॉप्टर

संख्याः 111 (95 भारत में एसेंबल)

बजटः 21,000 करोड़ रुपए

स्थितिः अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज लि., महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लि., एयरबस हेलिकॉप्टर्स, लॉकहीड मार्टिन और रशियन हेलिकॉप्टर्स ने इस परियोजना के लिए प्रस्ताव दिए. आरपीएफ अभी जारी होने हैं. इसे रोक दी गई क्योंकि एचएएल का कहना है कि वह एक एनएचयू (नेवल यूटिलिटी हेलिकॉप्टर) मैदान में उतारेगा

● ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

एयरक्राफ्ट

प्रोजेक्टः लड़ाकू विमान

संख्याः 110

बजटः 15 अरब डॉलर (1.1 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा

स्थितिः आरएफआइ (जानकारी के लिए निवेदन) अप्रैल 2018 में दसो एविएशन, साब, लॉकहीड मार्टिन, यूरोफाइटर, जीएमबीएच और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन को जारी किया गया. आरपीएफ अभी जारी होना है

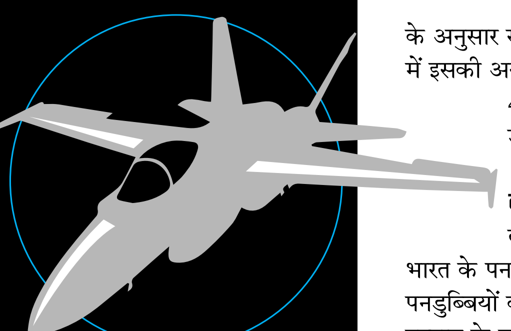

● ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

हथियारबंद लड़ाकू वाहन

प्रोजेक्टः भविष्य के लिए तैयार युद्धक वाहन

संख्याः 1,700 टैंक

बजटः 5 अरब डॉलर (36,000 करोड़ रुपए) से ज्यादा

स्थितिः सेना के टी-72 टैंकों को इनसे बदला जाना था; आरएफआइ जून 2021 में 12 ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) को जारी की गई; सितंबर 2021 तक जवाब आने की उम्मीद

● ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

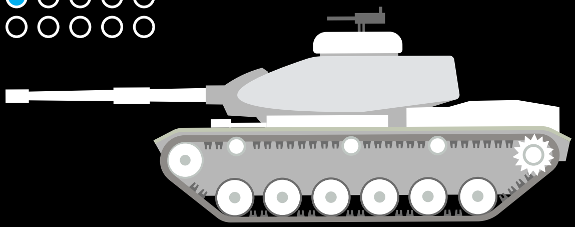

○ रक्षा अनुबंध के लिए कदम उठाना शेष है ● कदम उठाए जा चुके हैं

तन्मय चक्रवर्ती

या एयरलाइंस में भी कर सकते हैं.'' यही कारण है कि निजी कंपनियां एसपी मॉडल को लेकर सतर्क हैं. एक निजी क्षेत्र की रक्षा फर्म के सीईओ कहते हैं, ''मैं शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह हूं, मुझे पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है और रक्षा उद्योग में निवेश के लिए सरकार से कर छूट नहीं मिलती है.'' टाटा पावर एसईडी के पूर्व सीईओ और आंतरिक सुरक्षा पर फिक्की कमेटी के अध्यक्ष राहुल चौधरी कहते हैं, ''एसपी मॉडल व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इससे बुनियादी रक्षा अनुबंध सिद्धांत का उल्लंघन होता है, जहां सरकार प्रमुख ठेकेदार को पैसा देती है.''

भविष्य में ऑर्डर के लिए आश्वासन की कमी और संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश को लेकर अनिश्चितता भी, निजी खिलाड़ियों के कान खड़े कर देती है. जैसे, लार्सन ऐंड टूब्रो (एलऐंडटी) ने 2015 में भारतीय सेना के लिए 100 स्वचालित हॉवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए दक्षिण कोरिया के हान्वहा टेकविन के साथ 'खरीदो और बनाओ' समझौता किया और हॉवित्जर तोपों के लिए असेंबली लाइन स्थापित करने में निवेश किया. इस साल, समझौते के अनुसार सेना को सौंपी गई आखिरी तोप के बाद गुजरात के हजीरा में इसकी असेंबली लाइन में करने को कोई काम नहीं है. इसे जल्द ही 40 और हॉवित्जर के लिए रिपीट ऑर्डर मिलेगा, लेकिन उसके बाद यहां करने को कुछ भी नहीं होगा.

दक्षिण कोरियाई मॉडल से सबक

दक्षिण कोरिया का देवू शिपबिल्डिंग ऐंड मरीन इंजीनियरिंग भारत के पनडुब्बी-निर्माण कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 (आइ) के लिए पनडुब्बियों की आपूर्ति करने वाले पांच दावेदारों में से एक है. इस प्रस्ताव के साथ भी एक विचित्र विडंबना नजर आती है. दक्षिण कोरिया और भारत दोनों ने 1980 के दशक की शुरुआत में पश्चिमी जर्मनी की एक ही फर्म, एचडीडब्ल्यू से पनडुब्बी निर्माण की तकनीक खरीदी. जहां भारतीय पारंपरिक पनडुब्बी कार्यक्रम दशकों तक लड़खड़ाता रहा, भ्रष्टाचार और नौकरशाही के अनिर्णय में उलझा रहा, वहीं दक्षिण कोरियाई कार्यक्रम पूरी गति से चलता रहा. कोरियाई उद्यम ने प्राप्त तकनीक में और सुधार करते हुए बेहतर संस्करण विकसित किए और पनडुब्बी डिजाइन में महारत हासिल करके डीएसएमई-3000 को समुद्र में उतारा. अब कोरियाई कंपनी उसी डीएसएमई-3000 की पेशकश भारतीय नौसेना को कर रही है.

> **पिछले एक दशक में दक्षिण कोरिया आश्चर्यजनक रूप से भारतीय रक्षा बाजार में प्रवेश कर चुका है**

यह इकलौता मामला नहीं है. पिछले एक दशक में, दक्षिण कोरिया भारतीय रक्षा बाजार में आश्चर्यजनक रूप से प्रवेश कर चुका है. कोरियाई फर्मों ने भारतीय सेना को 100 के-9 हॉवित्जर की आपूर्ति के लिए 4,500 करोड़ रुपए का ठेका हासिल किया है और भारतीय नौसेना के लिए माइनस्वीपर्स और सेना के लिए स्वचालित एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए प्रतियोगिता में सबसे सस्ती बोली लगाने वाली कंपनियों के रूप में उभरी हैं. इसने तीनों क्षेत्रों—जल, थल और वायु—में परिष्कृत सैन्य साजो-सामान के निर्माण की क्षमता में महारत हासिल की है जो केवल चीन, रूस और अमेरिका जैसे संपन्न बड़े देशों के पास ही है.

मार्च 2021 की अपनी रिपोर्ट में स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उल्लेख किया कि 2016-20 में कुल वैश्विक निर्यात के 2.7 प्रतिशत हिस्से के साथ दक्षिण कोरिया दुनिया का नौवां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक था. 2016-20 में इसका हथियारों का निर्यात 2011-15 की तुलना में 210 प्रतिशत अधिक और 2001-2005 की तुलना में 649 प्रतिशत अधिक था. फिलाडेल्फिया स्थित विदेश नीति अनुसंधान संस्थान, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो फेलिक्स के. चांग के 2019 के एक शोधपत्र में कहा गया है कि 'दक्षिण कोरिया ने अपने रक्षा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए व्यापक सुधारों को लागू किया, देश के बड़े उद्योग घरानों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया और छोटी और मध्यम आकार की रक्षा कंपनियों को पनपने में मदद की जो हथियारों के घटकों का कुशलतापूर्वक उत्पादन कर सकती थीं. इन सुधारों ने न केवल इसके बड़े रक्षा उत्पादकों को अपनी कीमतें कम करने में सक्षम बनाया, बल्कि इसकी छोटी कंपनियों को भी वैश्विक रक्षा आपूर्ति शृंखला में कदम रखने में सक्षम बनाया.'

ये ऐसे सबक हैं जिन्हें रक्षा मंत्रालय को सीखने की जरूरत है. ■

दाने-दाने में है दम पर सेहतमंद न हो जाएं बेदम

सरकार की ओर से फोर्टिफाइड चावल को राष्ट्रीय मानक बनाना सुविचारित कदम है, लेकिन विशेषज्ञ पोषक तत्वों की अधिकता से होने वाले जोखिमों के प्रति कर रहे हैं आगाह

अमरनाथ के. मेनन

भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और महिलाओं और बच्चों को लक्षित खाद्य योजनाओं के माध्यम से ऊपर से मिलाए गए पोषक तत्वों से युक्त चावल (फोर्टिफाइड राइस) की आपूर्ति करेगी. खून की कमी या एनीमिया और कुपोषण से निपटने की दिशा में बड़े प्रयास के रूप में, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2021-22 से एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) योजना और मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू करेगा. इसमें 112 आकांक्षी जिलों (खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतक वाले) पर विशेष जोर रहेगा. इस वर्ष के लिए, केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पीडीएस, एमडीएमएस और आइसीडीएस योजना के लिए 3.28 करोड़ टन चावल आवंटित किया है. लेकिन 2024 तक चावल की पूरी आपूर्ति को फोर्टिफाइड चावल के रूप में उपलब्ध कराना, कठिन लक्ष्य लगता है.

राइस फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में अनाज में आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है ताकि पूरे देश में बड़े पैमाने पर कुपोषित और इसके जोखिम वाली बड़ी आबादी को पोषण उपलब्ध कराया जा सके. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रधिकरण (एफएसएसएआइ) के मानदंडों के अनुसार, एक किलो फोर्टीफाइ चावल में आयरन (28 एमजी से 42.5 एमजी), फोलिक एसिड (75-125 एमसीजी) और विटामिन बी 12 0.75-1.25 एमजी) होना चाहिए.

आयरन की कमी और एनीमिया से पीड़ित लोगों की दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या भारत में है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-4) के अनुसार, 59 प्रतिशत बच्चों और 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है. बाल और मातृ कुपोषण की देश में बीमारियों के बोझ में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. साल 2015-16 में हुए एनएफएचएस-4 में पाया गया कि पांच साल तक के बच्चों में कम वजन, बौनापन और दुर्बलता का औसत क्रमश: 35.7, 38.4 और 21 प्रतिशत है.

केंद्र सरकार का मानना है कि अतिरिक्त पोषक तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड चावल, कुपोषण से लड़ने में रामबाण साबित होगा. सरकार नीति आयोग और एफएसएसएआइ के अलावा टाटा ट्रस्ट, विश्व खाद्य कार्यक्रम, पाथ और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल जैसे गैर-सरकारी हितधारकों के साथ परामर्श से आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने और आपूर्ति संबंधी अन्य परेशानियों को दूर करने पर काम कर रही

उन्नत अन्न

फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई चुनिंदा राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई है जिसकी लोगों में अच्छी स्वीकार्यता है

है. दुनिया में उत्पन्न कुल चावल का पांचवां हिस्सा भारत में पैदा होता है. प्रति व्यक्ति 6.8 किलो प्रति माह खपत के साथ, यह चावल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है.

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 2019-20 से फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति की एक पायलट योजना (हर राज्य के एक जिले में) चल रही है और इसे विस्तार देते हुए मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, केरल और झारखंड में भी शुरू करने की योजना है. परियोजना के प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि लाभार्थी फोर्टिफाइड चावल पसंद कर रहे हैं.

किसी भी खाद्य पदार्थ को फोर्टिफाइ करने के पीछे उद्देश्य भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि जो लोग अल्प जोखिम में हैं उन्हें स्वास्थ्यकर आहार देकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके. इसके लिए तय मात्रा में खाद्य योजकों या फूड एडिटिव का उपयोग करना होता है.

क्या फोर्टिफाइड चावल से लाभ होगा?

जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी दूर करने के लिए आहार को अतिरिक्त पोषणयुक्त बनाना सबसे स्थायी उपायों में से एक है. यह न केवल कम खर्चीला, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त है, बल्कि पहले से चल रही खाद्य वितरण योजनाओं के माध्यम से लक्षित आबादी को इसकी आपूर्ति भी आसानी से सुनिश्चित की जा सकती है. पीडीएस, आइसीडीएस योजना और एमडीएमएस जैसे सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में चावल की खपत सबसे अधिक है. यही वजह फोर्टिफाइ करने के लिए चावल को ही एक आदर्श विकल्प बनाती है. यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी (छिपी भूख) से निपटने में मदद कर सकता है. जिनकी कमी से आबादी के एक बड़े वर्ग का स्वास्थ्य जोखिम में बना रहता है.

प्रजनन आयु वाली महिलाएं, बच्चे और किशोर सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं. पायलट प्रोजेक्ट में सरकार की साझीदार संस्था न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की भारत में निदेशक, मिनी वर्गीज कहती हैं, ''भारत में चावल की औसत खपत के आधार पर कहा जा सकता है कि फोर्टिफाइड चावल से आयरन के अनुशंसित आहार अंश (आरडीए) के 30-50 प्रतिशत तक की पूर्ति की जा सकती है जिसकी वयस्कों को रोज जरूरत होती है. सुव्यवस्थित निगरानी में किए गए ट्रायल, जिनमें गोलियों के माध्यम से आयरन का 100 प्रतिशत आरडीए सुनिश्चित किया गया था, का परिणाम 10 महीने के भीतर नजर आने लगा. लेकिन फोर्टिफाइड चावल के साथ किया गया ट्रायल असर दिखाने में कम से कम 24 महीने का समय लेता है.''

न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने सरकार के फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर (एफएफआरसी) के सहयोग से इस साल फरवरी में मध्य प्रदेश के तीन जिलों में फोर्टिफाइड चावल के लिए स्वीकार्यता का अध्ययन किया. आइसीडीएस योजना और एमडीएमएस के 400 से अधिक लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल से तैयार खिचड़ी और खीर परोसी गई. उनमें से 80 प्रतिशत से अधिक ने इसे पसंद किया और 60 प्रतिशत से अधिक ने कहा कि अगर पीडीएस, एमडीएमएस और आइसीडीएस योजना के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाए तो वे इसे खाना पसंद करेंगे. तीन जिलों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फोर्टिफाइड चावल और सामान्य पीडीएस चावल में देखने में कोई अंतर नहीं नजर आता और न ही धोते और पकाते समय इसमें कोई फर्क दिखा था. वर्गीज कहती हैं, ''कई अध्ययनों ने फोर्टिफाइड चावल की प्रभावकारिता को दर्शाया है. भारत सहित 25 से अधिक देशों में 17 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है कि बाहर से अतिरिक्त पोषण मिलाए गए फोर्टिफाइड चावल का सेवन, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है. यह शरीर में आयरन की कमी को काफी हद तक दूर कर सकता है.''

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान की ओर से पड़ोसी रंगा रेड्डी जिले में सितंबर 2011 में की गई डबल-ब्लाइंड प्लेसीबो-कंट्रोल्ड स्टडी से पता चला है कि फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से स्कूली बच्चों को प्रदान किए गए माइक्रोनाइज्ड फेरिक पायरोफॉस्फेट के नियमित सेवन से उनमें आयरन की कमी दूर हुई थी. डबल-ब्लाइंड स्टडी एक ऐसा परीक्षण है जिसमें न तो प्रतिभागी और न ही प्रयोगकर्ता को यह जानकारी होती है कि वे किसी अध्ययन का हिस्सा हैं.

मार्च 2012 में सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बेंगलूरू और द माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव (न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का पूर्व नाम) ने बेंगलूरू में इसी तरह का एक अध्ययन किया था. एक स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के माध्यम से सात महीने तक फोर्टिफाइड चावल दिया गया. इसका सेवन करने वाले बच्चों में भी आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के मामले

3.28
करोड़ टन
चावल का आवंटन केंद्र ने किया है 2021-22 के लिए पीडीएस, एमडीएमएस और आइसीडीस के तहत

3,50,000
टन
फोर्टिफाइड राइस की जरूरत होगी 2024 में पूरे देश को पीडीएस के तहत कवर करने के लिए

28,000
राइस मिलर्स
को फोर्टिफाइड राइस सप्लाइ लायक बनाना होगा एफसीआइ को

सुपर राइस

क्या है राइस फोर्टिफिकेशन

देश में खाद्य पदार्थों के मानक तय करने वाली संस्था भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने फोर्टिफिकेशन की परिभाषा दी हैः खाद्य की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना ताकि न्यूनतम जोखिम के साथ लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचे

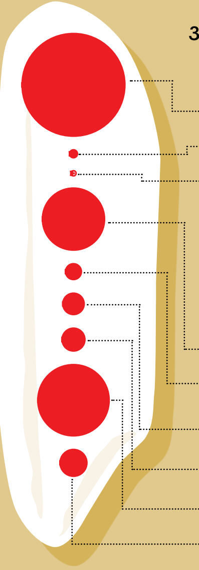

एफएसएसएआइ गाइडलाइंस के अनुसार एक किलो फोर्टिफाइड चावल में निम्न तत्व होने चाहिएः

आयरन **28-42.5** एमजी

फोलिक एसिड **75-125** एमसीजी

विटामिन बी-12 **0.75-1.25** एमसीजी

चावल को अतिरिक्त तौर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाइड किया जा सकता है

जिंक**10-15** एमजी

विटामिन ए **500-750** एमसीजी आरई

विटामिन बी-1 **1-1.5** एमजी

विटामिन बी-2 **1.25-1.75** एमजी

विटामिन बी-3 **12.5-20** एमजी

विटामिन बी-6 **1.5-2.5** एमजी

कैसे होता है चावल फोर्टिफाइड

चावल को पीसकर आटा बनाया जाता है और फिर इसमें पोषक तत्व (आयरन, विटामिन बी-12, फोलेट) मिलाए जाते हैं. आयरन अवशोषण बढ़ाने के लिए फेरिक पायरोफॉस्फेट और साइट्रिक एसिड व ट्राइसोडियम साइट्रेट जैसे यौगिक मिलाए जाते हैं. मशीनी प्रक्रिया से पिसे चावल और पोषक तत्व को चावल के आकार में बदला जाता है. इस चावल को सामान्य चावल में 1:100 के अनुपात में मिलाया जाता है

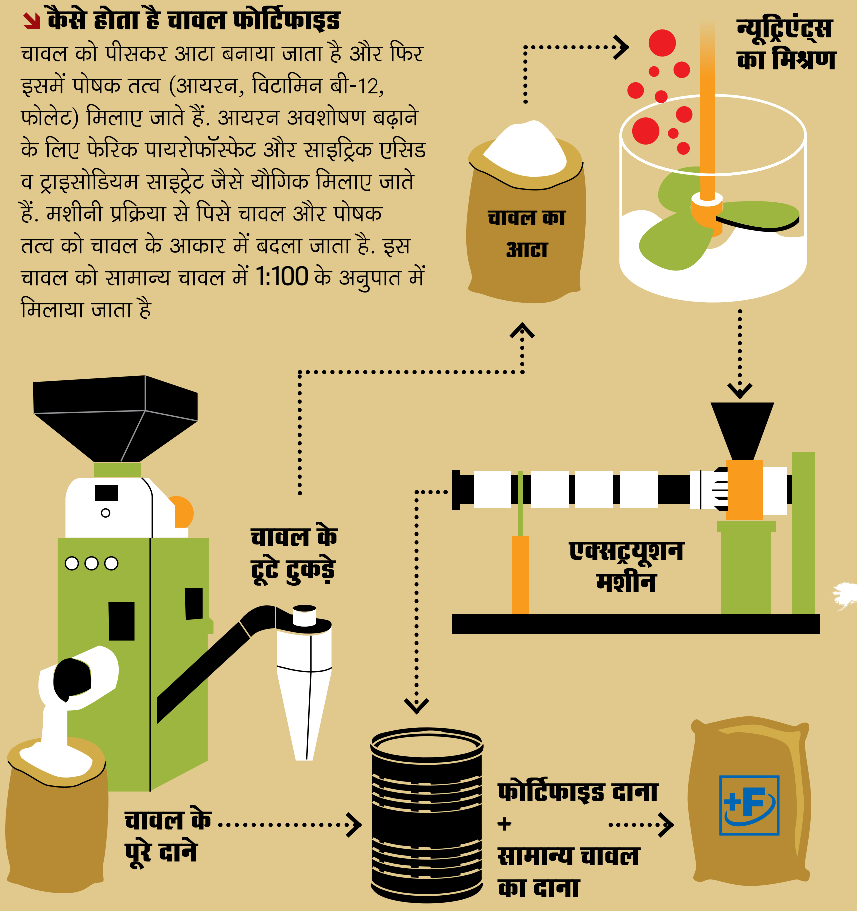
न्यूट्रिएंट्स का मिश्रण
चावल का आटा
चावल के टूटे टुकड़े
एक्सट्रयूशन मशीन
चावल के पूरे दाने
फोर्टिफाइड दाना
+
सामान्य चावल का दाना
+F

इस प्रक्रिया की लागत कितनी है

केंद्र सरकार का अनुमान है कि फोर्टिफाइड राइस (आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 समेत) बनाने में 60 पैसे प्रति किलो की लागत आएगी. इसका खर्च केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे, साथ ही चावल मिल वालों को इसकी भरपाई भी की जाएगी

कैसे पहचाना जाएगा फोर्टिफाइड राइस

फोर्टिफाइड राइस को **'+F'** लोगो लिखे जूट के बोरों में पैक किया जाएगा और उस पर—फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड ऐंड विटामिन बी-12—लिखना अनिवार्य होगा

किन देशों में फोर्टिफिकेशन अनिवार्य किया गया है

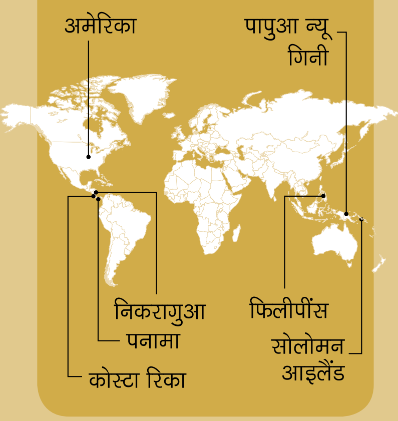
अमेरिका
पापुआ न्यू गिनी
निकरागुआ
पनामा
कोस्टा रिका
फिलीपींस
सोलोमन आइलैंड

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

30 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो जाने के संकेत मिले थे. अध्ययन से पता चला है कि फोर्टिफाइड चावल (प्रति 100 ग्राम पर 3-5 मिलीग्राम आयरन से युक्त) और प्राकृतिक चावल में, पके और बिना पके दोनों ही रूपों में कोई अंतर नहीं नजर आता था.

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूरू के पूर्व निदेशक डॉ. वी. प्रकाश जोर देकर कहते हैं, ''फूड फोर्टिफिकेशन एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका वास्तविक असर दिखने में वक्त लगता है. चावल भारत के कई हिस्सों में मुख्य भोजन है और इसके साथ खाए जाने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से दैनिक आधार पर आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति की जा सकती है. उम्मीद है कि इसके साथ पर्याप्त प्रोटीन और अन्य माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रदान किए जाएंगे.''

> "आयरन के अधिक सेवन का संबंध मधुमेह का खतरा बढ़ने से है. हम पहले ही विश्व की मधुमेह राजधानी बन चुके हैं"
>
> **डॉ. अनुरा वी. कुरपद** *सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बेंगलूरू*

छुपे हुए स्वास्थ्य जोखिम

अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि चावल को एक या दो पोषक तत्वों के साथ लैस कर देना पोषण संबंधी कमियों का समाधान नहीं है क्योंकि बच्चों के आहार में जब तक पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त प्रोटीन सुनिश्चित नहीं किया जाता, उनके स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी. विशेषज्ञ आहार में ऊपर से अतिरिक्त पोषक तत्वों को मिलाने के कारण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अधिक सेवन के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर भी आगाह करते हैं.

जुलाई 2021 में द *अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन* में प्रकाशित एक पेपर में इसके बजाए आहार विविधता में सुधार को अधिक कारगर बताया गया है. बेंगलूरू स्थित सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज के फिजियोलॉजी विभाग के डॉ. अनुरा वी. कुरपद के नेतृत्व में हुए अध्ययन में अत्यधिक सावधानी बरतने पर बल दिया गया है क्योंकि पोषक तत्व भी दवाओं की तरह तभी फायदेमंद होते हैं, अगर उनकी सही खुराक ली जाए. लेकिन बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने पर उनके फायदेमंद होने के बजाए नुक्सानदेह होने की अधिक संभावना रहती है.

पेपर में तर्क दिया गया है कि देश में एनीमिया को लेकर जो अनुमान हैं वे वास्तविकता से कहीं अधिक हैं. इसके लिए मुख्य रूप से तीन कारक जिम्मेदार हैं—बच्चों या गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के लिए जो हीमोग्लोबिन का स्तर तय किया गया है वह अनुचित है; जांच के लिए आवश्यक खून का नमूना नसों से निकालने के बजाए कैपिलरी ब्लड सैंपल (उंगली में चुभाकर निकाले गए खून से नमूना लेना) को अपनाने की प्रथा; और आयरन की दैनिक आवश्यकता का बेंचमार्क अधिक होना, जिसे हाल ही में संशोधित करके घटा दिया गया है. कुरपद कहते हैं, ''आपको भारतीय आहार में 15-18 मिलीग्राम की दैनिक जरूरत की पूर्ति के लिए अनाज को फोर्टिफाइ करने की जरूरत नहीं है. हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आयरन की कमी इसलिए तो नहीं है क्योंकि हम आयरन को अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं और कहीं एनीमिया की कुछ अन्य वजहें तो नहीं हैं. आहार में अधिक से अधिक आयरन को शामिल करने से आबादी के एक हिस्से के लिए आयरन की सहनीय ऊपरी सीमा से अधिक सेवन का खतरा पैदा हो सकता है.''

कुरपद चावल के अनिवार्य फोर्टिफिकेशन को घबराहट में ''बिना ठीक से विचारे लिया गया फैसला'' बताते हैं. वे कहते हैं, ''पिछले 20 वर्षों से यह सर्वविदित है कि आयरन के अधिक सेवन से मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है. भारत पहले ही दुनिया की मधुमेह राजधानी बन चुका है. आरडीए इसका गलत माप है. हमें एनआइएन (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन) की 2020 की संशोधित आहार संबंधी सिफारिशों का पालन करना चाहिए, जो कि आरडीए का आधा है. जब हम इन्हें लेते हैं तो कई आहार खुद ही पर्याप्त हो जाते हैं.''

सबको इसकी जरूरत नहीं

सरकार की योजना चावल और यहां तक कि खाद्य तेलों को अनिवार्य रूप से फोर्टिफाइ करने की है. देश की अनुमानित 28,000 राइस मिलों में तैयार होने वाले सारे चावल को फोर्टिफाइ करना भारी-भरकम काम होगा. वर्तमान में भारत के पास सालाना 15,000 टन अनाज फोर्टिफाइ करने की क्षमता है. यह 2024 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. जिन 112 जिलों को चिह्नित किया गया है, केवल उनके ही पीडीएस, आंगनवाड़ी और एमडीएमएस आपूर्ति को कवर करने के लिए हमारी वार्षिक क्षमता 1,30,000 टन होनी चाहिए. 2024 में पूरे देश में पीडीएस को कवर करने के लिए कम से कम 3,50,000 टन फोर्टिफाइड अनाज की जरूरत होगी.

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) को कहा गया है कि वह चावल मिलों को नियमित चावल में पोषण के दाने मिलाने के लिए आवश्यक सम्मिश्रण मशीनों से लैस कराए. राइस मिल संचालकों को इसके लिए तत्काल निवेश की जरूरत होगी और सरकार इसके लिए उन्हें ऋण और अन्य प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकती है. चूंकि फोर्टिफाइड दाने, सामान्य चावल के दानों जैसे ही दिखते हैं और उनके स्वाद में भी कोई फर्क नहीं होता, इसलिए गुणवत्ता जांच और निगरानी की भी आवश्यकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि चावल को अनिवार्य रूप से अतिरिक्त पोषक तत्वों से युक्त करने से आबादी का वह समूह भी इसके सेवन को मजबूर होगा, जिन्हें खाद्य योजक लेने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों को फोर्टिफाइड चावल खाने से फायदे की जगह नुक्सान भी हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. रमेश वी. भट कहते हैं, ''खाद्य कानूनों के सुरक्षा उपायों के बावजूद चावल को अनिवार्य रूप से फोर्टिफाइ किए जाने का फैसला खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है. खाद्य सुरक्षा कानूनों का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया गया है; और कई राज्यों में इसका पालन उचित तरीके से नहीं किया जाता.''

फोर्टिफाइ करना या अनाज में ऊपर से कुछ पोषक तत्व मिला देना, निवारक हस्तक्षेप है न कि उपचारात्मक हस्तक्षेप. यह मध्यम अवधि में हल्के एनीमिया और लंबे समय में गंभीर एनीमिया को रोकने में मददगार हो सकता है. इसके लिए केवल फोर्टिफाइ किया गया अनाज पर्याप्त नहीं होगा, उसे आहार में विविधता के साथ पूरक समर्थन की जरूरत होगी. वर्गीज कहती हैं, ''लोग बदलावों को स्वीकार करने में समय लेते हैं. अनाज को फोर्टिफाइ करने से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करने और इससे जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए मजबूत जागरूकता रणनीति की जरूरत है.'' लेकिन डॉ. कुरपद इस उपाय के साथ चेतावनी जोड़ देते हैं, ''इलाज, रोग बन सकता है.'' ■

बढ़ती संख्या
झालाना फॉरेस्ट रिजर्व में तेंदुए

गुलदारों से गुलजार गलियारा

झालाना रिजर्व फॉरेस्ट में लेपर्ड सफारी की कामयाबी से उत्साहित होकर झालाना से सरिस्का तक लेपर्ड कॉरिडोर बनाने की योजना

रोहित परिहार

धीरेंद्र गोधा

भारत में तेंदुओं की खोजबीन

भारत के ज्यादातर वन क्षेत्रों में तेंदुआ प्रमुख परभक्षी जानवर है. इसकी भारतीय प्रजाति *पैंथेरा पार्डस फुस्का* केवल थार के निर्जल रेगिस्तान और मैंग्रोव सुंदरबन को छोड़कर भारत के सभी वासस्थानों में पाई जाती है. हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि उनके वासस्थानों पर मानव अतिक्रमण के चलते बीती दो सदियों में उनकी आबादी 75-90 फीसद कम हुई. लिहाजा आइयूसीएन (अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) के तहत उनका दर्जा 'संकटासन्न' से घटाकर 'असुरक्षित' कर दिया गया. उन्हें भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) कानून 1972 की अनुसूची-1 में रखा गया है, जो कानून के तहत उपलब्ध सर्वाधिक संरक्षण देती है. 2018 में प्रकाशित डब्ल्यूआइआइ और एनटीसीए के अध्ययन ने अनुमान लगाया था कि पूरे भारत में 13,000 तेंदुए हैं. यह अध्ययन बाघ के वासस्थानों पर कैमरा ट्रैप से किया गया, जिन्होंने 26,838 जगहों पर करीब 5,200 गुलदारों की तस्वीर खींचीं.

झालाना रिजर्व फॉरेस्ट (जेआरएफ) के अफसरों ने मादा तेंदुआ फ्लोरा को दो शावकों के साथ देखा. हालांकि भारत में तेंदुओं की आबादी बीते कुछ सालों से बढ़ रही है, पर यह खासकर इसलिए खुशी की बात थी कि अक्तूबर 2018 में राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था कि झालाना में देश की पहली लेपर्ड सफारी होगी. यहां 29 वयस्क और 15 शावक तेंदुए हैं, जिनमें 12 इसी साल जन्मे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया में तेंदुओं की आबादी का सबसे ज्यादा घनत्व जेआरएफ में है. हालांकि अधिकारी कहते हैं कि यह दावा करना अभी जल्दबाजी होगा.

तो भी जेआरएफ ने अफसरों, सैलानियों और वन्यजीव विशेषज्ञों में खासी दिलचस्पी जगा दी है. इसकी कामयाबी को नजदीकी इलाकों में दोहराने का मनसूबा भी है, जिसमें इसे अंततः नजदीकी (करीब 100 किमी दूर) सरिस्का टाइगर रिजर्व से जोड़कर एक गलियारा बनाया जाएगा. राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और जंगल अमले के मुखिया दीप नारायण पांडे कहते हैं, ''जेआरएफ कामयाबी की कहानी बनकर उभर रहा है, पर हमें इसकी परवरिश करने की जरूरत है. जिस तरह रणथंभौर बाघ देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, वैसे ही झालाना तेंदुए देखने की बेहतरीन जगह है.''

लेपर्ड या तेंदुओं को कई इलाकों में गुलदार भी कहा जाता है. यह नाम उनक शरीर पर काली चित्तियों की वजह से पड़ा है. भारत में तेंदुओं के साथ बाघों के सौतेले भाइयों सरीखा बर्ताव किया जाता है. वे उन बड़ी बिल्लियों में जो हैं जिनका सबसे कम अध्ययन किया गया है. झालाना इसे

भी बदल सकता है. दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में गेम रेंजर के तौर काम कर चुके झालाना वाइल्डलाइफ रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख रिसर्चर स्वप्निल कुंभोजकर कहते हैं कि जेआरएफ हमारे लिए तेंदुओं के व्यवहार को लेकर अपनी समझ बढ़ाने का भी मौका है. मार्च 2020 के एक सहलिखित परचे में उन्होंने ऐसे ही एक लम्हे का वर्णन किया है. ऊपर जिस फ्लोरा का जिक्र है, 2019 में उसके दो शावक गायब हो गए. अधिकारियों और सैलानियों ने उसे एक पहाड़ी पर बैठे अपने शावकों को पुकारते देखा-सुना. करीब एक घंटे बाद एक पेड़ के नीचे बैठे दो धारीदार लकड़बग्घों पर उसकी नजर पड़ी. कौए उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जो चिंताजनक संकेत था. वह ताबड़तोड़ पहाड़ी से नीचे भागी, बबूल के पेड़ों और सफारी जीपों के बीच से सरपट दौड़ती पेड़ तक पहुंची और उस पर चढ़ गई. कुछ पल बाद अफसरों और सैलानियों के चेहरे तब मायूसी से घिर गए, जब उन्होंने उसे जबड़े में एक शावक को दबाए पेड़ से उतरते देखा. उसे लेकर फिर वह अरावली पहाड़ियों की कांटेदार नागफनी में चली गई. कुंभोजकर कहते हैं, ''मां तेदुए के अपने मृत शावक को मुर्दाखोर जानवरों से दूर ले जाने का यह पहला मामला (हमने देखा) है.'' उनकी टीम ने एक नर तेंदुए को भी नजदीकी पहाड़ी पर बैठे देखा. उन्हें शक है कि शावक की मौत के लिए वही जिम्मेदार था.

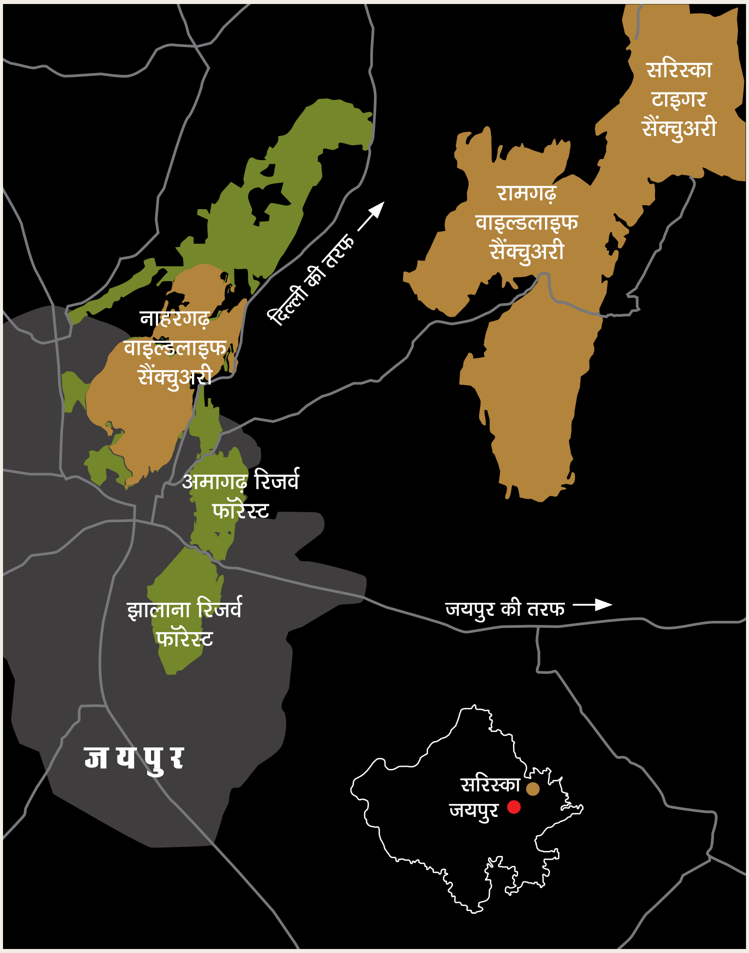

राजस्थान के वन अधिकारी झालाना से अमागढ़, नाहरगढ़ और रामगढ़ होते हुए सरिस्का तक लेपर्ड कॉरिडोर की योजना बना रहे हैं

पिछले साल छपे एक शोधपत्र में कुंभोजकर ने यह भी दावा किया कि झालाना भारत की उन जगहों में है जहां तेंदुओं का सबसे ज्यादा, 0.86 प्रति वर्ग किमी, घनत्व है. अनुमान है कि यहां तकरीबन 29 वर्ग किमी इलाके में 25 वयस्क तेंदुए हैं. हालांकि सटीक आंकड़ा निकालना आसान नहीं है, क्योंकि बाघों की गिनती केवल उन्हीं इलाकों में बार-बार की जाती है जहां सुसज्जित कैमरा ट्रैप लगे हैं. 2018 में भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तरफ से 20 राज्यों में बाघों के ठौर-ठिकानों पर किए गए अध्ययन में अनुमान जाहिर किया गया कि तमिलनाडु के श्रीविल्लिपुथुर भूरी गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य में उस वक्त तेंदुओं का सबसे ज्यादा, प्रति 100 वर्ग किमी 20.43, घनत्व था. राजस्थान के तीन टाइगर रिजर्व में करीब 476 तेंदुए होने का अनुमान है, जिनमें से 83 मुकुंदरा, 105 रणथंभौर और 273 सरिस्का में हैं.

अफसरान इस बहस में पड़ना नहीं चाहते कि भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक सघनता जेआरएफ में है या नहीं, पर वे खुशी-खुशी यह दावा जरूर करते हैं कि झालाना में तेंदुए देखना किसी भी और जगह से ज्यादा आसान है. तेंदुओं के दिखाई देने के लिहाज से झालाना की तुलना राजस्थान के पाली जिले के जवाई बांध से की जा सकती है, जहां तेंदुओं ने मैदान से ऊपर पहाड़ियों और स्थानीय लोगों के खेतों पर कब्जा जमा रखा है (न जेआरएफ और न ही जवाई बांध टाइगर रिजर्व है). प्राइवेट सफारियों का इंतजाम यहां स्थानीय लोग और होटल मालिक करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जमीनें निजी मिल्कियत में हैं. यहां तेदुओं की कुल संख्या का अंदाज लगा पाना तो मुश्किल है, पर स्थानीय लोगों का कहना है कि 50 से 60 के बीच गुलदार (तेंदुए) इस इलाके में हैं.

जेआरएफ को 1961 में राजस्थान वन कानून 1953 के तहत आरक्षित वन घोषित किया गया. यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जयपुर के दक्षिणपूर्व में और समुद्र स्तर से 516 मीटर की औसत ऊंचाई पर है. राज्य के वन विभाग ने करीब 20 साल पहले इस जंगल में स्थानीय पेड़-पौधे रोपने में बढ़ोतरी की कोशिशें शुरू कीं. फिर 2015 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जेआरएफ को लेपर्ड सफारी के इलाके में विकसित करने का आदेश दिया. उन्होंने राजस्थान प्रोजेक्ट लेपर्ड की स्थापना भी की. 2017 में रिजर्व में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और अक्तूबर 2018 में मुख्यमंत्री राजे ने जेआरएफ में तीन रास्तों पर ढाई घंटे की लेपर्ड सफारी का औपचारिक उद्घाटन किया. आज जेआरएफ को ईंट और कांटेदार झाड़ियों से बनी 32 किमी लंबी चारदीवारी ने घेर रखा है, जिससे अतिक्रमण में भारी कमी आई है और यह इस पूरे इलाके के लिए हरा-भरा द्वीप और हीट सिंक या ऊष्माशोषक बन गया है. राजस्थान वन्यजीव बोर्ड के सदस्य और वर्ल्ड वाइल्डरनेस कांग्रेस के भारत प्रमुख सुनील मेहता कहते हैं, ''झालाना की अनूठी खासियत यह है कि यह जयपुर शहर के हृदयस्थल के ठीक बगल में स्थित शहरी वन है. इसकी चारदीवारी के एक तरफ तीस

सफारी की सांख्यिकी

जब से झालाना रिजर्व फॉरेस्ट में लेपर्ड सफारियां शुरू हुईं (2017 में सफारियों की सॉफ्ट-लॉन्चिंग हुई), करीब 1,00,000 सैलानी यहां आए हैं. छह इलेक्ट्रिक वाहन और जिप्सी आगंतुकों को रिजर्व के तीन में से एक रास्ते पर दो घंटे के सफर पर ले जाती हैं. राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक दीप नारायण पांडे कहते हैं कि झालाना तेंदुए देखने के लिए भारत में सबसे अच्छी जगह है, जैसे रणथंभौर बाघ देखने के लिए. माना जाता है कि इस जंगल और आसपास के इलाके में करीब 30 वयस्क तेंदुओं की आबादी है. सफारियों की कामयाबी से उत्साहित अधिकारी नजदीकी इलाकों में ऐसे ही रिजर्व विकसित करने, झालाना से अमागढ़, नाहरगढ़ और रामगढ़ से होते हुए सरिस्का टाइगर रिजर्व तक एक वन्यजीव गलियारा बनाने पर काम कर रहे हैं. वासस्थान को मजबूत बनाने पर करीब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि शमन उपायों पर और 100 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है.

झालाना सुरक्षित अभयारण्य भारत की उन जगहों में है जहां तेंदुओं का सबसे ज्यादा, 0.86 प्रति वर्ग किमी, घनत्व है

लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और दूसरी तरफ 1,00,000 लोग वन क्षेत्रों के बहुत नजदीक या भीतर रह रहे हैं.''

जेआरएफ को तभी से स्थिर वासस्थान से चरागाह के रूप में विकसित करने की कोशिशें की जाती रही हैं. इस कवायद का मकसद इसके दायरे में रहने वाले जानवरों के लिए चारे और शिकार का आधार बनाना है. पशु-पक्षियों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय फलों के पेड़ लगाए और अतिक्रमण हटाए गए हैं. पांडे कहते हैं, ''हमारा लक्ष्य नई प्रजातियां लाने के बजाए स्थानीय प्रजातियों के जरिए झालाना और आसपास के पारितंत्र को यथा संभव अधिक से अधिक मजबूत करना है.'' इसीलिए जेआरएफ में 24 जलाशय भी हैं. इनमें से 17 बोरवेल से भरे गए हैं, जिनमें दर्जन भर का रख-रखाव सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों से किया जाता है. बाकी टैंकरों से भरे गए हैं.

जेआरएफ में पौधों की 220, स्तनधारियों की 33, पक्षियों की 132 और सर्पों की 20 प्रजातियां हैं. तेंदुओं के अलावा जो जानवर यहां बहुधा देखे जाते हैं, उनमें लकड़बग्घे, रेगिस्तानी लोमड़ियां, सियार, जंगली बिल्लियां, चीतल और सांभर हैं.

तेंदुओं के लिए शिकार के अड्डे के लिहाज से इलाके में जंगली कुत्तों की बड़ी आबादी है. तेंदुओं की लीद के विश्लेषण से पता चला कि कुत्ते और बिल्लियां गुलदारों का मुख्य आहार हैं. बकरियों और मवेशियों के अलावा चूहे-गिलहरियां, हिरण, छोटे भारतीय गंधबिलाव, मैकॉक, उत्तरी मैदानी भूरे लंगूर और नेवले भी उनके आहार का हिस्सा हैं. झालाना में अब सुस्थापित खाद्य श्रृंखला है, जिसमें तेंदुओं का आहार हैं कुत्ते और बिल्लियां, जो इलाके में बड़ी तादाद में फैले चूहों-गिलहरियों का शिकार करते हैं. इसके उलट, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक गोबिंद सागर भारद्वाज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरिस्का टाइगर रिजर्व में 84 फीसद तेंदुओं के शिकार मवेशी हैं.

झालाना की अन्य कामयाबियों में दूसरी प्रजातियों की रिवाइल्डिंग या उन्हें नए सिरे से जंगल में बसाना भी है. इनमें चीतल भी हैं जिन्हें चिड़ियाघरों से यहां लाया गया. सैकड़ों चीतल लाए गए थे, जिनमें से करीब 15 बचे हैं और एक किस्म से संस्थापक आबादी बन गए हैं. पांडे कहते हैं, ''वे जंगल में रहने के अभ्यस्त हो गए और उन्होंने तेंदुओं से बच निकलने की फितरत विकसित कर ली.''

पांडे 20 चीतल और 20 सांभर की संस्थापक आबादी विकसित करना चाहते हैं ताकि उनकी तादाद बढ़े. उन्होंने नजदीक में स्थित तेंदुओं के दूसरे वासस्थानों के लिए भी ऐसे ही उपाय प्रस्तावित किए हैं. झालाना में और जयपुर के आसपास मवेशियों पर तेंदुओं की निर्भरता को कम से कम रखना बेहद जरूरी है ताकि इनसानों के साथ उनके टकराव से बचा जा सके. अधिकारी जैसे-जैसे ज्यादा लेपर्ड रिजर्व स्थापित करने और उन्हें सफारियों के लिए खोलने की अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ेंगे, यह समस्या भी बढ़ती जाएगी.

वन अधिकारियों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने पाया कि झालाना के तेंदुए घूमते हुए करीब 40 किमी दूर अचरोल तक चले जाते हैं. अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए अक्सर नजदीकी इनसानी बस्तियों में आ जाते हैं, पर चूंकि उन्हें मुश्किल से कभी देखा गया और इनसानों के साथ टकराव भी बहुत कम हुए, इसलिए वे सुरक्षित घर लौट जाते हैं. कुंभोजकर के मुताबिक, ताजातरीन अध्ययनों से पता चला कि जेआरएफ में नर तेंदुए ज्यादा बड़े, मगर अनिश्चित इलाके में घूमते हैं, जबकि मादा तेंदुए और उनकी मादा शावक अपनी पैदाइश के नजदीकी इलाकों में घर बनाती और वहीं आसपास घूमती हैं. यही वजह है कि महकमा अमागढ़ वन क्षेत्र का 16 वर्ग किमी जेआरएफ सफारी इलाके में जोड़ने पर विचार कर रहा है, ताकि तेंदुओं को घूमने और शिकार करने के लिए ज्यादा बड़ा इलाका मिल जाए. महकमे की दूसरी प्राथमिकता यह है कि अचरोल में छोटे-से वन क्षेत्र नाहरगढ़ के 50 वर्ग किमी में और फिर रामगढ़ वन क्षेत्र के 300 वर्ग किमी में सीमित सफारियां शुरू की जाएं. रामगढ़ वन क्षेत्र को सरकार ने 2019 में सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1,100 वर्ग किमी से मिला दिया था ताकि संसाधन बढ़ाकर इसे मजबूत किया जा सके.

वासस्थान को मजबूत करने पर करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है. वहीं इन इलाकों को जोड़ने के लिए शमन उपाय करने पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी. मगर सरिस्का टाइगर रिजर्व में दाखिल होने से पहले जयपुर की बाहरी 100 किमी लंबी पट्टी पर लेपर्ड सफारियों का संचालन करने के लिए यह कोई बड़ी कीमत नहीं है.■

तो क्या महामारी बदल देगी पूरा किस्सा

नवीन कुमार

रेशुनाथ
पटकथा लेखक
''महामारी के दौरान जो कथ्य-तथ्य मेरे जेहन में बैठे वे मेरे काम में दिखेंगे ही.''

रोहन शंकर, 36 वर्ष
पटकथा लेखक
''अब कहानियां पूरी तरह जज्बात से कहने का वक्त आ गया है और मैं इसे लेकर गंभीर हूं.''

महामारी के दौरान पिछले साल अमेजन प्राइम वीडियो पर आई सीरीज *अनपॉज्ड* में एक कहानी थी *ग्लिच.* राज ऐंड डीके निर्देशित इस साइंस फिक्शन में कोरोना के समय की एक प्रेम कथा है: वायरस से खौफ के चलते एक आदमी घर से बाहर तक निकलने से डरता है. पर यही शख्स एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है जो हर रोज वायरस से लड़ रही है. इसकी पटकथा लिखने वाली रेशुनाथ कहती हैं, ''आप 2019 में इस तरह की कहानी नहीं लिख सकते थे. कोरोना महामारी ने मेरी ही क्या, सारे ही पटकथा लेखकों की सोच को बदलकर रख दिया है. एक अदृश्य वायरस हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में बैठ गया है. इसको इतनी जल्दी सोच से निकाल पाना आसान न होगा.''

कोरोना ने मनोरंजन की दुनिया को अंदर-बाहर से पूरी तरह बदलकर रख दिया है. ऐसे में सिनेमा की किसी भी रचना की बुनियाद माने जाने वाले पटकथा लेखकों पर इसका असर कैसे न पड़ता. पूरी तरह से बदल चुकी दुनिया की हकीकत और कल्पना के मेल से वे बिल्कुल नए किस्से गढ़ने में लग गए हैं. और उसका रंग फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखने लगा है.

आम लोगों की तरह रेशु ने भी महामारी के दौरान इनसानियत की ऊंचाइयों और छल-छद्म, लालच की पराकाष्ठा को भी नजदीक से देखा-जाना. वे मानती हैं कि ''यथार्थ को आत्मसात करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसने जिस तरह से हमें झकझोरा है, हमारा दिमाग बदलने लगा है.'' वैसे तो दिल्ली में लेडी श्रीराम कालेज से अंग्रेजी स्नातक और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से फिल्ममेकिंग में एमए रेशु ने पामेला रुक्स निर्देशित *डांस लाइक ए मैन* में बतौर सहायक निर्देशक सिनेमा में पारी की शुरुआत की थी. उन्होंने *फैशन* के लिए काम किया, डॉक्युमेंटरी बनाईं और कुछ दूसरी पटकथाएं भी लिखीं. ओटीटी पर उनका पहला शो था राजकुमार राव की मुख्य भूमिका वाला *बोस-डेड/अलाइव.* पर आठेक साल पहले अपने सपनों के साथ मायानगरी पहुंची बिहार के आरा की इस प्रतिभा के लिए सच और कल्पना की जुगलबंदी से महामारी के विजुअल्स रचने का यह बिल्कुल नया ही अनुभव था. उनके जेहन में लॉकडाउन के दौरान की ढेर सारी घटनाएं कैद हैं. जैसे हजारों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद करते सोनू सूद. इसी के बरअक्स ऑक्सीजन और दवा की कालाबाजारी करने वाले भी लोग. अभी वैसे वे संजय लीला भंसाली की पीरियड फिल्म *हीरा मंडी* और एक राज ऐंड डीके निर्देशित एक दूसरी फिल्म के लिए काम कर रही हैं. पर उन्हीं के शब्दों में, ''महामारी के समय के जो कथ्य और तथ्य मेरे जेहन में बैठे हुए हैं वे कालांतर में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरे काम में दिखेंगे ही.''

वेब सीरीज *पाताल लोक* के पटकथा लेखक सागर हवेली इस असर को थोड़ा अलग तरह से देखते हैं. उनका कहना है कि महामारी की वजह से लेखक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया है. ''कुछ लोग ज्यादा भावुक हो गए हैं तो कुछ लोग अतियथार्थवादी. लोगों में यह भी भावना आ गई है कि किसी के साथ कभी भी, कुछ भी हो सकता है. इसलिए अपने ढंग से जी लें.'' अभी वे दो फिल्में और एक वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं.

महामारी कहानी को आखिर बाहर से कैसे बदल रही है? इस पर वे स्पष्ट करते हैं, ''इसकी वजह से चूंकि शूटिंग के तौर-तरीके बदल गए हैं, इसलिए प्रोड्यूसर भी भीड़ वाले दृश्य नहीं चाहते. अब ऐसे में किरदार गढ़ते समय हमें इस पहलू का ध्यान रखना ही होगा.'' वे यहां एक दिलचस्प पहलू की ओर इशारा करते हैं, वह यह कि ईरान में सियासी प्रतिबंधों और दबावों के चलते वहां के लेखकों ने अपनी

सागर हवेली,
40 वर्ष
पटकथा लेखक
"बदले हालात में प्रोड्यूसर भीड़ वाले दृश्य नहीं चाहते. हमें उस हिसाब से कथानक बदलना होगा."

संजीव के. झा,
33 वर्ष
पटकथा लेखक
"महामारी में ओटीटी पर आए कंटेंट में कहानी केंद्र में रही. ऐसे में लेखकों की चुनौती बढ़ गई है."

बात रूपक वाले विजुअल्स में कहने का एक नया ढंग ईजाद कर लिया. सागर कहते हैं कि यहां भी उम्दा कहानियां निकलकर आ रही हैं. हाल में आई मलयालम फिल्म *कुरुथि* महामारी के दौरान ही बनी है. इसके लिए शहर से दूर की, बस 5-6 किरदारों वाली कहानी बुनी गई क्योंकि उसे बनाना आसान था. युद्ध पर फिल्म बनाना मुश्किल है. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सागर कृषि की पढ़ाई करके खेती करना चाहते थे मगर एमबीए के बाद विज्ञापन का काम करते हुए उनकी दुनिया बदल गई और वे अपने पहले प्रोजेक्ट *पाताल लोक* से जुड़े. बकौल सागर, ''मेरी कहानी भले ही महामारी के बारे में न हो पर कथानक और दृश्य लिखते वक्त उस बारे में तो सोचता ही हूं, सोचना जरूरी है. उस हिसाब से पक्के तौर पर कहानी बदल रही है. यह आज का सच है. कल पता नहीं क्या होगा.''

इस महामारी ने पटकथा लेखन के व्याकरण को किस तरह से बदला है, इसे एक और लेखक संजीव के. झा अपने ढंग से खोलते हैं, ''महामारी से उपजे हालात ने ओटीटी के रूप में लेखक को एक वैकल्पिक माध्यम दे दिया, जिसके लिए लिखते वक्त स्टार को नहीं बल्कि किरदार को महत्व दिया जाता है. यह पटकथा लेखन के क्षेत्र में एक बड़ी आजादी थी.'' बिहार में मोतिहारी के रहने वाले संजीव दो प्रयासों में भी एफटीआइआइ में प्रवेश न मिल पाने से निराश थे. फिर दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ाई करके मुंबई आ पहुंचे. 2019 में उनकी दो फिल्में *जबरिया जोड़ी* और *बारोत हाउस* (जी5 पर) रिलीज हुईं. उसके बाद लॉकडाउन लग गया. बकौल संजीव, ''लेखक को जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है मानवीय संबंध. परीक्षा की घड़ी में हम एक-दूसरे के लिए किस तरह से खड़े हुए. इसी तरह से डॉक्टर और मरीज के तथा सरकार और जनता के बीच के रिश्तों की सबसे परीक्षा होती है.'' संजीव का भी मानना है कि कोई पटकथा महामारी के बारे में न हो तो भी कहानी में उसकी झलक आने वाली है. रिश्तों का अनुभव, किसान आंदोलन, लड़कियों का विरोध प्रदर्शन, प्रवासी मजदूरों का पलायन, आदमी के स्वभाव में बदलाव ये सब पहलू तो कहानियों में झलकेंगे ही.

ओटीटी की कामयाबी और उसमें कहानियों की केंद्रीय भूमिका रहने से पटकथा लेखकों के सामने भी ताजा कथानक लेकर आने की चुनौती खड़ी हो गई है. और वे इसे अवसर में बदलने में लग गए हैं. हाल में ओटीटी पर रिलीज *मिमी* और *हेलमेट* जैसी फिल्मों के पटकथा लेखक रोहन शंकर का मानना है कि अब ''बहुत सारी कहानियां इमोशन से कहने का वक्त आ गया है. इस पहलू पर मैं ज्यादा गंभीर हूं. अब मैं जिन दो कहानियों पर काम रहा हूं उनमें से एक महाराष्ट्र पर आधारित है. उसमें मेरी सोच में आए बदलाव की झलक तो रहेगी ही. साथ ही उसमें वास्तविकता, गहराई और इमोशन को ज्यादा से ज्यादा कहने की कोशिश करूंगा.'' महामारी पर बात करते हुए रोहन भावुक हो जाते हैं. इसने उनके एक दोस्त की जिंदगी ले ली. उनके हिसाब से महामारी ने दुनिया ही बदल दी है. इसने जिंदगी, फिटनेस और रिश्तों की अहमियत बताई है.

महामारी ने पटकथा लेखकों को भी झकझोर कर रख दिया है. उम्मीद है कि उनके भीतर पलते द्वंद्व से दिलचस्प किस्से निकलेंगे

मिमी और *हेलमेट* से वाहवाही लूटने वाले रोहन की *सूरज पे मंगल भारी* (निर्देशक अभिषेक शर्मा) और *लुका छुपी* (लक्ष्मण उतेकर) भी दर्शकों के दिलों पर छाई हुई थी. रोहन बताते हैं, ''*मिमी* और *हेलमेट* मैंने कोविड से पहले लिखी थी. इसमें जज्बात भी हैं और ह्यूमर भी. दूसरे, हम लोगों ने साल भर में ओटीटी पर दुनिया भर के कंटेंट देख लिए हैं. मैं मराठी हूं तो मेरे लिए तो साउथ इंडियन मूवी भी फॉरेन कंटेंट है. देखकर पता चल रहा है कि दक्षिण के लेखक कमाल का काम कर रहे हैं.'' यह सब देखकर दर्शकों-लेखकों सभी की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं. रोहन का मानना है कि कॉमेडी सबसे ज्यादा चलेगी. ''महामारी को भूलने के लिए लोग हंसना चाहते हैं. ओटीटी पर महामारी से जुड़ी कुछ कहानियां आई हैं. फिर भी बेरोजगारी, जनाक्रोश, मानवीय रिश्ते जैसे मुद्दे भी कहानी में आएंगे ही. पर मैं किसी फॉर्मूले में बंधना नहीं चाहता. मैं अपनी कहानी स्वाभाविक अंदाज में कहूंगा.''

यह सच है कि महामारी ने जिस तरह से पटकथा लेखकों की सोच पर असर डाला है उससे उनके भीतर गहरे द्वंद चलने शुरू हो गए हैं. जाहिर है इस द्वंद के गर्भ से देर-सवेर ऐसे दिलचस्प किस्से निकलेंगे जो दर्शकों का एक नया तबका खींचकर लाएंगे. और मनोरंजन उद्योग को यही तो चाहिए. ■

बनारस में नहीं रहा बनारस

चर्चित कथाकार **काशीनाथ सिंह**
संस्मरण लेखन, बदलते बनारस और
यूपी में आने वाले चुनाव पर

● कोरोना संकट के डेढ़ वर्ष में अस्सी और पप्पू की चाय की दुकान छूट जाने की काफी कसक होगी आपके भीतर.

सब छूट गया है. इधर कुछ लिखा नहीं. दो-ढाई साल से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा. इसी के चलते घर से बाहर ही नहीं निकला. एक ऑपरेशन कराया था जो सफल नहीं रहा. लोग किताबें लेकर आते हैं और यहीं फोटो खींच लेते हैं. चीजें ऑनलाइन चल रही हैं.

● आपके साढ़े चार यारों में विजयमोहन सिंह, रवींद्र कालिया और फिर दूधनाथ सिंह का, साथ ही भैया नामवर सिंह का बिछड़ना भी आपको अकेला कर गया.

हां, अकेलापन तो है. जबलपुर में ज्ञानरंजन (कथाकार, संपादक) हैं. उन्हें भी कोरोना हो गया था. उसके बाद उनसे भी बातचीत नहीं हुई. सारे लोग धीरे-धीरे बिछड़ रहे.

● आपके संस्मरण काफी चर्चित हुए हैं. *काशी का अस्सी* पर तो फिल्म भी बनी है. पर लंबे समय से आपने कोई संस्मरण भी नहीं लिखा.

संस्मरण प्रायः मैंने उन्हीं के बारे में लिखा है जिन्हें भीतर-बाहर बहुत अच्छी तरह जानता हूं. जिन्हें बाहर से ही जानता हूं, अंदर से नहीं जान पाता, उनके बारे में नहीं लिखता. बाबा नागार्जुन पर लिखना चाहता था. वे आते तो हमारे घर ठहरते थे. हमारे लिए ही आते थे. उनके बारे में लिखने की सोची थी मैंने लेकिन कुछ ऐसे विरोधाभास मुझे दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें मैं समझना चाहता था, नहीं समझ सका. इसलिए लिखने से रह गए बाबा.

● अब तो आपका बनारस, उसका सांचा-ढांचा भी बहुत बदल रहा है.

अब तो बनारस भी बनारस में नहीं दिखता. जिन गलियों के लिए जाना जाता था, बाबा विश्वनाथ उन गलियों के बीच थे पर अब वे भी कॉरिडोर में चले गए. बनारस अब बचा कहां है? बनारस के लिए या- या नहीं किया लोगों ने पर अब वह बनारस रहा ही नहीं. ध्वंसावशेष के रूप में कुछ लोग आज भी रह गए हैं तो रह गए हैं, जैसे भांग-ठंडई वाले, मस्ती वाले.

● उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, क्या सोचते हैं?

चुनाव के बारे में मैं क्या बताऊं? सारी चीजें तो बिकती चली जा रही हैं. आदमी ही बचा हुआ है. अभी खुद को बचाए हुए चल रहा है. अब तो सीधे अस्तित्व पर ही संकट है भाई.

–आलोक पराड़कर

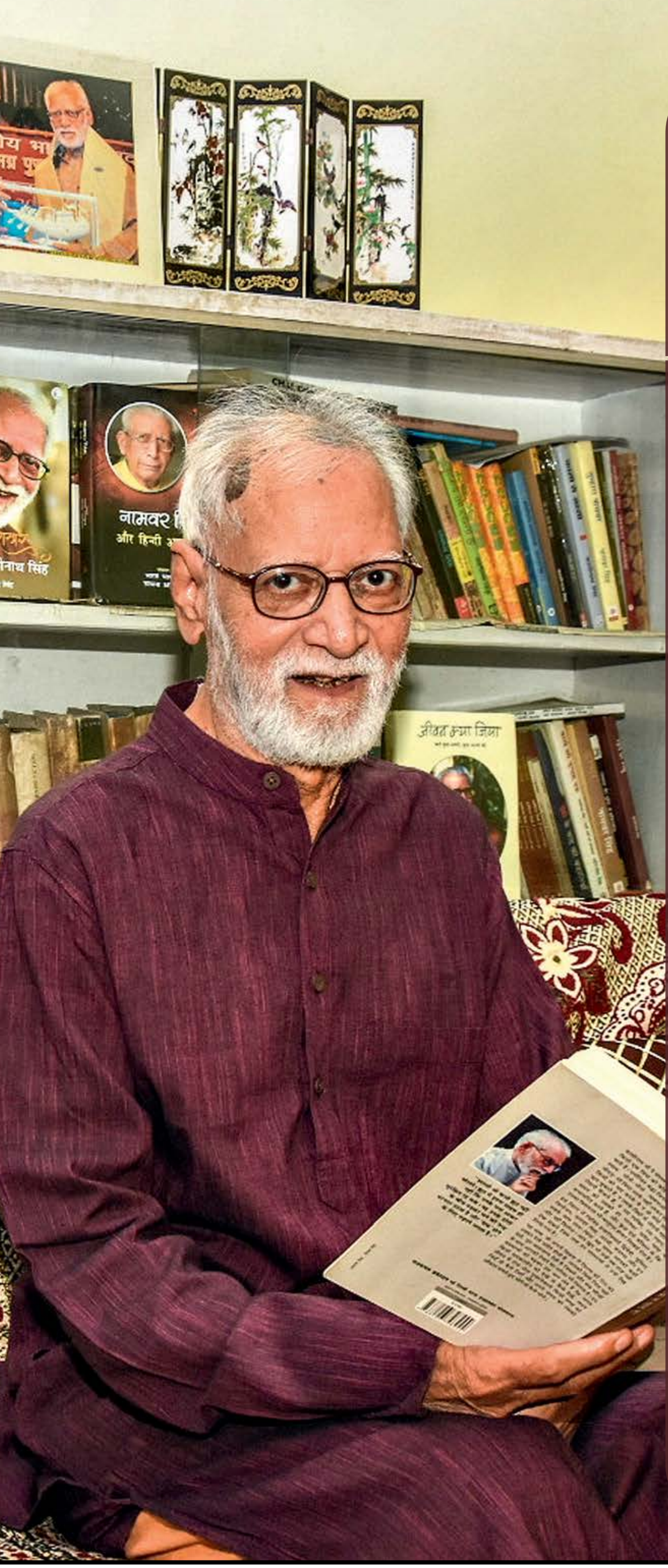

फोटोः समीर नंदन गुप्ता

देश का नं. 1
हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

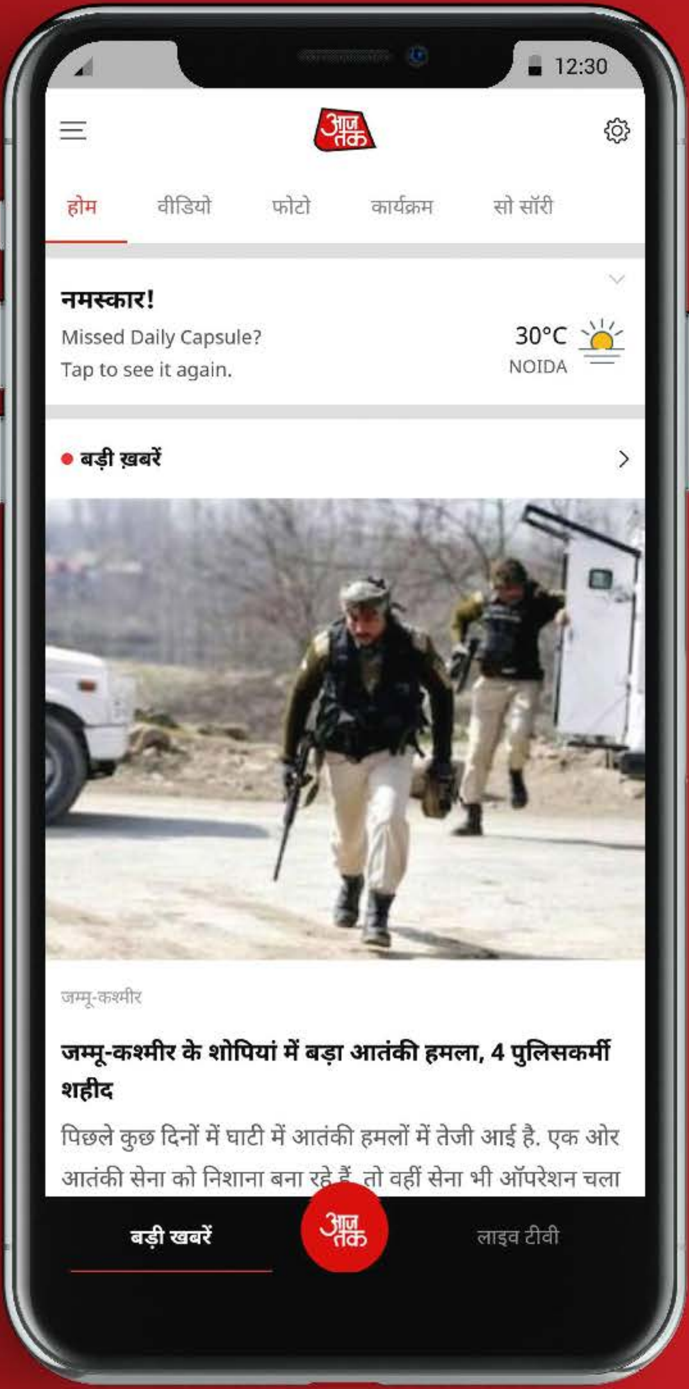

12:30

होम
वीडियो
फोटो
कार्यक्रम
सो सॉरी

नमस्कार!
Missed Daily Capsule?
Tap to see it again.
30°C
NOIDA

बड़ी ख़बरें

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बड़ा आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मी शहीद

पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकी हमलों में तेजी आई है. एक ओर आतंकी सेना को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सेना भी ऑपरेशन चला

बड़ी खबरें
लाइव टीवी

IndiaContent

SEARCH FOR
EDITORIAL IMAGES
ENDS HERE